हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

01/03/2016/1100/MS/AG/2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।
अध्यक्षः बोलिए, आपने क्या बोलना है?
श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, हम जो विधायक न्यू मैट्रोपोल में रहते हैं वहां पर पार्किंग के लिए बहुत समस्या है। जब से माननीय उच्च न्यायालय की नोटिफिकेशन हुई है तब से हम सब विधायक लोग सफर कर रहे हैं। उस दिन बात हुई थी कि इसमें कोई--,
अध्यक्षः यह विषय एजैंडे में लगा हुआ है।
श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, नियम 67 के तहत हमने रेजोल्यूशन दिया हुआ है।
अध्यक्षः यह एजैंडे में है।
श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, हमने नियम 67 के तहत काम रोका प्रस्ताव आपको कल से ही दिया हुआ है। जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं सभी ने मिलकर दिया हुआ है।
अध्यक्षः वह मैटर एजैंडे में लगा हुआ है।
श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, वह एजैंडे में लगा हुआ है या नहीं लगा है इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। सफर तो सभी विधायकगण कर रहे हैं।
अध्यक्षः जो आपने मामला दिया हुआ है वह हमने सरकार को भेज दिया है We are also waiting for the reply.

श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, हमारी व्यथा तो सुन लीजिए।
अध्यक्षः अभी उसमें क्या डिस्कस करना है?
श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, हमारी बात सुन तो लीजिए। आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। आप हमें थोड़ा सुन तो लो।
अध्यक्षः आप अपनी बात कह लीजिए बाकी बाद के लिए रख दो।

01/03/2016/1100/MS/AG/2

श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात ही रख रहा हूं। वास्तव में समस्या बहुत विकट आ गई है यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो रहा है। आप सब लोग सीनियर विधायकगण, मंत्रीगण, सरकार और छः-छः बार के मुख्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। जब से यह सत्र चला हुआ है हम जैसे नये विधायक और कुछ सीनियर मैम्बर्ज जो यहां चुनकर आए हुए हैं, हम न्यू मैट्रोपोल से विधान सभा तक पैदल आ रहे हैं। यह सबसे बड़ा शर्मनाक विषय है। इससे बड़ी शर्मनाक परिस्थिति किसी भी विधान सभा के लिए नहीं हो सकती जोकि स्वतंत्र राज्य है। इस तरह की स्थिति किसी अन्य राज्य में नहीं है। मुझे लगता है कि मान्य सदन के लिए इससे बड़ा मुद्दा और कोई नहीं हो सकता कि विधायकों के अधिकारों का हनन तथाकथित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है। क्योंकि कल जितनी भी चर्चाएं हुई हैं चाहे वह एन्क्रोचमैंट की बात हो। कल सिर्फ हम चर्चा ही कर पाए और किसी निर्णय तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हर चीज के लिए हमें कोर्ट की तरफ देखना पड़ रहा है। माननीय भारद्वाज जी ने धर्मशाला में बिल्कुल सही कहा था। हम इनके साथ है। अब देखिए एक नोटिफिकेशन के द्वारा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे -according to till further orders, the following mandatory directions are issued that the Chief Secretary is directed to ensure that no vehicle attached to the Hon'ble Judges is unnecessarily stopped or challaned. यह क्या बात हो गई? अपनी मर्जी से वे सारी डायरैक्शन्ज दे रहे हैं। अपने लिए सबकुछ ठीक कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक परिस्थिति कोई नहीं हो सकती। इसमें सरकार आज-की-आज कोई आश्वासन दे नहीं तो हमें नहीं लगता कि हमें इस विधान सभा में बने रहना चाहिए और इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति हम लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती। इस तरह से इस विधायिका का जो एक मान-सम्मान है, उसको बहुत बड़ी ठेस लगी हुई है इसलिए सरकार कुछ करे। नहीं तो आज से हम यहां कार्य नहीं चलने देंगे।

01/03/2016/1100/MS/AG/3

मुख्य मंत्रीः जो माननीय सदस्य ने समस्या उठाई है यह सचमुच में गम्भीर है। मेरी पूरी हमदर्दी इनके साथ है और यह जो कुछ हुआ है यह उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। अब हमने समाधान निकाला है कि मैट्रोपोल के ऊपर जो रोड है उसमें यलो लाइन लगाएंगे जहां पर विधायक पार्किंग कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य श्री हंस राज जी ने उठाया है। यह सवाल केवल मैट्रोपोल विधायक सदन के पास विधायकों की गाड़ियां
खड़ी करने का नहीं है। इस विधान सभा ने कानून पास किया है और उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय की असेंट मिली और उसमें जो प्रोविजन्ज है उसको वायलेट करके उच्च न्यायालय की डायरैक्शन्ज और ऑर्डर आ रहे हैं और वे सुओ-मोटो हो रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

01.03.2016/1105/**जेएस/एजी**/1

श्री सुरेश भारद्वाजः---------**जारी**------

क्योंकि किसी ज्युडिशियरी की हाई कोर्ट की गाड़ी का चालान पुलिस वाले कर देते हैं और उसके ऊपर पूरे का पूरा सी.डब्ल्यू.पी. बन जाती है। मैटर सबज्युडिस हो जाता है। उस पर फैसला दे देते हैं। इस प्रकार की डायरैक्शन्ज, ये क्वश्चन उन्होंने ओपन रखा है। दो बार अडिशनल एडवोकेट जनरल ने यह मामला वहां पर उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर एग्री नहीं करते हैं। यह क्वश्चन ओपन रहेगा। यहां से लेकर सी.टी.ओ. तक सील्ड एरिया है। It is not a core area. कोर एरिया शिमला क्लब से सी.टी.ओ. तक है। सी.टी.ओ. तक सील्ड एरिया है। विधान सभा सचिवालय ने भी उसमें परमिट इश्यु किये हैं। उसमें स्टेट गवर्नमैंट के होम सेक्रेटरी की तरफ से भी परमिट इश्यु होते हैं, लेकिन वहां गाड़ी नहीं ले जा सकते हैँ, क्योंकि किसी जज की

गाड़ी का चालान हो गया। अब जज की गाड़ी के साथ अटैच्ड गाड़ी भी होगी उसके लिए डायरैक्शन दी जा रही है कि उसको रोका न जाए, पकड़ा न जाए। मतलब वे कानून से भी ऊपर हो गये,कांस्टिच्युशन से भी ऊपर हो गये। सत्य पर ज्युडियरी है, लैजिस्लेटर्ज़ है, एग्जैक्टिव है। वे कानून के अन्दर ही काम करेंगे, कान्स्टिच्युशन के अन्दर ही काम करेंगे। लेकिन यह दिखाने के लिए लैजिस्लेचर को डाऊनग्रेड करने के लिए इस प्रकार के ऑर्डर्ज़ किए जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फोर्सफुली हाई कोर्ट में उस बात के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। धर्मशाला में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत हुई तो हम इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ऑल पार्टी मीटिंग में एक बार आपके सामने चर्चा हुई थी। हम इस बात को हाऊस में उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन हाऊस में इसलिए उठाना पड़ा कि आजकल हम गाड़ी कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। विधायकों को गाड़ी रखने के लिए कहीं पर जगह नहीं है। वहां पर कोई पार्किंग नहीं है। इसलिए या तो मकान इनको यहां पर दे दिए जाते। तब ये उन मकानों को मैट्रोपोल से छोड़ देंगे। मैट्रोपोल छोड़ना या नहीं छोड़ना, लेकिन वह तो कानून

01.03.2016/1105/जेएस/एजी/2

लैजिस्लेचर बनाती है। सरकार एक्शन लेती है। उस एक्ट को या तो हाई कोर्ट खत्म कर दे। पूरा कान्स्टिच्युशन अल्टर्ा वायरस है। तब तो हम मान सकते हैं कि High Court has the power to do that. लेकिन जब कान्स्टिच्युशनली वह एक्ट वेलिड है तो कान्सिटच्युशन के अन्दर यानि वेलिड एक्ट के अन्दर बिना मतलब के वह इसलिए कि जज की गाड़ी का चालान हो गया इसलिए वे सारे का सारा काम कर रहे हैं और इस प्रकार की डायरैक्शन्ज दे रहे हैं। यह टोलरेबल नहीं होगा। माननीय हंस राज जी ने ठीक कहा है कि यदि इस प्रकार का काम होगा तो कई मामले इन्ट्रप्रैट होते रहेंगे और

लैजिस्लेचर का कोई मतलब ही नहीं होगा। एग्जैक्टिव और लैजिस्लेचर का सारे का सारा काम हाई कोर्ट को सौंपा जाए और वही उसको देखे भी और काम भी करें। इस तरह से कुछ भी नहीं चलने वाला है। कान्स्टिच्युशन को वॉयलेट करके वे जो चाहे करते रहे। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय हम आप से रूलिंग चाहते हैं और सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि इस पर निर्णय ले करके कोई न कोई फैसला जरूर किया जाए।

Speaker: Just a minute. आप लोग एक मिनट के लिए बैठिये। ____(व्यवधान)____ प्लीज, आप लोग बैठ जाईये। मैं इस स्थिति पर कुछ बोलना चाह रहा हूं उसके बाद आप चर्चा करें। ____(व्यवधान)____ ठीक है, श्री संजय रतन जी कुछ बोलना चाहते हैं।

01.03.2016/1105/जेएस/एजी/3

श्री संजय रतन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। यह परमिट का मसला नहीं है। यह विधान पालिका को न्यायपालिका द्वारा चैलेंज किया गया है। विधान पालिका ने कानून बनाया। हमें परमिट मिलते हैं। हमें विधान पालिका ने कानून बना करके सचिव, विधान सभा को विधायकों को परमिट देने के लिए अथोराईज किया । लेकिन जब एक जज की गाड़ी का चालान होता है उस गाड़ी में कोई नहीं बैठा था। खाली गाड़ी का अगर चालान होता है उसके लिए सुओमोटो डिसिजन कर देते हैं और सभी के परमिट सस्पैंड कर देते हैं और अपने लिये चंद लाईने लिख देते हैं कि "Chief Secretary is directed to ensure that no vehicle attached to the Hon'ble Judges is unnecessarily stopped and challaned. यह बहुत शर्म की बात है। वह कानून काट रहे हैं। विधान पालिका ने कानून बनाया। कार्यपालिका उसको इम्पलिमैंट करती है और न्यायपालिका उसकी रखवाली करती है। यहां न्यायपालिका हमें डायरैक्शन दे रही है कि हम कहां जाएं और कहां नहीं जाएं? यह बड़ी शर्म की बात है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। इस हिसाब से डेमोक्रेसी हिन्दुस्तान में खत्म

हो जाएगी। हमारे बनाए हुए कानून को हाई कोर्ट निरस्त नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट उस कानून में यह देख सकता है कि उस कानून की पालना ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। हमें जो परमिट मिलते हैं वे सचिव, विधान सभा द्वारा दिए जाते हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

01.03.2016/1110/SS-AS/1

श्री संजय रतन क्रमागतः

विधान सभा ने जो कानून बनाया है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इस सील्ड रोड पर जा सकते हैं और इस सील्ड रोड पर नहीं जा सकते हैं। मैं दुख के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि अधिकारियों ने जजमैंट को पूरा पढ़ा नहीं है। 21 तारीख को जजमैंट आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी गाड़ी का भी चालान हुआ। आपकी गाड़ी को भी रोका गया। सी0पी0एस0 की गाड़ी को भी रोका गया। मंत्रियों की गाड़ी को रोका गया। विधायकों की गाड़ी को रोका गया, सिर्फ अखबार में पढ़कर कि हाई कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी है। किसी भी अधिकारी ने इस जजमैंट को पढ़ने की कोशिश नहीं की। हाई कोर्ट ने पहली जजमैंट 21 तारीख को दी। दूसरी जजमैंट 26 तारीख को दी और तीसरी जजमैंट 27 तारीख को दी। 27 तारीख की जजमैंट में उन्होंने खुद कहा कि जो वैलिड परमिट इश्यु हुए हैं वे लोग सील्ड रोड पर जा सकते हैं। अब हमारे अधिकारी इस चीज़ को भी इम्प्लीमैंट नहीं करते। क्या हर चीज़ के लिए हमें हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी? अब हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में जायेंगे। हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि क्या हम रैस्ट्रिक्टिड/सील्ड रोड पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। क्या हम पार्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाई कोर्ट में जब पार्किंग का इश्यु आया। मैट्रोपोल में जो विधायक रहते हैं उनका जब इश्यु आया तो उसमें उन्होंने उसको ओपन रखा है। खुला रखा है। हाई कोर्ट ने कोई रैस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि वहां पर पार्किंग नहीं हो सकती। तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारियों को कहा जाए कि जो कानून हमने विधान सभा में बनाया है उसके तहत हमारी गाड़ियां जाने दी जाएं और हमें वहां पर पार्किंग मुहैया करवाई जाए। कल रात को मैं छोटा शिमला के लिए गया। सभी

विधायकों की गाड़ियां कार्ट रोड पर लगी हुई थीं। बड़े दुख की बात है। हाई कोर्ट के जजिज़ की गाड़ियां चारों तरफ घूम सकती हैं और ऑनरेबल विधायक जोकि सिर्फ सैशन अटैंड करने के लिए यहां पर आते हैं उनके चालान होते हैं। हम 24 घंटे शिमला में नहीं रहते, कभी-कभार मीटिंग या सैशन अटैंड करने के लिए आते हैं और हमारी गाड़ियों के अब चालान होंगे। किशोरी लाल जी यहां बैठे हैं। एक पुलिस कॉंस्टेबल ने शिमला क्लब के पास इनकी गाड़ी का स्टिकर स्क्रैच कर दिया, जिसके ऊपर विधायक (एम0एल0ए0) लिखा हुआ था। अगर

01.03.2016/1110/SS-AS/2

इस तरीके से विधायकों के साथ होगा तो मैं नहीं समझता कि डैमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। डैमोक्रेसी के ऊपर रोक लगाने की कोशिश न्यायपालिका द्वारा की जा रही है। अगर हम इसके ऊपर और ज्यादा बोलना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जायेगा। हाई कोर्ट में क्या हो रहा है और जजिज़ क्या कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर विधान सभा के अंदर मंत्रणा/चर्चा होगी तो बहुत ज्यादा हो जायेगा। मैं नहीं चाहता कि हम उसके ऊपर और ज्यादा चर्चा करें। हम यह चाहते हैं कि हमारी विधायिका ने जो कानून बनाया है जिसके तहत हमें अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारों की रक्षा भी विधायिका ही करेगी, धन्यवाद।

01.03.2016/1110/SS-AS/3

अध्यक्षः आपने जो यहां पर कुछ बातें कहीं हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ सहमत हूं। सारी बात यह है कि जो हाई कोर्ट की जजमैंट है, उसमें हमने ऐक्ट बनाया है जिसके तहत हम परमिट देते हैं। उसको निरस्त नहीं किया हुआ है। इसमें होम डिपार्टमैंट ने इस चीज़ को मैस किया हुआ है पुलिस ने मिस इंटरप्रैट किया। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि परमिटधारक नहीं जा सकता। The only thing is that वहां पर पार्किंग नहीं हो सकती। मुझे पता लगा, वैसे मुझे लिखित रूप में नहीं आया कि गवर्नमैंट ने इसके लिए येलो लाइन लगाने के लिए लिखा है और वह कारपोरेशन करेगी। --(व्यवधान)--एक मिनट ठहरिये। आप सुन तो लीजिए। मैं समस्या का समाधान ही कर रहा हूं। I am not different then you मैं आपकी बात कर रहा हूं। इसमें सिर्फ यह है कि जो हाई कोर्ट की

जजमैंट है वो extra jurisdictional है। उसमें कोई भी ऐसा बंधन नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते। जो परमिट आपको मिले हैं, वे वैलिड हैं, वे लॉ के मुताबिक ही हैं। रूल्ज़ में हैं और जब तक रूल्ज़ निरस्त न हो जाएं तब तक हाई कोर्ट की जजमैंट उस पर लागू नहीं होगी। वरबल ऑर्डर्ज़ नहीं होंगे। यह बिल्कुल जस्टिफाइड बात है कि अगर एम0एल0ए0 आते हैं और वहां पर पार्किंग के लिए जगह नहीं है, उन्होंने अपना सामान उतारना है और उन्होंने अपने फ्लैट पर जाना है तो कहां से जायेंगे। कैसे गाड़ी पार्क करेंगे। कई बार ड्राईवर होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं यह कहता हूं कि होम डिपार्टमैंट ने आज दो महीने से कोई भी ऐक्शन नहीं लिया है। Home Department is responsible for this. पिछली बार मेरे कमरे में कुछ एम0एल0ऐज़ आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो हम सैशन अटैंड नहीं करेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

01.03.2016/1115/केएस/एएस/1

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारा विषय हंस राज जी, सुरेश भारद्वाज जी और संजय रतन जी ने इस माननीय सदन में रखा है और इतने वर्ष हमें भी शिमला में रहते हुए हो गए लेकिन यह पहला मौका है कि विधायकों के ऊपर आपकी रहनुमाई में कितना कुठाराघात हो रहा है। आप ही नहीं बचें तो हम कहां बचेंगें?

मुख्य मंत्रीः रवि जी, यह कहिए कि आपके होते हुए हो रहा है। यह अध्यक्ष जी की रहनुमाई में नहीं हो रहा है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे हाई कोर्ट ने पहले कोई डायरैक्शन दी थी और जिस ढंग से आपकी गाड़ी का चालान किया गया, यह उसी समय ऐक्शन होना चाहिए था कि केवल मात्र आपके ऊपर ही नहीं, पूरी विधानसभा और लैजिस्लेशन के ऊपर कुठाराघात किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, विधायिका के ऊपर इतना कुठाराघात करना लोकतंत्र में शोभा नहीं देता और लोकतंत्र को बचाने की प्रक्रिया आपको शुरू करनी पड़ेगी। आपके जजिज़ क्या-क्या

रुलिंग दे रहे हैं? क्या ये हमसे ऊपर हो गए? क्या लिखा है- "According to till further orders the following mandatory directions are issued. The Chief Secretary is directed to ensure that no vehicle attached to the Hon'ble Judges is unnecessary stopped or challaned". वे कौन होते हैं ऐसा रूल बनाने वाले? क्या इसे हमारी विधान सभा ने कहीं पास किया है? हम विधायकों के लिए तो उन्होंने रुलिंग लगा दी है कि विधायक अगर गाड़ी में होंगे तो सी.टी.ओ. तक गाड़ी जाएगी वरन् अगर उनमें हमारे परिवार का कोई मैम्बर होगा, हम नहीं होंगें तो वहां पर चालान किया जा रहा है। सी.टी.ओ. तक गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं। आपकी गाड़ी गई तो उसका

01.03.2016/1115/केएस/एएस/2

भी चालान हो गया इसलिए हमारा सीधा सा मतलब है, केवल मात्र गाड़ी खड़ी करने का विषय नहीं है, यह प्रोटैक्शन देने का विषय है। आप आज यह आदेश करें, माननीय विधान सभा आज आदेश करें, सरकार इसको इम्पलीमैंट करें और तुरंत आज से ही इम्पलीमैंट होना चाहिए, बात तभी बनेगी वरन् बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विधायिका है, यह अपना एक स्थान रखती है, माननीय संस्था है, कंस्टीच्यूशनल बॉडी है और विधायिका के काम में कोई हनन हो या विधायकों के साथ यदि कोई अप्रिय घटना हो, उनको रोका जाए और यहां तक कि जहां वे रहते हैं, वहां वे अपनी गाड़ियां पार्क नहीं कर सकते, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। और जितने आप उत्सुक है कि विधायकों के जो राईट्स हैं, प्रिविलेजिज़ हैं, उनका जो मान और सम्मान है, वह कायम रहे, इस बात से मैं भी सहमत हूं और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार आपके मान और सम्मान और आपको जो तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं, उनको दूर करने

के लिए तुरन्त कार्रवाई करेगी।

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, पहले भी ऐसा ही कहा था कि हमारी तकलीफें दूर होंगी, यह होगा, वह होगा । मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने जितने भी माननीय विधायक वहां पर रहते हैं और अन्य विधायक भी जो हमसे मिलने वहां आते हैं, उन सबकी गाड़ियां आज मैट्रोपोल में जहां पहले लगती थीं, वहीं लगेगी और जिस ने उठानी होगी, उठा लें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

01.03.2016/1115/केएस/एएस/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि मैट्रोपोल में जहां आपकी गाड़ियां लगती थी, वहां पर सड़क में यलो लाईट लगाई जा रही है ।

श्री हंस राजः नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह आज ही लगाई जाए और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों को डायरैक्शन्ज़ दे दी जाए क्योंकि कल भी हमारे साथ एक कॉंस्टेबल ने बद्तमिज़ी की है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी बीमार है इनको चलने में दिक्कत हो रही है लेकिन इनको वहां से मेन रोड़ तक पैदल आना पड़ा । जिन भी माननीय विधायक जो वहां पर रह रहे हैं, जिनको वहां पर अलॉटमैंट हुई हैं, उनकी सभी की गाड़ियां आज वहां पर खड़ी होंगी । देखते हैं कौन उनका चालान करता है या उनकी गाड़ियों को उठाता है। हम सभी विधायक उनके साथ हैं और इनके साथ चलेंगें। देखेंगें कि क्या होता है। ऐसे यह बात बनने वाली नहीं है।

श्री संजय रतन जी श्रीमती अ0व0की बारी में----

1.3.2016/1120/av/dc/1

श्री संजय रतन : वहां पर हमारी गाड़ी भी रोक दी जाती है। मेरी गाड़ी में माननीय विधायक श्री अजय महाजन जी ने लिफ्ट ली मगर मेरी गाड़ी भी रोक दी। मैंने कहा कि अजय महाजन जी बैठे हैं मैं इनको छोड़ने जा रहा हूं तब जाकर मेरी गाड़ी जाने दी। हमारी गाड़ी भी आपस में जाने दे। इस तरह से तो हमारे रिलेशन खराब हो जायेंगे। जो वहां रह रहे हैं, हमारे आपस में सम्बंध खराब हो जायेंगे। हमारी गाड़ी भी जानी चाहिए।

मुख्य मंत्री : यह यलो लाइन आज ही लगेगी और आपकी गाड़ियां वहां खड़ी होगी। There will be no compromise with the prestige, honour and privilege of the MLAs. I can guarantee that . आपकी गाड़ी जाने दी जायेगी।

श्री संजय रतन : ए.जी. ऑफिस से आगे सी.टी.ओ. तक आने-जाने के लिए हमें विधान सभा से जो परमिट मिले हैं उसको भी इम्पलीमैंट किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष : आपको जो वैलिड परमिट मिले हुए हैं वह परमिट निरस्त नहीं होंगे। Valid permit is enough.

1.3.2016/1120/av/dc/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर अपने साथ हुई बद्तमीजी के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा परिवार कुछ सामान लेने के लिए मार्किट गया था। उन्होंने कहा कि गाड़ी तब आयेगी जब आप गाड़ी में बैठकर सी.टी.ओ. आयेंगे। मैं उनको लेने के लिए सी.टी.ओ. के पास पहुंचा। गाड़ी मोड़कर लगाई ही थी कि उतने को एक महिला पुलिस कर्मी जिसका नाम पूजा है। मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरी तरह से बद्तमीजी की है। अभी मैं गाड़ी लेकर पहुंचा ही था और जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी उसने शीशे पर टक-टक करके बोला। मेरा परिवार सी.टी.ओ. में लगे बैरिकेड के पास पहुंच गया था और मैं खिड़की खोलकर उनको गाड़ी में बैठा ही रहा था कि उसने एकदम से कहा कि अगर गाड़ी की परमिशन दी है तो यहां पर खड़ी

मत करो, नीचे खड़ी करो। मैंने कहा कि मैं कर रहा हूं और मेरा परिवार आ गया है। मेरी वाइफ और बेटी मेरे साथ थी और उसने उनके साथ भी बद्तमीजी की। उस लेडी ने यह कहा कि करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। मैंने उसको विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े।

उसके बाद मैंने एस.पी. को फोन किया। एस.पी. ने कहा कि मैं उसको वहां से अभी शिफ्ट कर रहा हूं। उसको शिफ्ट किया या नहीं किया मगर कोर्ट के आदेश पर जिस प्रकार से हमें हर जगह जलील होना पड़ रहा है इस बात को लेकर सचमुच हमें अफसोस है। ऐसे आदेश पुलिस अधिकारियों को भी जाने चाहिए कि हमें इस प्रकार से जलील मत कीजिए। हाई कोर्ट जो कर रहा है वह हम देख रहे हैं। हम ज्यादा नहीं बोल सकते, उसमें एक सीमा है और हम एक सीमा के अंदर बोल सकते हैं। मगर पुलिस अधिकारी/कर्मचारी हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे हम कोई डाकू या गुंडे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बातें ठीक नहीं है और इनको देखना चाहिए।

मुख्य मंत्री : जिस किसी भी पुलिस ऑफिसर या कॉंस्टेबल ने इस प्रकार की बद्तमीजी की है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी और जिसने बैजनाथ के माननीय विधायक की कार में लगे स्टीकर को उखाड़ा है he will be suspended immediately.

1.3.2016/1120/av/dc/3

प्रश्न काल आरम्भ

स्थगित प्रश्न संख्या : 2298

मुख्य मंत्री : इतनी बड़ी सूचना मांगी है कि किस विभाग में कौन-कौन और कितने कर्मचारी हैं जो उसी इलाके के हैं और this is infructuous exercise. फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री टीसी द्वारा जारी

01.03.2016/1125/TCV/DC/1

प्रश्न संख्याः ---- 2298 क्रमागत

श्री विक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लगाते हुए मुझे तीन साल हो गए है। सरकार का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जब धर्मशाला में विधान सभा का सत्र हुआ था, तब भी मैंने यह प्रश्न किया था। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि आप मुझे लिखकर दो। मैंने लिखकर भी दिया। परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि कौन-कौन से कर्मचारी कहां-कहां पर अप्वांईटिड है। अब सरकार का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है और इन कर्मचारियों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। लेकिन अब तो इनका स्थानान्तरण कर दो। माननीय मुख्य मंत्री के कहने पर मैंने लिखकर दिया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई । अभी भी लिखा जा रहा है कि सूचनाएं एकत्रित की जा रही है। क्या माननीय मुख्य मंत्री बताएंगे कि जो मैंने आपको लिखकर दिया था, उसका क्या हुआ?

मुख्य मंत्रीः मुझे आपका कोई पत्र नहीं मिला। मगर आपने सारे हिमाचल प्रदेश की सूचना मांगी है। आप अपने काम की बात करिए। यदि आपके हलके में ऐसी कोई बात है, आप मुझे बताईये। मैं आपको सूचना दे दूंगा। We will see, we are doing our best to gather information but information involves so many people and इन्होंने लार्ज सूचना मांगी है, इस कारण इसको इक्ट्ठे करने में समय लग रहा है।

Speaker: You write to Hon'ble Chief Minister for answer.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा कि पूरे प्रदेश की सूचना मांगी है। लेकिन सरकार द्वारा एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई हुई है और अभी कुछ समय पहले ही वह ट्रांसफर पॉलिसी बनी है। उसमें डायरेक्शन्ज दी गई है कि इस-इस

स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घर के नज़दीक या बीट में नहीं लग सकते हैं। इसलिए इन्होंने सूचना तो यही मांगी है कि कैसे इतने अधिकारी/कर्मचारी अपने घरों के नज़दीक या बीट में लगे हैं? माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह सूची कोई लम्बी तो है ही नहीं। मुझे लगता है कि यह सूचना तो श्री ठाकुर सिंह भरमौरी

01.03.2016/1125/TCV/DC/2

जी के पास भी उपलब्ध होगी कि कौन-कौन से अधिकारी /कर्मचारी लगाए हैं? ये ही बता दें तो ठीक हैं।

मुख्य मंत्रीः यह जो सूचना है यह इतनी व्यापक है। It involves the entire state and information has to be gathered from 18 departments. जब तक पूरी सूचना प्राप्त नहीं होगी मैं सभापटल पर नहीं रख सकता।

अध्यक्षः अगला प्रश्न । काफी हो गया है, next question. Please sit down, it is not that important question. Please don't not insist for this question. । ये कह रहे हैं कि आपको सूचना दे देंगे। आप इनसे मिलिए और यदि किसी की ट्रांसफर करवानी है तो ट्रांसफर करवा देंगे। Please. Not at all.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो बात है वह इनके अपने चुनाव क्षेत्र की है। जो लिखकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने मांगा था, इन्होंने वह डिटेल भी दे दी है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसी सत्र में इन्श्योर करेंगे कि इनके विधान सभा क्षेत्र भटियात में विभिन्न विभागों में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने उन्हीं सर्कल में लगे हैं जहां वह नहीं लग सकते हैं?

मुख्य मंत्रीः ऐसा है जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, वह इनके अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसमें सारे प्रदेश की सूचना मांगी है। Yes it is there. देखिए प्रश्न क्या है? इन्होंने लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो अपनी

सेवाएं सरकार की स्थानान्तरण नीति के विपरीत अपने घर, अपने होम ब्लॉक, ज्वाईंनिंग ब्लॉक में प्रदान कर रहे हैं, ब्यौरा हर विभाग का जिलावार दिया जाये? (ख) सरकार कब तक इन अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार करने का विचार रखती है? This information is required for the entire state and for all the departments.

श्री आर0के0एस0 द्वारा प्रश्न----- जारी

01.03.2016/1130/RKS/AG/1

प्रश्न संख्या 2298.....जारी...
मुख्य मंत्री क्रमागत...
अगर आप अपने चुनाव क्षेत्र का उत्तर पूछना चाहते हैं तो हम दे देंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः **सर, मैं अपना प्रश्न अमैंड करता हूं।.....**

Chief Minister: Let him amend his question. जिस क्रम में आएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे।

Speaker: What is there in this question? (Interruption) I will not allow you. ये पढ़ के बता दे। You should be satisfied now. You deal with this separately with the Hon'ble Chief Minister. Don't waste the time of this House?

मुख्य मंत्रीः यह नया नोटिस हो गया। It will take time also.

Speaker: Next Question श्री गोविन्द सिंह ठाकुर.

01.03.2016/1130/RKS/AG/2

प्रश्न संख्यां 2484

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मैंने मांगी है उस सूचना में एक फाऊंडेशन ने जानकारी दी है कि दिनांक 27.10.2015 को अंतरंग सभा, ढालपूर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने फाऊंडेशन किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा की अंतरंग सभा, ढालपूर में कौन सी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इसका फाउंडेशन देव सदन और पी.डब्ल्यु.डी रेस्ट हाऊस के मध्य में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सन् 2011 में दशहरा उत्सव के समय माननीय पूर्व मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने उसी स्थान पर अटल दशहरा सदन बनाने के लिए शिलान्यास किया था। क्या वह, वही स्थान है? अगर वह, वही स्थान है तो श्रद्धेय अटल जी जिनको हिमाचल प्रदेश, देश और दुनिया

सबसे बराबर प्रेम मिलता रहा और हिमाचल को उनका विशेष श्रेय मिलता रहा है। अगर इसी स्थान पर है तो क्या ऐसी परंपरा को बनाए रखना क्या ठीक बात है? क्या उस भूमि

का उपयोग किया जा रहा है? यदि यह फाऊंडेशन वहीं पर है तो यह परंपरा ठीक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया मुझे जवाब दें।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है वह बिल्कुल जायज है। मैंने आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है। कौन-कौन से प्रोजैक्ट हैं, किस तारीख को उसका उद्घाटन किया है और आज उसकी स्थिति क्या है। सभी प्रोजैक्टस के ऊपर काम हो रहा है, पैसा लग रहा है, कुछ प्रोजैक्टस तैयार हो गए हैं और कुछ अभी तैयार होने को हैं। कोई भी ऐसा प्रोजैक्ट नहीं है जो फंडिड नहीं है। आपने पहले प्रश्न अपनी कंस्टीच्यूअंशी के बारे में पूछा था परन्तु अब आप कुल्लू शहर के बारे में पूछ

रहे हैं। ठीक है, वहां पर पहले पी.डब्ल्यू.डी का रेस्ट हाऊस था, वहां पर शिलान्यास रखा था। वहां कुछ

01.03.2016/1130/RKS/AG/3

थियेटर, कमरे इत्यादि बनने थे। कुल्लू की जो वास्तविक आवश्यकताएं थीं उनको ध्यान में रखते हुए उस नक्से को मोडिफाई किया गया है। इसी वजह से उसको बदला है।

अध्यक्षः गोविन्द जी, आप क्या कहेंगे?

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुल्लू जिला की जानकारी मांगी है। अगर यह अंतरंग सभागार उसी स्थान में है तो उस समय के मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, जिनकी शिलान्यास पट्टिका वहां पर लगी हुई थी, उस पट्टिका का क्या हुआ? इसके अलावा अटल दशहरा सदन के नाम पर जो फाऊंडेशन हुआ था, इसके लिए उस समय भी लगभग 10 करोड़ का प्राक्कलन था। जो आजकल आप चाह रहें हैं कि ये चीजें इसमें होनी चाहिए, वे भी इसमें उस समय मौजूद थी। परम श्रद्धेय अटल जी का नाम इससे हटाना एक गलत परंपरा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसका नाम फिर से श्रद्धेय अटल जी के नाम पर रखेगी।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री।

मुख्य मंत्रीः अटल जी पूजनीय है और वे मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं।

श्री एस. एल.एस. द्वारा जारी....

01.03.2016/1135/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 2484.. जारी

माननीय मुख्य मंत्री ....जारी

जो यह आपकी सोच है, यह बिल्कुल गलत है।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, क्या उसको अटल जी के नाम से ही रखेंगे?

अध्यक्ष : यह आपका मूल प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया गया है। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : मैंने यही कहा कि वह अटल जी के नाम से ही बना है और अटल जी के नाम से ही उसका नाम होगा। हमने वह हटाया नहीं है। हम कोई अहसान फरामोश नहीं हैं। अटल जी हमारे देश के प्रधान मंत्री थे। मुझे खुशी है और मैं उनको अपने निकटतम मित्रों में से एक मानता हूं।

01.03.2016/1135/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या : 2637

Speaker: This question is authorized to Shri Mahender Singh.

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने 'क' भाग में उत्तर में कहा है कि प्रदेश में कुल 18,28,219 राशन कार्ड धारक हैं। 2013-14 में जो राशन कार्ड धारक थे, आपने उनकी संख्या 17.15 लाख बताई थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 2523 में आपने राशन कार्ड होल्डर की संख्या 18,24,077 बताई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो एक निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर डिजिटल राशन कार्ड बनाए जाएंगे; इनके बारे में आपने अपने उत्तर में कहा है कि मार्च में सारे-के-सारे डिजिटल राशन कार्ड बन जाएंगे। आज प्रथम् मार्च है। पहले तो आप यह बताएं कि मार्च के टारगेट के अनुसार आज तक कितने राशन कार्ड

बने हैं, राशन कार्ड होल्डर कितने हैं और उनमें कितने उपभोक्ता शामिल किए गए हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं, आपने कहा कि इसके लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है। आपने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी इसमें ज़िक्र किया है कि आधार कार्ड के बिना भी राशन कार्ड बन सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग इस प्रदेश के अंदर हैं, जब आधार कार्ड बनाते हैं तो उनके फिंगर प्रिंट्स उस मशीन में नहीं आते हैं। जिनके फिंगर प्रिंट्स उसमें नहीं आते, उनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। जिनके आधार कार्ड में फिंगर प्रिंट्स नहीं आते, उनको आप राशन किस प्रकार से सप्लाई करेंगे? साथ में, जो मार्च महीने का राशन है वह आप पुराने राशन कार्ड के आधार पर देंगे या जो नए कार्ड बने हैं, उनके आधार पर देंगे?

01.03.2016/1135/SLS-AG-3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महेन्द्र सिंह जी ने बुजुर्गों के आधार कार्ड के बारे में पूछा है। अगर उनका आधार कार्ड नहीं होगा, यह नहीं है कि उसके कारण उनका डिजिटल कार्ड नहीं बनेगा। उसके लिए प्रमाण हम बैंक या कहीं और किसी रिकॉर्ड से ले लेंगे। मैंने यह डायरैक्शन दे दी है। दूसरी बात आपने कही कि क्या मार्च से राशन पुराने कार्ड पर देंगे। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया बार-बार हमसे राशन सप्लाई बंद करने की बात कह रही है। हमने इसे 8 मार्च तक एक्सटैंड किया है। अभी ब्रिफिंग के समय मुझे सचिव महोदय ने बताया कि विडियो कॉफ्रैंसिंग की गई है और 80-85% तक काम पूरा भी हो गया है।

जारी ..गर्ग जी द्वारा

01/03/2016/1140/RG/AS/1

प्रश्न सं. 2637 क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री-----क्रमागत

बाकी जो 15% काम रहा हुआ है वह दस दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई, तो उसमें 5-10 दिन की और ऐक्सटेंशन देने पर भी विभाग विचार कर सकता है। राशन में अभी कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मार्च के बाद उसमें दिक्कत आ सकती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि मार्च के अन्दर-अन्दर इसका सारा कार्य खत्म हो जाए और जहां आधार कार्ड नहीं भी होगा, तो वहां भी डिजिटल कार्ड बनाने का किसी और तथ्य के साथ करेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तृत जवाब दे दिया है, लेकिन यहां जो बात उठाई है और वैसे माननीय मंत्री जी मान भी गए हैं कि यदि अप्रैल महीने में राशन काड्र्स नहीं बने, तो दिक्कत आ सकती है। एक बात जो माननीय मंत्री जी ने कही कि पहले आधार काड्र्स पर डिजिटल राशन काड्र्स बनाने के आदेश किए थे, लेकिन अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले ये आदेश विदड्रॉ कर लिए और इनके यहां से सारी पंचायतों में और निचले स्तर पर ऐसे आदेश गए हैं कि अब आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है जैसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किए थे, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ऐसी कंडीशन प्रदेश में पहले क्यों लगाई गई कि आधार कार्ड इसके लिए अनिवार्य है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी एक सप्ताह पहले ही आधार कार्ड वाली कंडीशन वापस ले ली और इन्होंने यह कहा कि किसी भी तरह का कोई भी परिचय-पत्र होगा, तो उसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अभी तक जिन पंचायतों में डिजिटल राशन काड्र्ज बनाने की प्रक्रिया जैसा इन्होंने कहा कि 80% पूरी हो गई है। जैसे यदि किसी परिवार के पांच सदस्य हैं, तीन का आधार कार्ड था और दो सदस्यों के पास आधार कार्ड नहीं था, वे इसमें शामिल नहीं किए गए, तो उन सदस्यों को आप कैसे शामिल करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, तीसरा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि मार्च महीने का राशन तो हम दे देंगे, लेकिन अप्रैल महीने में दिक्कत आ सकती है। पहले आपने इसके लिए 29 फरवरी की तारीख दी थी,

लेकिन अब आपने उसको बढ़ाकर मार्च महीना कर दिया है, तो मैं

01/03/2016/1140/RG/AS/2

यह चाहूंगा कि इसकी आप ऑऊटसोर्सिंग भी कर सकते हैं। अगर पंचायतों में इतना काम करने की क्षमता नहीं है, तो इसको ऑऊटसोर्सिंग करके कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि 31 मार्च तक ये सारे-के-सारे डिजिटल राशन काड्र्ज पूरे प्रदेश में बनकर तैयार हो जाएं और सभी उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने का राशन समय पर मिले?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि श्री रविन्द्र सिंह जी ने कहा कि मैंने यह कहा कि जब यह आधार कार्ड की समस्या आने लगी और सरकार के नोटिस में यह बात लाई गई, तुरन्त मैंने ये आदेश दिए कि आधार कार्ड को ही आधार रखा जाए, ऐसा नहीं है। वैसे आधार कार्ड के साथ हमारी कनैक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। अगर कहीं पर कोई छूट गया है, तो अपना दूसरा प्रूफ दें, उसके साथ हम उसको ऐड कर देंगे, लेकिन परिवार के मुखिया के नाम राशन कार्ड बनेगा। परिवार की मुखिया आजकल हमने महिला को ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य को छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर कोई ऐसा मामला होगा, तो आप मेरे ध्यान में लाएं, वैरीफाई करके we will completely do it. Nobody will be left. **अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि मार्च में ही यह काम हो जाए क्योंकि भारत सरकार की ओर से बार-बार वार्निंग दी जा रही है। इसलिए मैं माननीय सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर इसमें जरूरत पड़ी, तो इसको ऑऊटसोसिंग करने पर भी विचार किया जा सकता है। वैसे हम इस काम को ऑऊटसोर्सिंग के बिना ही कम्पलीट कर देंगे**। इसमें हमारी नीयत बिल्कुल ऐसी है कि लोगों को राशन मिले और डिजिटल इण्डिया तो माननीय मोदी जी का सबसे बड़ा सपना है। उसके लिए तो आपको सपोर्ट करना चाहिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से दो चीजों के बारे में जानकारी चाहता हूं। पहला तो जो इन्होंने कहा कि यदि मार्च तक डिजिटल

राशन काड्र्ज बन जाते हैं, तो ठीक है, नहीं तो उसके पश्चात दिक्कत आएगी या आ सकती है। इन्होंने इस बात की संभावना स्वयं ही व्यक्त की है। मेरा इसमें एक निवेदन है कि क्या ये इस बात की जानकारी देंगे कि इस डिजिटल राशन कार्ड बनाने के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए या उन्हें जागरूक करने के

01/03/2016/1140/RG/AS/3

लिए इन्होंने क्या माध्यम या तरीका अपनाया है? क्या लोगों को जानकारी है कि यदि मार्च तक डिजिटल राशन कार्ड नहीं बने, तो उस परिस्थिति में जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

01/03/2016/1145/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2637 क्रमागत---श्री जय राम ठाकुर जारी----------

तो क्या इस बात को लेकर आपने लोगों को अवगत करवाया? दूसरा, मेरा महिला के नाम पर राशन कार्ड बनाने का विरोध नहीं है। यह अच्छा है। हम भी डिजिटल इण्डिया के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं। हमें उसमें सहयोग ही करना है। मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि महिला कहीं चली गई है या शादी करने के बाद कहीं और बस गई है तो उस परिवार का राशन कार्ड कैसे बनेगा? अध्यक्ष जी, एक दिन सुबह-सुबह किसी पंचायत का एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि आप प्रधान को फोन करो। मैंने कहा कि फोन क्यों करना है? वह बोला कि प्रधान बोलता है कि आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने बताया कि मेरी बीबी कहीं और चली गई है इसलिए प्रधान कहता है कि आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता। अब ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि ऐसे केस प्रदेश में एक नहीं बल्कि सैंकड़ों होंगे। इसके अलावा, अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई है उस परिस्थिति में भी अभी तक पंचायत वालों को कोई जानकारी ही नहीं है कि करना क्या है। ये दो मुद्दे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में प्रकाश डालें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, दोनों मुद्दे काफी गम्भीर हैं। पहला जो मुद्दा है, जब National Food Security Act (NFSA) बना जिसे पार्लियामैंट ने पास किया। उसमें कण्डीशन है कि परिवार की महिला के नाम पर ही राशन कार्ड बनेगा और यदि किसी की दो पत्नियां हैं तो जो बड़ी वाली होगी उसके नाम पर राशन कार्ड बनेगा। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, NFSA की यह कण्डीशन थी और उसमें मेंडेटरी था कि Woman member has to be the head of the family. दूसरी बात, जो माननीय सदस्य ने पूछी कि क्या लोगों को सूचना दी गई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने वॉयस मैसेज से बल्कि मैंने बार-बार प्रैस कान्फ्रेंस करके, प्रैस रिलीज और प्रैस

01/03/2016/1145/MS/AS/2

एडवरटाइजमैंट देकर के, रेडियों से एडवरटाइजमैंट देकर के और थ्रू डिपो होल्डर्ज हमने उनको कहा है कि 29 फरवरी का टारगेट है। इस बारे में हर व्यक्ति को पता है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि मार्च में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो बाद में हम अपने साथियों से बातचीत करके उसका कोई-न-कोई हल निकालेंगे।

01/03/2016/1145/MS/AS/3

प्रश्न संख्याः 2638

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हमारे प्रदेश में पैसे आ रहे हैं, उसमें कुछ फण्ड ऐसे हैं जो स्कूल प्रबंधन समिति को दिए जा रहे हैं। जो यह समिति है यह विलेज स्तर पर एक गांव में बनाई जाती है। उसमें 22-22 लाख रुपये के काम उनको दिए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता

हूं कि 10 लाख रुपये से ज्यादा जितना भी पैसा किसी भी स्कूल बिल्डिंग के लिए आता है वह लोक निर्माण विभाग को दिया जाए। उससे काम में पारदर्शिता और गुणवत्ता आएगी। जो काम ये स्कूल प्रबंधन समितियां कर रही हैं इसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लेंटल डालने में लग जाते हैं। जो स्कूल के मास्टर हैं और कमेटी है वे खुद ही गड्ढे खोदने लग जाते हैं और खुद ही रोड़ी कूटने लग जाते हैं तथा अंत में लेंटल देने में भी लग जाते हैं। इसलिए जितने भी इस तरह से पैसे आ रहे हैं वे लोक निर्माण विभाग को देने चाहिए। जैसे मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलों के लिए पैसे आए हैं। अगर वे पैसे लोक निर्माण विभाग को दिए होते तो उसके काम में गुणवत्ता होती और जो कार्य हो रहा है यदि उसको लोक निर्माण विभाग का तकनीकी स्टाफ देखता तो सही होता। साथ-ही-साथ कुछ पैसे जो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में आ रहे हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

01.03.2016/1150/जेएस/डीसी/1
प्रश्न संख्याः 2638ः--------**जारी**---------

श्री बलवीर सिंह वर्माः-------**जारी**-----

वह अलग-अलग डिपार्टमैंट को दिए जा रहे हैं। मेरे चुनावक्षेत्र में कुछ पैसे एच.पी.एस.आई.डी.सी. को दिये गये, कुछ पैसे हाऊसिंग बोर्ड को दिए गए, कुछ टैलिकाम्युनिकेशन डिपार्टमैंट को दिए गए। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि जितने भी स्कूल भवनों के पैसे हैं वे सारे के सारे पैसे लोक निर्माण विभाग को दिए जाएं और लोक निर्माण विभाग में चुनावक्षेत्र वाईज दे करके हम भी उसकी निगरानी कर सकते हैं। उनको पूछ भी सकते हैं। उस काम की गुणवत्ता को भी चैक कर सकते हैं। अगर यह पैसे बहुत सारे अलग-अलग विभागों को दिए जाएंगे उससे यही पता नहीं चलता कि किससे क्या बात करें? इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बिल्कुल ठीक है। **भविष्य में इन मद्दों में जो पैसा आएगा वह पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा ही खर्चा जाएगा।**

01.03.2016/1150/जेएस/डीसी/2

प्रश्न संख्याः 2639

श्री बलदेव सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क-भाग के ज़वाब में आपने वर्ष 2012-13 में दो स्कीमों के लिए सबसिडी दी थी लेकिन उसके बाद वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में कोई भी पैसा मेरे क्षेत्र में ग्रीन हाऊस के लिए अलॉट नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहे कि इन तीन सालों में कोई भी योजना प्रस्ताव आपके पास नहीं आया? क्या जानबूझ कर यह धनराशि स्वीकृत नहीं की है?

दूसरे, ख-भाग के ज़वाब में आपने कहा कि जो सिंचाई की स्कीमें हैं और उसमें विभिन्न स्कीमों में आपने जो पैसा दिया है मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक यह कोई भी स्कीम नहीं चल रही है। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि क्या आप इसकी छानबीन करवाएंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ख-भाग में जो आपने पूछा उसमें वर्ष 2013-14 में तो पैसा दिया है। इसमें 55 स्कीमों पर पैसा दिया हुआ है। .....(व्यवधान).....ख-भाग में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत फव्वारा एवं टपक सिंचाई हेतु 102 योजनाएं बनाई गई, जिन पर 8,14,473/-रूपये की धनराशि उपदान के रूप में दी गई। ग-भाग में गत तीन वर्षों में शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कितने ग्रीन हाऊस का निर्माण किया गया।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

01.03.2016/1155/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 2639 क्रमागत

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री क्रमागतः

एक 2012-13 में किरपा राम सुपुत्र श्री सही राम, गांव बुंडेक हैं। दूसरा श्री जगत राम, सुपुत्र श्री तुलसी राम हैं और 2013-14 व 2014-15 में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने एप्लाई नहीं किया। आप जितने भी यहां बैठे हुए हो कितनी-कितनी उम्र वाले हो? आप लोगों को शर्म करनी चाहिए कि आप अगले आदमी को किस तरह से डिस्टर्ब करते हो। बिक्रम सिंह जी तूं क्या नया जम्या या किसी के काबू नहीं आ सकदा? मुझे एक दफा धर्मशाला में धूमल साहब ने कहा था कि सुजान जी आदमी सारी उम्र जवान रहे। बड़ी अच्छी बात है। पर एक दिन उसको बचपन से बाहर आ जाना चाहिए। मैं उसी दिन बचपन से बाहर आ गया और ये बुढ़ापे से बचपन में घुस गये। आप अपनी टीम को समझाओ।

01.03.2016/1155/SS-DC/2

प्रश्न संख्याः 2640

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सभापटल पर रखी है, इसके उत्तर में इन्होंने कहा है कि 100 योजनाएं 2014-15 को भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय ने मंजूर की हैं। लेकिन 2015-16 में कोई भी योजना भारत सरकार से स्वीकृत नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि 2015-16 को हिमाचल सरकार ने कितनी योजनाएं भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजी हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह भी जानना चाह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी डी0पी0आरज़0 हैं जो आज से नहीं बल्कि पिछले 10 वर्षों से फॉरैस्ट क्लीयरैंस की वजह से रूकी हैं। जो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानक हैं वे पूरे होने चाहिएं। कम-से-कम क्लस्टर ऑफ हाउसिज़ की जो जनसंख्या है वह 250 प्लस होनी चाहिए और उसके साथ ही पी0डब्ल्यू0डी0 को जमीन उपलब्ध करवानी होगी। जमीन उपलब्ध

करवाने में ज्यादातर अब वे बस्तियां छूटी हैं जहां जंगल हैं और एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस की वजह से ये सारी डी0पी0आरज़0 भारत सरकार को भेजी नहीं जा रही हैं। इसमें मेरे ही चुनाव क्षेत्र की दो योजनाएं हैं जिनको जब मैं खुद पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर था तब परश्यू करता रहा। अब तीन साल से मुख्य मंत्री जी पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर हैं लेकिन उन योजनाओं की जो एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस है वह पिछले आठ साल से नहीं हो रही है। जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि कन्धार से थरोट सड़क है वह आठ किलोमीटर है। एक गलू से पटवारा सड़क है, अब उस सड़क की डी0पी0आर0 भारत सरकार को इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि फॉरैस्ट की क्लीयरैंस हो नहीं रही है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या समय-समय पर सरकार ने यह चाहा है कि फॉरैस्ट की क्लीयरैंस युद्धस्तर पर हो, डिप्टी कमिश्नर के स्तर पर हो, फॉरैस्ट कंजरवेटर के स्तर पर हो? लेकिन वह क्लीयरैंस नहीं हो रही है। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि ज्यादा-से-ज्यादा डी0पी0आरज़0 भारत सरकार में जाएं और वहां से मंजूर हों। फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए अभी क्या लेटैस्ट इंस्ट्रक्शन्ज़ गवर्नमैंट ने जारी की हैं? यह मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

01.03.2016/1155/SS-DC/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं इनकी जानकारी के लिए इनको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। During 2014-2015, 77 road projects and 23 bridge projects have been sanctioned for Rs. 246 Crores under PMGSY stage I&II and upgradation works. Out of 24 number projects have been completed and

जारी श्रीमती के0एस0

01.03.2016/1200/केएस/एजी/1

Chief Minister Continued . . . .

75 projects are in progress. One project is yet to be awarded. For the year 2015-2016, Rs. 188 projects amounting to Rs. 731 crores have been

submitted to the Government of India for sanction under PMGSY. The Pre Empowered Committee, Ministry of Rural Development, Government of India, consented to these proposals in its meeting held on 26.02.2016 and recommended for its approval. The final approval is awaited from Government of India. This gives the reply to your other question. आपने कहा कि जो फोरैस्ट कंजर्वेशन की जो परमिशन आती है उससे सड़कें बहुत टूट जाती है। It is a fact. We have to go to a long procedure before we get FRA permission. We are doing our best to see that all these matters which are pending with the Forest Department for final approval are pursued. हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है। अगर उनका पीछा करो तो आ जाती है।

प्रश्न काल समाप्त

01.03.2016/1200/केएस/एजी/2

सदन की समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2015-16), समिति का 23वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जो कि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

01.03.2016/1200/केएस/एजी/3

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें तथा माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चर्चा का उत्तर देंगें। श्री सुरेश कुमार जी।

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांकः 25 फरवरी, 2016 को पच्छाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत चम्बीधार में हुई बस दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज इस भाग दौड़ भरी ज़िन्दगी में हर किसी को अपने गन्तव्य तक पहुंचने की जल्दी है लेकिन कभी-कभी यह जल्दी जीवन को उस ठहराव की ओर ले जाती है जहां से लौट कर आना असम्भव हो जाता है1 ऐसा ही ठहराव उन लोगों की जिन्दगी में भी आ गया जो 25 फरवरी की सांय राजगढ़ के निकट चम्बीधार के नज़दीक पंचड़ गांव में दुर्घटना के शिकार हुए जिसमें कि जय महाकाली ट्रैवल्ज़ की निजी बस एच.पी. 14-ए-4256 की दुर्घटना हो गई। यह निजी बस लगभग दो सौ से ढाई सौ फुट गहरी खाई में गिर गई जिसमें चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और तीन लोगों की मौत सोलन अस्पताल में हुई उसके बाद एक व्यक्ति ने पी.जी.आई. में दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर इस बस में 29 लोग सवार थे और उनमें से 8 लोगों की इस

01.03.2016/1200/केएस/एजी/4

दुर्घटना में मौत हो गई और जो 21 लोग इसमें घायल हुए हैं, उनमें कुछ गम्भीर है और कुछ लोग जिनको गहरी चोटें नहीं आई थी, इसमें से एक का ईलाज आई.जी.एम.सी. शिमला में तथा छः लोगों का ईलाज पी.जी.आई. में चल रहा है। कुल मिलाकर इस

हादसे में जहां मेरे विधान सभा क्षेत्र के छः परिवारों से छःलोगों की जिन्दगी चली गई साथ ही साथ दो व्यक्ति जिनमें एक सहारनपुर से आया था । पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में ही हाबन में नाई की दुकान करता था उसकी मृत्यु हुई और एक व्यक्ति जो कि बिहार का रहने वाला था और यहां पर ग्रीन हाऊस लगाने के लिए आया था उसकी भी इस हादसे में मौत हो गई ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

01.3.2016/1205/av/ag/1

श्री सुरेश कुमार----- जारी

कुल मिलाकर इस हादसे के क्या कारण रहे यह तो जांच का विषय है और सरकार ने इसमें मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी कर दिए हैं। परंतु चिन्ता का विषय यह है कि पिछले एक वर्ष के दौरान न केवल पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में बल्कि जिला सिरमौर में ऐसे लगभग 265 छोटे-बड़े हादसे हुए जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई और वे समय से पहले ही काल का ग्रास बन गये। इसमें चाहे रेणुकाजी विधान सभा क्षेत्र, शिलाई विधान सभा क्षेत्र, पच्छाद विधान सभा क्षेत्र या पांवटा विधान सभा क्षेत्र की बात हो। जो हादसा 25 फरवरी को राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हुआ, इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या इन मौतों को रोका जा सकता था। जो सौ लोग जिला सिरमौर में और 8 लोग अभी पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में हुई दुर्घटना में मारे गये क्या वे काल का ग्रास बनने से बच जाते। आज जिस प्रकार से सड़कों की हालत है, मेरा मानना है कि पूरे जिला सिरमौर और विशेष रूप से मेरे पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सड़कों की दुर्दशा है। लिंक रोड्ज की तो बात ही छोड़िए अपितु जो मुख्य मार्ग हैं उनकी हालत भी दयनीय बनी हुई है। सड़कों में पैरापिट्स नहीं है। मुख्य सड़कें चाहे सोलन-मिन्स रोड है, सराहं-चण्डीगढ़ मार्ग की बात हो, छैला-नेरीपुल सड़क की बात हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन मुख्य सड़कों की हालत भी बहुत दयनीय है। दुःख का विषय यह

है कि पिछले वर्ष सोलन-मिन्स मार्ग की टारिंग की गई थी मगर वह 6 महीने के अंदर ही उखड़ चुकी है। ऐसे ही सराहं-चण्डीगढ़ सड़क की बात है। छैला-नेरीपुल सड़क के कुछ भाग की पिछले वर्ष रीमैटलिंग की थी मगर दुर्भाग्य यह है कि वह पूरी तरह से उखड़ गई है। यह बात बार-बार सरकार के ध्यान में भी लाई गई परंतु अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ-साथ सड़कों पर पैरापिट्स नहीं बने हैं। जो हादसा चम्बीधार में हुआ उसके बारे में स्थानीय लोगों का यह कहना था कि अगर वहां पर पैरापिट्स होते तो शायद यह हादसा न होता। इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर

1.3.2016/1205/av/ag/2

बसें चाहे राजगढ़ की बात है या सराहं क्षेत्र की बात है; वहां प्राइवेट बसें चलती हैं क्योंकि सरकारी बसों की कमी है। माननीय मंत्री जी ने जिला सिरमौर को कुछ बसें दी हुई हैं लेकिन जो बसें दी है उनकी लम्बाई बहुत ज्यादा है। विशेष रूप से पच्छाद और शिलाई विधान सभा का क्षेत्र है या रेणुका विधान सभा क्षेत्र है; उन क्षेत्रों में ये लम्बी बसें चलाई नहीं जा सकती। दूसरे इन बसों में लो फ्लोर है इसलिए इन बसों को वहां चलाने में परेशानी हो रही है। मैंने आर.एम., नाहन से बात की थी और उनका भी यही कहना था। शायद उन्होंने इस बारे में मंत्री जी को लिखा भी है। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि वहां तीखे मोड़ है और बड़ी बसों को मोड़ काटने में दिक्कत होती है इसलिए वहां पर छोटी बसें भेजी जाए। इसके अतिरिक्त प्राइवेट बसों की समय सारिणी में गैप बहुत कम होता है और प्राइवेट बसों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है जो कि हादसों को न्यौता देती हैं। इसके अलावा प्राइवेट बसों में ड्राइवर्स के पास लाइसैंस नहीं होते हैं, बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आए हैं। अभी जो हादसा हुआ शायद उसमें भी ड्राइवर के पास लाइसैंस था या नहीं, यह जांच का विषय है। बहुत सारी प्राइवेट बसों के ड्राइवर अनट्रेन्ड हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि बसों का रूट परमिट कहीं और जगह का होता है और वह चल कहीं दूसरे रूट पर रही होती है।

मैं इस ओर भी मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसी भी बस को जिस रूट का परमिट दिया गया है वह उसी पर चले। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बस अपने रूट को

श्री टीसी द्वारा जारी

01.03.2016/1210/TCV/AS/1

श्री सुरेश कुमार----- जारी

मैं इस ओर भी मंत्री जी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री) का ध्यान लाना चाहूंगा कि बसों के रूट जिनको जहां के दिए गए हैं, वह वहीं के लिए चले। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रूट तो दिए जाते हैं कहीं और के लिए, लेकिन बसें वे अपनी सुविधा के अनुसार कहीं दूसरे ही रूट पर चलाते रहते है। एक अन्य बात मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री) के ध्यान में भी लाना चाहूंगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे रूटस हैं, सडकें हैं, जिनको अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाकर के पास कर दिया गया है, लेकिन वे सडकें अभी भी तंग हैं। ये सड़कें बस योग्य नहीं है लेकिन उदघाट्न करने थे, बसों को हरी झण्ड़ी देनी थी और शीघ्रातिशीघ्र उन रूटों को पास करवाना था। इसलिए उन रूटों को पास करवा दिया जाता है, जोकि बाद में हादसों को न्यौता देते हैं। इसके अलावा बसों में ऑवर-लोडिंग की समस्या है। बसें कम हैं और उसमें ओवर-लोडिंग होती है। जब ये हादसा हुआ उस समय तो इस बस में 29 ही सवारियां थी। ये बस शादी समारोह से लौट रही थी और इससे पिछले स्टेशन पर ही इसमें से 15-20 लोग उतर चुके थे। वरना जो यह दुर्घटना हुई, इसमें मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। यह जो ओवर लोडिंग की समस्या है, इसके बारे में मेरा मंत्री जी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री) से निवेदन रहेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में और अधिक सरकारी बसें चलाई जाएं। साथ ही साथ बहुत बार देखा गया है

कि प्राईवेट बसों के ड्राईवर बस चलाते समय मोबाइल फोन पर लगे होते हैं। सडकें संकरी हैं और जरा सी असावधानी होने पर बस दुर्घटना का शिकार हो जाती है। बसों में स्टिरियो लगे होते हैं। ऊंची-ऊंची आवाज में गाने चल रहे होते हैं। जोकि दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके अलावा बहुत बार देखा गया है कि जब कोई उत्सव/मेला या शादी समारोह हो तो उस समय ड्राईवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इन सब बातों पर गौर किया जाये। ताकि आने वाले समय में

01.03.2016/1210/TCV/AS/2

इस प्रकार के हादसे न हों। इसके साथ ही मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन रहेगा कि जिन लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है, उन्हें उचित मुआवज़ा मिले और जो लोग पी0जी0आई0, चण्डीगढ़ और आई0जी0एम0सी0 में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं,उन्हें भी राहत राशि दी जाये। वैसे जिस दिन यह हादसा हुआ था, उस दिन डी0सी0, सोलन हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा एस0डी0एम0, सोलन और साथ-साथ जो हॉस्पिटल स्टॉफ था, उन्होंने भी बड़ी मुस्तैदी से काम किया। क्योंकि मैं भी दुर्घटना के तुरन्त बाद जैसे ही मुझे खबर मिली वहां पहुंच गया था। हमारे माननीय विधायक डा0 राजीव बिंदल जी जो नाहन विधान सभा चुनाव क्षेत्र से हैं, वे भी सोलन हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल स्टॉफ ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया, वरना कुछ जानें और जा सकती थी। लेकिन मुझे कल ही एक पेशेंट (घायल) श्री दीपक, सुपुत्र श्री रमेश कुमार के साथ अटैंडेंट का फोन आया था और वह आई0जी0एम0सी0 में उपचाराधीन है। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी भी राहत राशि नहीं मिली है। मैं एस0डी0एम0, राजगढ़ से सर्म्पक कर रहा था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मेरा यही निवेदन रहेगा कि जिन लोगों को अभी तक राहत राशि नहीं मिली और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाये। जो लोग मौत का ग्रास बन गए हैं, उन्हें उचित मुआवज़ा मिले। माननीय मंत्री महोदय (खाद्य, नागरिक

आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री), मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो बातें मैंने आपके ध्यान में लाई है, उनकी ओर ध्यान दिया जाये। ताकि आने वाले समय में जो इस प्रकार की दुघटनाएं हो रही है, वह दुर्घटनाएं न हों और लोगों को समय से पहले ही मौत का ग्रास न बनना पड़े। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जयहिन्द।

अध्यक्षः अब इस प्रस्ताव का उत्तर माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री देंगे

01.03.2016/1210/TCV/AS/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी ने जो जिला सिरमौर में एक अनहोनी दुर्घटना के संदर्भ में नियम-62 के तहत चर्चा उठाई है। दिनांक 25-02-2016 को करीब 6.15

बजे सायं निजी बस 'शर्मा कोच़' जोकि सोलन से हाबन की ओर जा रही थी, चंबीधार, पंच्छा नाला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बस में लगभग 30 यात्री थे, जिनमें से अभी तक 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु मौका पर, एक व्यक्ति की मृत्यु सोलन के रास्ते में हो गई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु ------

श्री आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

01.03.2016/1215/RKS/AS/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री.....जारी

और एक व्यक्ति की मृत्यु पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में हुई। बाकि 22 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति अभी तक पी.जी.आई. में, 2 व्यक्ति आई.जी.एम.सी.शिमला और एक व्यक्ति जिला अस्पताल सोलन में उपचाराधीन है। बस में सवार श्री जितेन्द्र कुमार ने अपना

ब्यान जेल धारा-154 के अंतर्गत दर्ज करवाया है कि वे दिनांक 25.02.2016 को बस नं0 एच0पी0- 14ए-4256जो कि सोलन से हावन जा रही थी, में अपने घर जा रहा था। बस का चालक राहुल, निवासी चाखल चला रहा था। बस में करीब 25-30 लोग सवार थे। जब बस पेचड़ के पास पहुंची तो तेज रफ्तारी के कारण बस खाई में जा गिरी। बस में सवार सभी लोगों को चोटें लगी। स्थानीय लोगों द्वारा घायल लोगों को निजी वाहन व एम्बूलेंस द्वारा उपचार के लिए रिजनल होस्पिटल सोलन ले जाया गया। हादसे में 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई । इस ब्यान पर अभियोग संख्याः 12/6 दिनांक 26.02.2016, धारा 279, 337, 304 आई.पी.एस. के अंतर्गत थाना राजगढ़ में मामला पंजीकृत किया गया। जिला के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का निरीक्षण किया। मैं उस समय दूर था परन्तु जब मुझे दूरभाष द्वारा सूचना मिली तो तुरंत मैंने शिशु सांतल जी, जोकि ऑल इंडिया रेडिया में हैं उनसे बात की और कहा कि मैं बुलेटिन के लिए सूचना एकत्रित कर रहा हूं। मुझे यह पता नहीं लग रहा था कि यह दुर्घटना सिरमौर हल्के में हुई या सोलन में । क्योंकि यह एक बॉर्डर एरिया है। हमने अपने आर.एम., आर.टी.ओ. सबको सूचित किया। एस.पी., सिरमौर को मौके पर भेजा गया। डी.सी. को भी इस दुर्घटना का जायजा लेने के लिए कहा गया। राहत कार्य तुरंत चलाया गया। उस समय वहां लाइट का प्रबंध बहुत कम था। स्टेट्स रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई तथा कुल 22 लोग घायल हो गए। प्रारम्भिक अन्वेषण से यह ज्ञात होता है कि यह दुर्घटना चालक राहुल ठाकुर की लापरवाही के कारण प्रतीत हुई हो रही है। मामले में अन्वेषण प्रगति पर है। इस हादसे में हुई मौतों के नाम व पत्ते मैं आपको बाद में दे दूंगा। यह सूची आपके पास भी है। मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि जब से नई लम्बी बसें, लोअर फलोर की आई हैं तब से माता की कृपा से कोई बड़ा

01.03.2016/1215/RKS/AS/2

एक्सीडेंट नहीं हुआ है। यह एक बड़ा शुभ संकेत है। हमने यह भी प्रयास किया है कि जो प्राईवेट ड्राईवर हैं उन्हें हमने आदेश दिए हैं कि वे हमारे सेंटर में ट्रेनिंग करें। परन्तु ये ड्राईवर चेंज होते रहते हैं। आपने छोटी बसें लेने की बात कही है। हम छोटी बसें 150 से ज्यादा ले रहे हैं। 37-40-42 सीटर बसें हम ले रहे हैं, ताकि ट्राईबल एरिया, हार्ड एरिया में कोई दिक्कत न आए। मैं आपको आश्वसत करता हूं कि कम से कम 20 बसें मैं सिरमौर को देने जा रहा हूं। जहां तक स्पीड की बात है, यह मोनिटरिंग की बात है इसमें पुलिस भी चैक करती है और हम लोग भी देखते हैं। मगर इसमें कंट्रोल नहीं हो सकता। यह कंट्रोल सोशल भी होना चाहिए। जो लोग बस में बैठे हैं, उन्हें भी स्पीड के ऊपर ड्राइवर को रोकना चाहिए। यह हादसा ड्राईवर और कंडक्टर की आपस में लगातार बात करने के कारण हुआ है। जो आपने रोडज के ऊपर चर्चा की है वह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है, वे स्वयं इन समस्याओं के बारे में देखेंगे। जहां तक बसिज की बात है इनकी पासिंग में हमने स्ट्रिकनैस की है और हमने यूनिफोर्म पहनने के भी निदेश दिए हैं। जहां तक ट्रांसपोर्ट विभाग है वह अपना कार्य बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जहां बड़ी बसें नहीं चल पा रही हैं वहां के लिए हम छोटी बसें लेंगे जिसके लिए हम सप्लीमेंट करेंगे। यह मैं सूचित करना चाहता हूं ।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

01.03.2016/1220/SLS-DC-1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य होंगे और सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

होगा।

<u>विचार-विमर्श</u>

अब माननीय मुख्य मंत्री जी गत सत्र में पुरःस्थापित विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधाई सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारण

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए? **हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) ध्वनिमत से पारित हुआ।**

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री गत सत्र में पुरःस्थापित विधेयक हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

विचार-विमर्श

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 8 तक विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधाई सूत्र विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायीसूत्र विधेयक का अंग बनें।

01.03.2016/1220/SLS-DC-4

पारण

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि **हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23)** को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि **हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23)** को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ **हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23)** को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है **हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23)** को पारित किया जाए?

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक **23**) **ध्वनिमत से पारित हुआ।**

01.03.2016/1220/SLS-DC-5

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

अध्यक्ष : अब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

अब श्री अजय महाजन जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री जगजीवन पाल जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे।

श्री अजय महाजन जी.. गर्ग जी द्वारा

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में सदन के वरिष्ठ सदस्य एवं माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री जगजीवन पाल जी द्वारा 25 फरवरी, 2016 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुसमर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। We all know that in the last BJP led government all the development works had come to a standstill. It was a 'लारों और नारों की सरकार।' It was insensitive to the needs and aspiration of the people of Himachal so they voted them out, realizing their mistake and voted Shri Virbhadra Singh ji led Congress Government back to power. If Dr. Y.S. Parmar is considered the creator of Himachal Pradesh them Shri Virbhadra Singh Ji can be considered as the creator of modern Himachal Pradesh. His six terms as a Chief Minister have really been a boon for the State of Himachal Pradesh. His politics starts with the upliftment of the poor, down trodden, helpless, old, youth, farmers, traders;

(In the Chair-Hon'ble Deputy Speaker)

both men and women and all other sections of the society and ends there. For him, development of the State is a mission, and for achievement of this mission no religion , region ,caste or creed is an impediment. राजा वीरभद्र सिंह जी हैं तो राजा, परन्तु उनकी जो शख्सियत है, वह फकीरों की तरह है और उनका यही कहना है कि

'हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए,
हर कड़े वक्त में जीने की अदा ले जाए।'

It is surprising and an irony that the BJP government did nothing credit worthy in its tenure, even as an Opposition party it has not played its role constructively. In a democracy the two wheels i.e. the Government and the Opposition are equally important. It was expected that having so many seasoned and senior leaders amongst them, the BJP would play a very

constructive role of the Opposition, but unfortunately beside walkouts ,

01/03/2016/1225/RG/DC/2

not allowing the House to function and personally attacking our Hon'ble Chief Minister, no real contribution has come from there side. आप जितना मर्जी परसनल अटैक करो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये सच्चे हैं और इनके साथ हिमाचल के लाखों लोगों का आशीर्वाद है और माता रानी का भी आशीर्वाद है। मैं अपने विपक्ष के दोस्तों को दो लाईनें कहना चाहता हूं। यहां करीब कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो हम में ढूंढते फिरते हैं अपनी बुराइयां, सुनो ध्यान से सुनो और इनकी तरफ से कहना चाहता हूं कि

सवाल ज़हर का नहीं था, वो तो मैं पी गया,
तकलीफ लोगों को यह थी कि फिर भी मैं जी गया।

In the last three years the Congress Government has been very development oriented and has positively touched lives of almost all sections of society in many ways. I would like to take the opportunity to elaborate some of them.

Education has been one of the priorities of the Congress Government. The previous government, it seems, was insensitive to educational need of the people. Instead of opening new schools, it closed down several schools and colleges in various parts of the State. Surprisingly it gave nod to several universities for reason best known to them and as of today majority of them are in the red. The Congress Government headed by visionary Shri Virbhadra Singh ji was sensitive to the educational needs of the rural and urban youth population of the State, specially girls for whom at times it becomes difficult to go far from their homes to seek education. The government has opened up need based schools i.e. Primary, Middle, High and Senior Secondary in large number. To meet the demand of need in the

higher education sector, several colleges, ITIs, Engineering colleges, Central Institute of Plastic Engineering Technology at Baddi and a Regional Vocational Training Institute for women in Jundla in district Shimla have been opened. Beside this there is a long list of institutions which will take a long time to put across.

But sir, I would specially like to thank the Hon'ble Chief Minister for his deep concern for all the students specially the meritorious students of the weaker

01/03/2016/1225/RG/DC/3

sections. To benefit students, an amount of 13.64 Crores was distributed among 67,619 students under the State sponsored scholarship schemes and 1,30,213 students were provided scholarship amounting Rs. 62.03 Crores under other schemes. 10,000 laptops were given to meritorious students of class 10^{th} and 12^{th}. Another thoughtful incentive and probably the first in the country is that Rs. 75,000/-is being given to all students who are getting admission into the following premier institutions like IMA, IIT, AIMS etc. Rs. 30000/- is given to students who pass the IAS preliminaries. Besides this travel for students is free from their homes to the school in HRTC buses and also free uniforms are being given to majority of students.

एम.एस. द्वारा हिन्दी

01/03/2016/1230/MS/AG/1

श्री अजय महाजन जारी----------

अब मैं बात करना चाहता हूं (व्यवधान) सुनो, सुनो। यह जो बात चल रही है यह मजाक की बात नहीं चल रही है and you are very senior Hon'ble Members. मुझे बोलने दीजिए। बुढ़ापा, अपंग और विधवा पैंशन के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने इसको 450 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया है।

सबसे बड़ी बात 80 साल से ऊपर का वह बुजुर्ग जिसको आप भी महसूस करते होंगे जब वह आपके पास हाथ फैलाकर आकर कहता था कि "मुन्नू मेरी पैंशन लवाई दे"। इसमें होता क्या था जो इनके बच्चे आगे नौकरी करते थे, उसके कारण इनको पैंशन नहीं लग सकती थी। इसके लिए हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने इन्कम के क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया है और 1100 रुपये उनकी पैंशन कर दी है। इसी तर्ज पर जो(व्यवधान) चलो, मान गए मोदी जी ने दे दिया। हमें यह सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि किसने दिया। जिसने दिया है उसी ने दिया है। इसी तरह से 70 प्रतिशत अपंगता वाले लोगों के लिए भी यह कण्डीशन वेवऑफ कर दी गई और उनको भी 1100 रुपये पैंशन लगा दी गई। सबसे बड़ी बात जो पहले 17,500 रुपये का इन्कम क्राइटेरिया था, उसमें पहले कोई नहीं आता था। उसको अब 35,000 रुपये कर दिया है और उसमें अब काफी लोग आने शुरू हो गए हैं।

इसी तरह से जो हमारा गरीब वर्ग था जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके लिए अर्बन एरियाज में चार मरले और रूरल एरिया में छः मरले जमीन देने का प्रावधान किया है। जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो आपने वर्ष 2002 में सबको कहा कि जो आपके नाजायज कब्जे हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा। आप ऐफेडेविट दे दो। वही ऐफेडेविट आज इनके गले की फांस बना हुआ है।
इसी तरह से एकल नारी, विधवा और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 30,000 रुपया ट्रीटमैंट के लिए और 1 लाख 25 हजार रुपया क्रिटिकल कण्डीशन्ज के लिए किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

01/03/2016/1230/MS/AG/2

एक बहुत बड़ा वर्ग किसानों/बागवानों का है। इनकी आजकल प्रदेश में बहुत दुर्दशा है क्योंकि वर्षा इनके हाथ में नहीं है। वर्षा के कारण सीजन का शैड्यूल चेंज हो रहा है। इसके साथ फसलों को बन्दर बहुत नुकसान कर रहे हैं और साथ में आवारा पशु और जंगली जानवर भी हैं। इसके अलावा कइयों के पास होल्डिंग्ज भी छोटी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है और सबसे ज्यादा इसमें लोग हैं। इसके लिए कोई एश्योर्ड

इरीगेशन भी नहीं है। एक "वाई0एस0 परमार किसान स्वराज योजना" 111.19 करोड़ रुपये की हैं जिसके तहत पॉली हाउस बनने हैं। पॉली हाउस एक ऐसी चीज है जैसा सरकार कर रही है, it is the only way we can fight with the schedule of seasons जो बारिश बेमौसमी आती है और बंदरों से भी हमें निजात मिल सकती है। इसके लिए 85 प्रतिशत सब्सिडी है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इसमें किसान थोड़ा सा because of controlled conditions अगर 15-20 दिन पहले मार्किट में आ जाए या लेट आए तो जो उस सब्जी या फ्लावर की वेल्यु होती है, वह बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही 11000 करोड़ रुपये का वर्ल्ड फण्डिड प्रोजैक्ट अभी शुरू हुआ है जो सभी किसानों को ऊपज और मार्किटिंग के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा।

इसी तरह से उद्योगों की मैं खास बात करना चाहता हूं कि उद्योगों के लिए गवर्नमैंट का एक इण्डस्ट्री फ्रैंडली रवैया रहा है। इसके लिए मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री दिल्ली भी गए। वहां 5 और 6 अक्तूबर को पहली इन्वेस्टर मीट हुई। उसके बाद भी कई मीट्स हुईं। दिल्ली वाली मीट में 2724 करोड़ रुपये की पोटैंशियल प्रपोजल्ज आईं। इसमें जो सबसे बड़ी बात आई, जो टैरिफ फ्रीज किया है that is very-very pro-friendly to industries. इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तीन न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया कंदरौड़ी, पंडोगा और दबोटा में बनने जा रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

01.03.2016/1235/जेएस/एजी/1

श्री अजय महाजनः----------**जारी**----------

Technology centres worth Rs.102 crores, which will be tool room for micro, medium and small industries, besides the skill development centre with an investment of Rs. 8.10 crores are also being set up in Baddi. Part-time workers, contract appointees, daily wagers and contingent paid workers are being regularized. अब बात मकानों की। अच्छे दिन आने वाली सरकार कहती थी। बड़े दुख की बात है ये जो मकान गरीबों को, असहाय लोगों को, जिनके ऊपर छत नहीं होती उनको मिलते थे। वर्ष 2014-15 में 4688 मकान सेंक्शन हुए और पिछले साल वर्ष

2015-16 में जब सरकार नई आई 2635 रह गए। मेरे अपने चुनावक्षेत्र में 75 मकान सेंक्शन हुए । उनको चिट्ठियां चली गई। वे बड़े खुश हुए। गरीब आदमी के लिए 75 हजार रूपया बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक महीने के बाद 35 मकान विद्ड्रा कर दिए। वे मेरे पास आए मैंने कहा कि यह क्या हुआ? वे कहने लगे कि ऊपर से कट लग गया। मैंने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं इस बारे में तो सेन्टर गवर्नमैंट को पूछो? बहुत अफसोस की बात है। कट लगाना है तो अदानी पर लगाओ, अम्बानी पर लगाओ, पूंजीपतियों पर लगाओ, लेकिन आप गरीब आदमी पर कट लगा रहे हैं। जो गलत बात है वह गलत बात है। हमारी स्टेट गवर्नमैंट जो कहती है वह करती भी है। हमारा जो इलैक्शन मेनिफैस्टो था उसको हमने अपना नीति दस्तावेज़ बना दिया। मगर बी0जे0पी0 की केन्द्र की सरकार के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है। जुमले से बनी सरकार की असलियत अब धीरे-धीरे सामने आ रही है। जो योजना आयोग था उसमें प्लानिंग तो होती थी और पता भी था लेकिन अब नीति आयोग बना दिया गया जिसकी नीति का कोई पता ही नहीं है। इतना जरूर पता है कि वह नीति हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बुरी है। हमारे जितने कट हिमाचल प्रदेश में लगे हैं वह नीति उनकी अपनी ही होगी। कल मेरे भाईयों ने यहां से कहा कि एक प्रश्न आई0पी0एच0 मिनिस्टर के लिए आया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था कि पैसे नहीं आ रहे हैं। इस बारे में बिल्कुल सही कहा कि सेन्टर गवर्नमैंट की जो कमिटिड लाईबिल्टीज़ हैं, स्वां चैनेलाईजेशन है, फिनासिंह स्कीम है ये सारी की सारी कमिटिड लाईबिल्टीज़ हैं लेकिन इसमें अब पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं यहां पर सभी को बताना चाहता हूं और यहां पर बहुत सारे सीनियर लीडर्ज़

01.03.2016/1235/जेएस/एजी/2

हैं कि जो पैसा है उसको स्टेट के लिए दिलाएं। हम सब लोगों को उसका फायदा होगा। जो केन्द्र की सरकार बनी है उसने और तो कुछ नहीं किया लेकिन स्कीम्ज के नाम चेंज कर दिए। स्वच्छ भारत, जिसका नाम निर्मल भारत होता था। ब्रैंड एम्बैसडर वहीं है विद्या बालन। वही एड करती थी और आज भी वही कर रही है। होता क्या कि फोटो खिंचाई और टी0वी0 में आए। बजट कम हो गया। शोर ज्यादा हो गया और एडवरटीज़मैंट का

बजट ज्यादा हो गया। स्वच्छ भारत जो निर्मल भारत के लिए बजट था उसमें कम हो गया। स्मार्ट सिटी यानि जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन होता था जहां और अब नाम डाल दिया स्मार्ट सिटी। दीन दयाल उपाध्याय विद्युतिकरण बहुत शोर मच रहा है इसका नाम होता था राजीव गांधी विद्युत योजना। डिजिटल इंडिया जिससे आज अखबारें भरी हैं, टी0वी0 में आ रहा है। राजीव गांधी जी जब कम्प्यूटर ले कर आए यह उसी का ही अन्जाम आज आ रहा है। तब क्या हुआ था पार्लियामैंट के बाहर गाड़ियां भर कर खड़ी कर दी थी और कहते थे कि सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज वही कम्प्यूटर राजीव गांधी की सोच जो डिजिटल इंडिया बन कर आ रही है। जब चुनाव लड़े गए बहुत बड़ा शोर मचा। आंधी सी आ गई और कहा गया कि हर बैंक में हर एकाऊंट में 15 लाख रूपया जमा हो जाएगा वह भी 90 दिन के अन्दर-अन्दर जमा होगा। यह कहा गया कि फौरन में बड़े पूंजीपतियों का का ब्लैकमनी है वह वापिस आएगा। उसके बाद जन-धन योजना शुरू हो गई और लोगों ने फटाफट एकाऊंट खोलने शुरू किए। जब उनको पूछा गया कि पैसे नहीं आए तो ये कहते कि यह तो जुमला था। आज वह पैसा लाने के बजाए ब्लैकमनी के लिए जो अब बजट आया है उसमें 40 व 60 प्रतिशत AMST Grant वहां से एक पैसा भी वापिस नहीं आया है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

01.03.2016/1240/SS-AS/1

श्री अजय महाजन क्रमागतः

एक बहुत बड़ी बात कही जाती थी। --(व्यवधान)-- मैं उस बात पर आ जाऊंगा, आप फिक्र मत करो। मैं वापिस आपके पास आ रहा हूं। 2013-14 में सीज़ फायर वॉयलेशन 96 हुईं। पिछले डेढ़ साल में 11 से ऊपर बॉर्डर वॉयलेशन्ज़ हुई हैं। बॉर्डर वाले जो 46000 लोग थे, दो बार माइग्रेट करना पड़ा। क्या कहते थे कि 56 इंच का सीना है, अगर एक सिर कटेगा तो मैं 10 काट कर लाऊंगा। सिर तो क्या काटने थे पाकिस्तान पहुंच गये नवाज़ शरीफ के बर्थ डे पर केक काटने। मैं फाइनैंशियल बात करना चाहता हूं। जब

2014 में बी0जे0पी0 की गवर्नमैंट बनी तब डॉलर का रेट 58.50 रुपये था और आज 68.90 रुपये है। जो हालात बन रहे हैं, उसके हिसाब से यह 74 रुपये तक जायेगा। इस सबसे अपने आपमें पता लगता है कि इकोनॉमी को क्या हो रहा है। कल जो बजट आया, उसमें ई0पी0एफ0 60 परसैंट पर टैक्स लगा दिया। सारे इम्प्लॉईज़ ने आपका क्या बिगाड़ा? इसके बारे में मुझे नहीं पता। रेलवे बजट में हिमाचल को छुनछुना मिला। अभी एक सैस लगा दी और पिछले साल भी लगाई थी। इसको कहते हैं कि जोर का झटका आहिस्ता से लगे। इससे सारे हिन्दुस्तान में रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार सैस जो लगा था उसका रिलज्ट आया है और अब भी देखना कि आगे क्या रिजल्ट आता है। महंगाई आसमान छू रही है। दालों के रेट देखो, हर चीज़ के रेट देखो, सब बढ़े हैं। अगर सस्ती हुई है तो आदमी की जान। हरियाणा देखो। जे0एन0यू0 देखो। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। सिर्फ सस्ती आदमी की जान हुई है और बाकी सब महंगा हो गया है। मैं थोड़ी बहुत बात अपनी कांस्टीचुऐंसी की कहना चाहता हूं। मैं सीधा नूरपुर पहुंच गया हूं। शिमला भी नहीं रूका। पिछले पांच साल जो सरकार थी और नूरपुर क्षेत्र था, उसमें सिर्फ एक स्कूल ठेड़-कुठेड़ का अपग्रेड हुआ। उसका भी स्टाफ वहां तब गया जब हमारी सरकार बनी। मैं मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले तीन साल के अंदर 30 स्कूल अपग्रेड हुए हैं। जिसमें साइंस क्लासिज़, ओम; साइंस क्लासिज़, सुरयाली; साइंस क्लासिज़, गनूह इत्यादि शामिल हैं। मैं बाकी स्कूलों की लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैटर बहुत लम्बा हो जायेगा। पिछले पांच साल में नूरपुर हॉस्पिटल में क्या हुआ था? हिन्दुस्तान में पहली बार हुआ होगा कि नूरपुर का हॉस्पिटल 100 बैड से 50 बैड कर दिया गया था। जब हमारी सरकार बनी तो उसको फिर से 100 बैड का किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार 150 बैड का हॉस्पिटल एनाऊंस करके गये हैं। वहां पर ढाई करोड़ की सी0टी0 स्कैन की मशीन

01.03.2016/1240/SS-AS/2

लग गई। बच्चों का आई0सी0यू0 बन गया। मिनी सचिवालय की बात करूं, उसका जो शिलान्यास हुआ था वहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मेरे स्वर्गीय पिता श्री सत

महाजन जी का बोर्ड लगा था। ये सत्ता में पांच साल रहे लेकिन वहां पर एक इंट भी नहीं लगी। जब हमारी सरकार बनी तो वहां पर एक आधुनिक बिल्डिंग तैयार हुई। जिस दिन मैं उसको inaugurate करने गया तो वह मेरे लिए फख्र का दिन था। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा कि एक तरफ सत महाजन और वीरभद्र सिंह जी का नाम लिखा और दूसरी तरफ इंओगरेशन में मेरा और आपका लिखा है, वह मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। जसूर के लिए 10 करोड़ रुपया आया। उसकी शुरूआत हो चुकी है। 29 टयूबवैल दिये गये। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और विद्या स्टोक्स जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ठाकुर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने भी हॉस्पिटल में बहुत-बहुत योगदान दिया। 29 टयूबवैल नूरपुर में लगने जा रहे हैं। 12 करोड़ रुपये की एक अपग्रेडेशन स्कीम है। इंडोर स्टेडियम अभी अनाऊंस हुआ है। इसके अलावा खन्नी, परगना, हडल इत्यादि अनेकों स्कीमें आई हैं। मैं पी0डब्ल्यू0डी0 की बात करूं तो 38 करोड़ रुपये की एक ही सड़क चुगान से लेकर तुनुहट्टी तक की शुरूआत हो चुकी है। मैं सैंकड़ों नहीं कहूंगा लेकिन पचासों सड़कें वहां बननी शुरू हो गई हैं और उन-उन इलाकों में जा रही हैं जहां कभी सड़क पहुंच नहीं सकती थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। फतुकाबाग, थोड़ा खड्ड, बलून खड्ड, लोहलाना खड्ड, ये सारे ब्रिजिज़ वहां बने हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो नूरपुर सीवरेज स्कीम थी, पांच साल पीछे सरकार थी, इसका शिलान्यास पहले हुआ था और फिर काम बंद हो गया। लेकिन अब उसका काम युद्धस्तर पर चला हुआ है। पार्किंग के लिए मैं माननीय सुधीर जी और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शहर के अंदर चार फ्लोर की पार्किंग का काम शुरू हो गया है। फिना सिंह स्कीम जो थी, उसके लिए भी मैंने कहा कि पैसे आने चाहिएं। यह मेरे पिता जी का एक ड्रीम प्रोजैक्ट था।

जारी श्रीमती के0एस0

1.03.2016/1245/केएस/एएस/1

श्री अजय महाजन जारी----

और एक डिजास्टर मैनेजमैंट स्कीम आनी थी वह बीच में चली गई लाडो और पंजाब में

। मैं सभी से कहूंगा कि कोशिश करें कि वह यहां पर वापिस आएं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो नूरपुर की बात थी लेकिन इसी स्तर पर सभी कन्सीच्युएंसिज़ में विकास का कार्य हुआ होगा। इस सरकार ने केवल वायदे ही नहीं किए बल्कि उनको पूरा भी किया है। बेरोज़गारों को रोज़गार मिला है, किसानों/बागवानों को रोज़गार के नए आयाम प्राप्त हुए हैं। प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है और यह सारा श्रेय मुख्य मंत्री जी को जाता है। इन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया है । हर गांव व क्षेत्र के लिए अधिकारिक रूप से जो भी सम्भव हो सकता था, कार्य किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की दिल की आवाज़ इस शेर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूंः-

एक कतरा ही सही, मुझे ऐसी नीयत दे मौला,

एक कतरा ही सही, मुझे ऐसी नीयत दे मौला

किसी को प्यासा जो देखूं तो दरिया हो जाऊं

1.03.2016/1245/केएस/एएस/2

उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री *श्री* वीरभद्र सिंह जी के प्रति अपनी व प्रदेश के लाखों नागरिकों की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूंः-

जनता के लिए अजब मिसाल है आप, जनता के लिए अजब मिसाल है आप,

गरीबो-बेसहारों के दुख का समाधान और हिमाचल की जनता के दिलों की जान है आप

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जगजीवन पाल जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस प्रस्ताव का आपकी

अनुमति से अनुसमर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

1.3.2016/1400/av/dc/1

(सदन की कार्यवाही दोपहर के भोजनोपरांत 2.00 बजे (अपराह्न) पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी। अब मैं नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी को चर्चा हेतु आमन्त्रित करूंगा।

प्रो0प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2016 को सत्र के प्रथम दिवस पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन को सम्बोधन दिया है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री जगजीवन पाल जी ने रखा और जिसका अनुसमर्थन श्री अजय महाजन जी ने किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महामहिम बहुत ही सज्जन पुरूष है। महामहिम वही बोलते हैं जो सरकार लिखकर देती है। पिछली बार जो कुछ लिखा था महामहिम को उसमें जो पढ़ने योग्य लगा था, वह पढ़ा था। पहला और अंतिम वाक्य पढ़कर उस समय के राज्यपाल महोदय ने अपनी बात समाप्त की थी। इस बार भी जो बातें कही गई हैं वह सत्य और तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसीलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने जब अपना अभिभाषण पढ़ना प्रारम्भ किया तो उन्हें लगा कि आगे जो पढ़ना है वह सत्य नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि 'असतो मा सदगमय' अर्थात् असत्य की ओर से मुझे सत्य की ओर ले चलो। (---व्यवधान---) स्वास्थ्य मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। इशारा ऐसा ही था कि असत्य की ओर से सत्य की ओर ले चलो।

श्री टीसी द्वारा जारी

01.03.2016/1405/TCV/DC /1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ---- जारी

'असतो मां सद्ग्मय, तमसो मां ज्योतिर्गमय' जो अंधेरा इन्होंने फैला रखा है, उससे प्रकार की ओर ले चलो। अध्यक्ष महोदय, दूसरे ही वाक्य में यह दावा किया गया है कि राज्य में, हाल ही में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया शान्तिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई । पहली बार हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में रामपुर के ननखरी ब्लॉक में खमवाडी पंचायत के वार्ड नम्बर-2 में पहली जनवरी, 2016 को नया साल प्रारम्भ होते ही 50 मतपत्रों का एक बंडल गुम पाया गया। एफ0आई0आर0 लॉज हुई है। दूसरे, जुब्बल-कोटखाई की भढ़ाल पंचायत में वार्ड न03 सरोह में एक व्यक्ति 27 मतपत्र प्रातः ही मतदान केन्द्र से लेकर भाग गया। एक अन्य जिला में काउंटिंग के दौरान, जब प्रधान पद की गिनती हो रही थी तो 50 मतपत्र वहां से हटा लिए गये। अगर ये शांतिपूर्ण चुनाव हैं तो अशांतिपूर्ण कैसे होंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले दावा यह होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं
के चुनाव में हम राजनीति को चुल्हे तक नहीं ले जाना चाहते। इसलिए राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों पर चुनाव नहीं होगा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो यह 70-75 प्रतिशत जीत जाते हैं। अगर यह दावा बाद में करना है तो कम से कम बी0डी0सी0 और जिला परिषद् के चुनाव तो चुनाव चिन्ह पर करवाओ। जो सदा होता रहा है, सारे देश में होता है, नगर निगम के चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं। आखिर ऐसी क्या घबराहट है? धर्मशाला को आप कहते हैं कि आपने वहां नगर निगम देकर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसी महीने की 27 तारीख को चुनाव होना है। ये रूल क्यों बनाया गया, कि चुनाव चिन्ह पार्टी के इस्तेमाल नहीं होंगे। पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं होगा और शायद शिमला में भी आप यही करेंगे। आखिर ऐसी घबराहट क्यों? तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा, मैंने विंटर सैशन में धर्मशाला में कही थी। 14वें वित्तायोग के धन का जो आबंटन आप कर रहे हैं, उसमें जिला परिषद् और बी0डी0सी0 के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हमने 13वें वित्तायोग की धनराशि को 50

01.03.2016/1405/TCV/DC /2

प्रतिशत जिला परिषद् के लिए, 30 प्रतिशत बी0डी0सी0 के लिए और 20 प्रतिशत पंचायत के लिए बांटा था। अन्ततः धन पंचायत के माध्यम से खर्च होता है। जो एम0पी0, एम0एल0ए0, जिला परिषद् का पार्षद और बी0डी0सी अलाउंस करता है, उसकी एग्जिक्युटिंग ऐजेंसी तो पंचायत है। यदि उनको धन या प्लॉन उनको नहीं देना है या कोई योजना उन्होंने नहीं बनानी है तो जिला परिषद् और बी0डी0सी0 का औचित्य क्या है? थ्री टायर सिस्टम क्यों। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस पर पुनर्विचार करें। जिला परिषद् और बी0डी0सी0 के पार्षदों को धन आबंटित किया जाये ताकि वे विकास कार्य कर सकें। एक और नई बात जो पहले आपने नगर निकायों में की थी कि चैक पर साईन नगर परिषद् के अध्यक्ष के नहीं ई0ओ0 के होंगे।

श्री आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

01.03.2016/1410/RKS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल.....जारी

आज सवेरे बड़ी चर्चा हुई कि किस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों को अपमानित किया जा रहा है। यह बाह्य एजेंसियां ही नहीं कर रही है, सरकार भी जाने- अनजाने में ऐसा कर रही है। आपने कहा ई.ओ. ही करेगा, परन्तु जब बाद में अध्यक्ष आपको मिले तो शायद असाइनिंग पावर उनको अलौ की गई। हम पंचायत के प्रधानों को भी हिदायत दे रहे थे कि जिला परिषद् और बी.डी.सी. के पास तो कुछ नहीं रहा। सारे पैसे का इस्तेमाल आप ही करोगे। परन्तु अब आपने यह कर दिया कि इस पैसे का इस्तेमाल अधिकारी व कर्मचारी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान अगर पंचायत स्तर से शुरू होगा तो यह ऊपर तक जाएगा। मेरा निवेदेन है कि जो जनता का विश्वास जीत कर आते हैं उन पर आप विश्वास करिए और जो प्रथा चल रही है उसके

अनुसार काम करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय कम दिया है। तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि सरकार ने लगभग सभी चुनावी वायदों को पूरा कर दिया है। 'सरकार द्वारा अर्जित उपलब्धियां, मेरी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की साक्षी है।' उपलब्धियां कहां हैं? अगर आप कहते कि ये उपलब्धियां हैं और इस बात का साक्ष्य यह है कि हमने ये काम कर दिये हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कार्य कर दिये हैं। मैंने इसीलिए आपका चुनाव घोषणा पत्र निकलवाया कि इसमें से आपने क्या-क्या पूरा कर दिया? आपका पहला वायदा है कि राजस्व आय में वृद्धि हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रयत्न किए जाएंगे। राजस्व में कितनी वृद्धि हुई? जो राज्यपाल महोदय ने ब्योरा दिया है, राज्यपाल का अभिभाषण पिछले कार्यों की झलक होती है और माननीय मुख्य मंत्री जो स्वयं वित्त मंत्री हो, उनका जो बजट भाषण होता है वह आने वाले साल का प्रतिबिम्ब होता है। 'वित्तीय मानकों और राजकोषीय घाटा एवं राजस्व अधिशेष में सुधार के प्रयास किए जाएंगे।' आगे इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपने इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए? 'राज्य सरकार की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।' दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता, Financial

01.03.2016/1410/RKS/AG/2

Stability इसके लिए क्या कदम उठाए? 35,000 से ज्यादा का ऋण हो गया है। क्या ऋण उठाकर हम इसको स्थिर कर सकते हैं? 'ख' भाग में हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में गुणवत्तापूर्वक सुधार हेतु खाली पदों पर निष्पक्ष चयन लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। वस्तुस्थिति क्या है? क्या विभागीय लोग नहीं रखे जा रहे हैं? क्या सबोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड से कुछ पोस्टों को स्लेक्ट करने का काम आपने पब्लिक सर्विस कमीशन से शिफ्ट नहीं कर दिया? जो कांगड़ा सहकारिता बैंक की भर्ती आई.बी.पी.एस. के माध्यम से होती थी,

राज्य सहकारिता बैंक की भर्ती जो आई.बी.पी.एस. के माध्यम से होती थी, निष्पक्ष होती थी। उसको आपने स्कूल एजुकेशन बोर्ड को दे दिया। जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड अपना टाईमली रिजल्ट नहीं दे सकता, उस स्कूल एजूकेशन बोर्ड में बिना पेपर दिए पास होन की घटना भी हुई हैं। आपके मंत्रियों, रिश्तेदारों को किस तरह से नम्बर मिले थे, क्या हुआ था, केसिज आज भी कोर्ट में चले हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। यह क्यों किया गया? आपके समय में जब राज्य सहकारिता बैंक की भर्ती हुई थी तो कुछ कैंडिडेट्स के अलग कमरों में पेपर करवाए गए थे और सांगटी में रिकॉर्ड जला दिए गए थे। उस भर्ती का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

01.03.2016/1415/SLS-AG-1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ...जारी

इसलिए एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया परंतु दूसरी जगह भी लोग कोर्ट्स में गए हैं। लेकिन यह पारदर्शिता का तरीका नहीं है कि आप एजुकेशन बोर्ड से भर्ती का काम करवाओ। उनको एजुकेशन का काम करने दो।

'राज्य स्तर पर सशक्त पब्लिक ग्रीवांस कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे।' हमें भी तो उनका नाम-पता लगे कि कौन नियुक्त किए गए हैं। एम.एल.एज. की शिकायत है कि वह जो पत्र लिखते हैं, उनका जवाब उनको ही नहीं मिलता तो आम आदमी को क्या मिलता होगा?

शिकायत निवारण के लिए निश्चित समयावधि की बात कही गई है लेकिन इसके लिए न तो मंत्रालय स्तर पर कोई है न किसी ऑफिसर की जिम्मेवारी है।

सिटिजन राईट्स की बात कही गई है। 'नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से प्रत्येक कार्य को करने हेतु समयबद्ध पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा।'

सिटिजन राईट्स का चार्टर है कहां? जो अधिकार-पत्र बना ही नहीं उसे लागू क्या करेंगे?

आपने कहा कि 'आधुनिक खुदरा व्यापार के लिए विपणन मार्किटिंग संपर्क और कोल्ड स्टोरेज सुविधा को बढ़ावा देंगे।' इन 3 वर्षों में कितने नए कोल्ड स्टोरेज बने हैं? उनका ज़िक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आना चाहिए था कि हमने इतने नए स्टोर जोड़ दिए।

आपने कहा कि प्राईवेट लोगों से जो धन लेते थे उससे बचाने के लिए सहकारी बैंकों में प्रबंध किया जाएगा। मुख्य मंत्री महोदय, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जांच करवाइए। क्या कौपरेटिव बैंक्स के बीच में लोन में कमीशन का धंधा शुरू हो गया है या नहीं? अपनी सी.आई.डी. एजैंसी से जांच करवाइए कि कितने करोड़ों का धन लोन में दिया जा रहा है और उसमें कितना कमीशन लिया जा रहा है। किसी-किसी इनवैस्टर को तो, जो एक बैंक से पहले पैसे ले चुका है, वह

01.03.2016/1415//SLS-AG-2

उसी काम के लिए दूसरे बैंक से भी धन ले रहा है। आपके कांगड़ा सैंट्रल कौपरेटिव बैंक से और स्टेट कौपरेटिव बैंक से भी साथ-साथ लोन लिए जा रहे हैं। यह तथ्य हैं।

'अधिक रोज़गार सृजित करने के लिए उद्योगों को सशक्त बनाने का प्रयास होगा।' आपके विधायक जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इनवैस्टर मीट हुई। पहली दिल्ली में हुई और फिर अन्य स्थानों पर हुई और बड़े भारी प्रोमिजिज हुए। अध्यक्ष महोदय, यह सारा चिट्ठा इनवैस्टमैंट और यहां से उद्योगों के बंद होने का है। परसों रविवार के दिन दिव्य हिमाचल में 'दखल' नाम से एक पूरा पेज इसी बात पर लगा था और उसका हैडिंग था - कहां खो गया निवेश। Where has the investment gone? और उसमें जो बात इनवैस्टर मीट की कही गई वह शायद यही उन्होंने पढ़ी थी। 'इनवैस्टर मीट भी

नहीं आई काम।' अकेले परवाणु से 64 उद्योगों की यह लिस्ट है जहां बिजली बोर्ड ने बिजली के परमानैंट डिसकनैक्शन कर दिए हैं । वहां यूनिट बंद हो गए हैं। कुल 63 यूनिट्स बंद हो गए और 64वां वहां से शिफ्ट कर गया। मालवा कौटन नाम की एक मिल सिरमौर जिले में बंद हुई। वह वर्षों से चल रही थी।

जारी...गर्ग जी

01/03/2016/1420/RG/AS/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल-----क्रमागत

और पैकेज से पहले की चल रही थी। पांच हजार महिलाएं उस क्षेत्र में जो यूनिट्स बन्द हुए और दो हजार तो मालवा कॉटन मील की महिलाएं ही बेरोज़गार हुई हैं। आपने रोज़गार देने का वायदा किया था। अगर वायदे का अर्थ यही था कि सारे वायदे हम पूरे कर देंगे और आपने घोषणा करवा दी कि हमने वायदे पूरे कर दिए। यह मेरे पास सूची है, मैं माननीय उद्योग मंत्री को इसको भेज दूंगा। यदि वे चाहें, तो कनफर्म कर लें कि क्या ये यूनिट्स बन्द हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, यदि इस तरह उद्योग बन्द होंगे, तो रोज़गार मिलेगा किसको? अध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण के बारे में कहा गया। कहा गया कि वन नीति की समीक्षा की जाएगी एवं नई नीति बनाई जाएगी। औषधीय परिस्थितियों के अनुकूल पौधे लगाए जाएंगे। वनों के बारे में सारी बात इसमें कही गई है। वैसे तो आपके ध्यान में यह बात आई होगी। 'वन महक़मों की टीम पर डण्डों से हमला', 'बरसाए पत्थर', 'तस्करों को पकड़ने गए रेंजर व डिप्टी रेंजर समेत चार कर्मचारी घायल', 'ऊना के हड़ोली में गोंदपुर-जयचन्द में देर रात 10.00 बजे के बाद वारदात', 'सरकारी गाड़ी को बुरी तरह तोड़ा', 'घायल अधिकारी अस्पताल में भर्ती।' 15-20 लोगों ने हमला किया और सिर्फ एक आदमी गिरफ्तार हुआ। इसके अतिरिक्त जो आपकी टीम गई थी उनके मोबाईल भी छीन लिए गए। आखिर इतना यह सब कुछ कैसे हो पा रहा है? इनको किसका आश्रय प्राप्त है? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? ये वहां के स्थानीय लोग ही होंगे जिन्होंने किया होगा क्योंकि उनकी लकड़ी जा रही होगी। इनको संरक्षण कौन दे रहा है? 'प्रदेश से सालाना 50 करोड़ रुपये की लकड़ी हो रही है

तस्करी।' अध्यक्ष महोदय, यदि कानून-व्यवस्था की यह स्थिति है और आपकी सरकार की घोषणाओं को लागू करने की, तो क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर बहुत बातें कही गई हैं। 'क्वालिटी बेस्ड' की इसमें बात कही गई है। मुख्य मंत्री महोदय, आपके ध्यान में भी आ गया होगा क्योंकि शिक्षा विभाग आपके पास ही है। आपने इसी सदन में 'रूसा' को डिफेंड किया था और कहा था कि जब नए कुछ काम किए जाते हैं, तो ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं। हमने भी माना था कि शायद आगे कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पंजाब एवं दिल्ली विश्वविद्यालयों ने आपके छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। 'रूसा' पर रुसवाई हो रही है। जो बच्चें यहां से ग्रेजुएशन होकर पोस्ट-ग्रेजुएशन में वहां प्रवेश नहीं ले सकते। हिमाचल विश्वविद्यालय जिसको शायद लगभग 40-45 साल हो गए होंगे, आज उसकी स्थिति यह है कि हैड लाइन्ज में लग रहा है कि यहां से जो पढ़कर आएगा, हम उसको प्रवेश नहीं देंगे, वह कम्पटीशन नहीं कर

01/03/2016/1420/RG/AS/2

सकता। 'Opposition to RUSA gets shield 'Hindustan Times' 'रूसा' पर मुश्किल में फंसेगा विश्वविद्यालय प्रशासन', 'दैनिक सवेरा', 'Teaching in collages take back seat

. 'The Tribune', कि काम ही और-और करवाए जाते हैं अध्यापकों से, पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति क्या है? कहीं विधायक शिकायत करते हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र में अध्यापक नहीं हैं, स्कूल खाली हैं। मुख्य मंत्री महोदय, मैं दो ही कटिंग आपको सुनाना चाहता हूं। 'सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बैठा भट्ठा', 'कहीं छात्र कम, तो कहीं शिक्षक ज्यादा।' 'रामनगर स्कूल में तीन छात्रों के लिए दो अध्यापक।

एम.एस. द्वारा जारी

01/03/2016/1425/MS/AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी----------

"रजौल स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था का अनोखा नमूना- छः विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं

दो अध्यापक"। आज अजय महाजन जी कह रहे थे कि विकलांगों के लिए बहुत किया। "दिव्य हिमाचल" और "ट्रिब्यून" में शायद कल आया था कि "विकलांगों को नहीं मिली निःशुल्क शिक्षा" Umang Foundation to file contempt plea against Government. यह तो कुल मिलाकर लगता है कि आपके अधिकारियों को यहां से ज्यादा कोर्ट की दौड़ रहती है, जिस तरह से हर मामला अदालत में जा रहा है। High Court orders on providing free education to special children defied, says Chairman

यह मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई है। जैसे मैंने कहा कि अध्यक्ष जी, आपने बोलने के लिए समय कम दिया है जबकि हर चीज पर बहुत बोला जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा में यह क्या बात है कि जब एडमिशन्ज शुरू होते हैं तो बहुत हाई स्टैंडर्ड रखा जाता है और कहा जाता है कि 60 और 65 प्रतिशत से कम अंक वालों को एडमिशन नहीं दी जाएगी और उत्तर दिया जाता है कि स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने बार-बार उस समय भी प्रश्न किया था कि मान लो आप 60 प्रतिशत अंक से नीचे एडमिशन नहीं देते, मैं इस बात को भी एप्रिशिएट करने को तैयार हूं। परन्तु आपके पड़ोस के राज्य में 45 प्रतिशत अंकों वाला एडमिशन ले रहा है। वह वहां से आई0टी0आई0 डिप्लोमा, पॉली टैक्निक डिप्लोमा या बी0टैक करके आ रहा है और जब आप यहां पोस्ट्स एडवरटाइज करते हैं तो क्या ऐसी पाबंदी है कि पड़ोस के राज्य से जो डिप्लोमा करके आएगा, आप उसको नहीं लेंगे? वह 45 प्रतिशत अंकों वाला विद्यार्थी बाहर से डिप्लोमा करके यहां टैस्ट क्वालिफाई कर जाता है और आपके यहां जॉब ले लेता है। 59 प्रतिशत अंक वाले को आपने यहां एडमिशन नहीं दी थी। वह कोई कोर्स ही नहीं कर सकता, तो वह कहां जाएगा? अध्यक्ष जी, विचित्र मिस्ट्री यह है कि दो-तीन साल से हम लगातार देख रहे हैं कि पहले एडमिशन बंद होता है कि इतना स्टैंडर्ड लिया जाएगा, इससे कम प्रतिशत वाले को एडमिशन नहीं देंगे। आखिरी दो रात में वह क्या होता है जब एडमिशन खुल जाता है और कण्डीशन्ज रिलैक्स कर दी जाती हैं और फिर 45 प्रतिशत

अंक वालों का यहां भी एडमिशन हो जाता है। आखिर इससे हम शिक्षा की कौन सी क्वालिटी दे रहे हैं? इस बारे में जरा सोचिएगा।

पैरा संख्या-17 में महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्वास्थ्य का जिक्र किया है। ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष 2013-14 का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़कर इसको तैयार नहीं किया गया है। आपने उसमें कहा था कि मण्डी, हमीरपुर और धर्मशाला में जो जोनल अस्पताल हैं वहां भी गुर्दे के मरीजों को डायलेसिज की सुविधा दी जाएगी। शायद कल की अखबार में आया था कि "आई0जी0एम0सी0 में जल्दी ही लगेगी डायलेसिज मशीन", "खराब पड़ी है मशीन, कम्पनी अधिकारियों ने दिया मशीन का डेमो", "किडनी रोगियों को होगा लाभ, पांच मशीनें लगाने की योजना"। कौल सिंह जी आपको बधाई क्योंकि अब केन्द्र ने ही एक योजना कल बजट में अनाऊंस कर दी है कि हर जिला अस्पताल में डायलेसिज की सुविधा देने के लिए केन्द्र मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसका लाभ उठाएंगे।

इसी तरह से खबर है कि "हजारों बुजुर्गों के नहीं लगाए जा सके दांत" और आपके चुनाव घोषणा पत्र में आपने कहा है कि हम आते ही सारे जो तकनीकी स्टाफ है, पैरा मेडिकल स्टाफ है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

01.03.2016/1430/जेएस/एजी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः-------**जारी**------

मैंने अखबार में रिपोर्ट पढ़ी कि 295 के बजाए आपके पास 95 ही है। इस करके बुजुर्गों के डैंचर्ज़ नहीं लग रहे हैं जो मोस्टली बी0पी0एल0 वालों को लगाते थे। मुस्कान योजना जो हमारे कार्यकाल में शुरू हुई थी। पहले आप कहते थे कि हमने ट्रेनिंग नहीं दी है, लेकिन तीन साल में तो कोई भी ट्रेनिंग हो जाती है। उन डैंचर्ज को लगाईये ताकि लोगों को सेवा उपलब्ध हो सके। राज्यपाल महोदय से आपने यह भी पढ़वा दिया कि चार कैंप आपने आयूर्वेद के लगाए थे और उसमें 1866 मरीज देखे गए। यह क्या कोई बड़ी

उपलब्धि है जिसको राज्यपाल महोदय अपने मुखरविन्द से पढ़ कर यहां सुनाए?

अध्यक्ष महोदय, पैरा 22 से 24 में आपने दालों का जिक्र किया है। पी0डी0एस0 के सिस्टम का जिक्र किया है। मंत्री जी ने अपना नम्बर भी दिया था। हर पी0डी0एस0 की दुकान में इनका नम्बर लिखा हुआ है। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पहले रौंगी दे रहे थे और आजकल राजमाश दे रहे हैं। जो लोग डिपू से राशन लेते हैं उनकी शिकायत है कि रौंगी का दाना भी बहुत छोटा है और अब जो राजमाश दिए जा रहे हैं वह तो बिल्कुल छोटे-छोटे हैं। वह बदबू मार रहे हैं और उससे लोग बीमार हो रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि जो सैम्पल्ज आपने अप्रूव किए थे उन सैम्पल्ज की आप जांच करवाईए। उसकी तुलना करें। डिपुओं की राशन की दुकानों में गड़बड़झाला है। यह अमर ऊजाला की रिपोर्ट है। मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। इसमें स्पैसेफिक नाम दिए हुए हैं। इसमें डिपू का नाम है और प्रधान का नाम है। बड़सर हमीरपुर में सस्ते राशन के डिपुओं में राशन सप्लाई में गडबड़झाला सामाने आया है। सिविल सप्लाई कार्पोरेशन की राशन सप्लाई में दालों के कुछ खाली पैकेट और कई कम वज़न के पैकेट पहुंच रहे हैं। कुछ पैकेट खाली हैं और कुछ का वज़न कम है। मैं इसको पढ़ रहा हूं आप इसकी जांच करिए। मैंने तो यह नहीं कहा कि ऐसा है। ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के कृषि सहकारी सभा भालक में कम

01.03.2016/1430/जेएस/एजी/2

पैकिंग की दालों और रिफाईंड तेल की सप्लाई पहुंची है। सहकारी सभा के अध्यक्ष, श्री रमेश चन्द ने खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के इस मामले की जांच की उचित कार्रवाई की मांग की है। ऑलरेडी आपके पास डीमाण्ड आई है। श्री रमेश चन्द ने बताया कि उन्होंने डिपू का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान राजमाश के दो पैकेट खाली मिले, जबकि रिफाईंड तेल के पैकेट में मात्र 200 ग्राम तेल पाया गया। हालांकि रिफाईंड तेल का पैकेट पुरी तरह से सील्ड पाया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य, आपूर्ति

एवं उपभोक्ता निगम ने जो राशन मुहैया करवाता है लेकिन सप्लाई में गड़बड़ होने लगी है। पैकेट पूरी तरह से सील है और उसमें राजमाश के कुछ ही दाने दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप ट्रांसपैरेंट बता रहे थे, लेकिन हम उसमें देख रहे हैं। रिफाईंड तेल का पैकेट भी पूरी तरह सील है लेकिन पैकेट में तेल कम है। उसमें 200 ग्राम तेल ही है। शिकायत विभाग को भेजी गई है। एक जो आपने स्टाईल बदला है कि जो ठीक होगा वह देंगे। कभी काबली चने देंगे, कभी राजमाश देंगे, कभी रौंगी देंगे और मुझे लगता है कि इसके कारण भी काम जो व्यवस्थित होता है वह डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आप निश्चित करके दे रहे हैं तो आपके ऑर्डर हर दूसरे-तीसरे महीने बदलने पड़ते हैं वह भी न बदलने पड़े। चीनी बीच में कई बार नहीं मिलती। आपने राज्यपाल महोदय से पढ़वा दिया कि हर महीने आप आयोडाईज्ड नमक एक किलोग्राम देते हैं । आपने इसी सदन में स्वीकार किया था कि आयोडाईज्ड नमक के कई सैम्पल्ज क्वालिटिवाईज फेल हुए। मेरा यही आग्रह है कि लोग बड़ी आशा के साथ डिपू में जाते हैं ताकि उनको रैगुलरली राशन मिले।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

01.03.2016/1435/SS-DC/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

कृषि के बारे में जो उपलब्धियां कही गई हैं मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सर्वे किया कि कितनी कृषि भूमि पर लोगों ने कृषि करनी बंद कर दी? --(व्यवधान)-- कृषि भूमि में आपने कहा कि इतने हज़ार एकड़ अब और कृषि होगी, क्या आपने पता किया कि बंदरों, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं के कारण कितनी भूमि पर लोगों ने कृषि करनी छोड़ दी है? क्या आपने यह भी सर्वे करवाया है? आप वह भी आंकड़े दीजिए। पैरा-37 में आपने कहा है कि इंश्योरैंस की स्कीम को लागू किया। अब प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना चली है। उसमें बहुत कम खर्च आपको करना पड़ेगा। लेकिन किसान को बहुत राहत दी जा सकती है। मुझे विश्वास है, आप किसानों के बड़े हितैषी

होने का दावा करते हैं, उसको अवश्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पैरा संख्याः 38-39 में खर्चे का ज़िक्र किया गया है कि 6 करोड़ 7 लाख, 12 करोड़ 38 लाख इस काम पर खर्च किये गये। लेकिन उपलब्धि क्या है? रिजल्ट क्या है? पैसा खर्च करना कोई उपलब्धि नहीं है। उस पैसे को खर्च करके आपको उपलब्धि क्या हुई, अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। गोसदनों के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान का ज़िक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने हर पंचायत के प्रधान को आदेश दिया था। शायद पिछले 31 मार्च तक हर पंचायत में गोसदनों की स्थापना का आदेश था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने गोसदन स्थापित हुए? 10 करोड़ से कितने गोसदन बनेंगे? इसलिए राज्यपाल महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा - 'असतो मा सद्गमय'।

मुख्य मंत्रीः ये कह रहे हैं कि राज्यपाल राज्यपाल नहीं हैं बल्कि जैसे वे आपके संरक्षक हैं। Keep him out of the controversy.

Sh. Prem Kumar Dhumal: I am keeping him out of controversy and he himself has kept him out of controversy by saying - 'असतो मा सद्गमय'।

मुख्य मंत्रीः उनके कहने का मतलब कुछ और था और आप उसको ट्विस्ट करके अपने हिसाब से बता रहे हैं। यह बात सही नहीं है। ठीक है, गवर्नर साहब आपके हितैषी होंगे, मगर हम मानते हैं कि वे प्रदेश के भी हितैषी हैं। हमारे भी हितैषी हैं। आप इस तरह से जो उन्होंने बातें कही हैं उसको ट्विस्ट करके ये बताने की

01.03.2016/1435/SS-DC/2

कोशिश न करें कि गवर्नर साहब किसी तरह से सरकार की आलोचना कर रहे हैं। This is wrong. This is your interpretation, not my interpretation.

Sh. Prem Kumar Dhumal: Interpretation can be different but meaning cannot be different. 'असतो मा सद्गमय' का अर्थ यही होगा कि असत्य से सत्य की ओर ले चलो। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' - अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। इसलिए इसमें तो राज्यपाल महोदय का सम्मान है कि उन्होंने पहले ही अपने आपको इस दोष

से बचा लिया कि असत्य बुलाया जा रहा है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आम बात कही है सारे सदन के लिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः सच्ची बात कही है। जब यही कह रहे हैं कि उन्होंने आम और सच्ची बात कही है।

मुख्य मंत्रीः उन्होंने आम बात कही है सारे सदन के लिए कि हमारी कार्यवाही कैसी होनी चाहिए। मगर आप यह कहते हैं कि उन्होंने आपके पक्ष की बात कही है जैसे कि हम झूठ बोल रहे हैं और उसकी पुष्टि कर रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। It is universal.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आप इसमें इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?

मुख्य मंत्रीः इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो बात जाहिर है हम उसको प्रकट नहीं करना चाहते। जो बात गवर्नर साहब पर जाहिर है हम उसको प्रकट नहीं करना चाहते हैं। Don't bring him into controversy.

Sh. Prem Kumar Dhumal: You are bringing him into controversy.

Chief Minister: You are bringing Governor into controversy.

Sh. Prem Kumar Dhumal: You are bringing him into controversy I am honouring him that he is a true person and he has said the truth in the beginning itself.

Chief Minister: Which is applicable to you.

01.03.2016/1435/SS-DC/3

Sh. Prem Kumar Dhumal: It is applicable to everybody. आप कह रहे हैं कि गवर्नर हमारे भी हैं अब वह मेरे पर ही लागू होता है।

मुख्य मंत्रीः झूठ की और बातें ट्विस्ट करने की भी कोई सीमा होती है। हर चीज़ को

ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्रीमती के0एस0

01.03.2016/1440/केएस/एजी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जगजीवन पाल जी ने एक बहुत अच्छा प्वाइंट उठाया था। उन्होंने पंजाब के नशे की बात की। यहां तो राज्यपाल के अभिभाषण में नशे का कहीं ज़िक्र ही नहीं है। ड्रग एडिक्शन का कहीं ज़िक्र ही नहीं है और पंजाब की पुलिस ने आकर आपके क्षेत्र में छापा मारा। वहां ड्रग की फैक्टरी पकड़ी गई और उसी क्षेत्र में कई नौजवान नशे के कारण मरे हैं, यह तथ्य है। आप समझते ही नहीं कि ड्रग के कारण प्रदेश को व देश को खतरा है? यदि समझते हैं तो आपने इसमें मैंशन क्यों नहीं किया?

मुख्य मंत्रीः एक बात को बार-बार मैंशन करने की जरूरत नहीं होती। यह बुद्धिजीवियों का सदन है । जो बात हम कई दफ़ा कह चुके हैं, उसको बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि Drug menace is a threat to the country and the State also and we are dealing with it.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्री महोदय को इतनी ही तकलीफ़ है तो अपने चैम्बर में जा कर सुनें। बार-बार वहां इनको उठना नहीं पड़ेगा। ये हर बात पर खड़े हो जाते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं तो अभी ही उठा। धूमल जी की दूसरों पर ऊंगली उठाने की पुरानी आदत है। जब मैं आपके ऊपर ऊंगली उठाऊंगा तब आप याद करेंगें कि क्या चीज़ है परन्तु हम ऐसा नहीं करते।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः यदि आप अभी ही उठे तो क्या इससे पहले आप सोए हुए थे?

01.03.2016/1440/केएस/एजी/2

मुख्य मंत्रीः नहीं, मैं बैठा हुआ था और आपकी बात सुन रहा था। काफी सुन लिया और आपकी पूरी स्पीच कोई कंस्ट्रक्टिव स्पीच नहीं है, दोषारोपण की स्पीच है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं तो पैराग्राफ कोट कर रहा हूं। वह डॉक्यूमैंट कोट कर रहा हूं जो आपका मैनिफैस्टो है। मैं तो पेज गिनाकर कह रहा हूं कि आपने यह नहीं किया। आपने जो कुछ इसमें लिखा है, मैंने पैराग्राफ नम्बर साथ में दिया है और जो आपने नहीं किया है उसके बारे में बता रहा हूं कि आपने यह नहीं लिखा। विपक्ष का काम आलोचना करना ही होता है । विपक्ष आलोचना करता है और आप अगर इतने पुराने अनुभवी हो तो आपको उसको सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, आलोचना की भी एक सीमा होती है। आपकी जो स्पीच है it is nothing but like time to find some dirt somewhere. It is not constructive speech.

Prof. Prem Kumar Dhumal: I am reminding you of your past.

Chief Minister: I am going to remind you about your past and future also.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः पैरा नं0 54 पर सड़कों के बारे में बड़ा ज़िक्र किया है। मुख्य मंत्री जी, आप अपने उत्तर में बताएं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने मण्डी में कहा कि सड़कों की खस्ता हालत के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनको मैं डिमोट कर दूंगा। एक्सिअन को एस.डी.ओ. बना दूंगा, एस.डी.ओ. को जे.ई. बना दूंगा लेकिन कितने डिमोट हुए? सड़कों की स्थिति आज क्या है? आपका यह बयान लगा हुआ है लबाणा बोर्ड की मीटिंग में आपने कहा कि जो ठेकेदार समय पर अपना काम नहीं करते उनको ब्लैक लिस्ट कर दो। हमें तो कहते हैं कि हैड लाईन लेने के लिए वाक आऊट हुआ क्या

आपने भी हैड लाईन लेने के लिए बयान दिया? कितने ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए? कितने डिमोट हुए?

01.03.2016/1440/केएस/एजी/3

मुख्य मंत्रीः कुछ हुए हैं और कुछ किए जा रहे हैं। यह वार्निंग थी । अगर नहीं मानेंगें तो यह अमल में आएगी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, पैरा ग्राफ 59 और 60 - इस अभिभाषण में इलैक्ट्रिसिटी पर बहुत दावा किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड ने जो विद्युत मीटर खरीदे हैं, इलैक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद, जिसमें सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ और करंट मीटरों की विगत वर्षों में खरीद बड़े स्कैंडल और भारी भरकम क्रप्शन की ओर इशारा करती है। इसकी न्यायायिक जांच होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विगत वर्षों में बिजली बोर्ड ने दिल्ली की एक फर्म को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार ऑर्डर करके करीब ढाई लाख से तीन लाख तक मीटरों का ऑर्डर दिया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

1.3.2016/1445/av/ag/1

प्रो0प्रेम कुमार धूमल----- जारी

जब ये मीटर फील्ड में लगे तो लगते ही उनमें से बहुत सारे डिफैक्टिव पाये गये। तदोपरांत ऑर्डर कैंसिल किया गया परंतु उन खराब मीटरों की रिप्लेसमैंट अभी तक बाकी है और फर्म पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। क्या यह सच्च है कि बोर्ड ने करीब 23 हजार थ्री फेज़ वोल्ट के कंरट मीटर बहुत बड़ी लागत से अपनी जरुरत को आंके बिना वर्ष 2013 में खरीदे और यह भी पता चला है कि इनमें से लगभग 13 हजार मीटर अभी भी बिना उपयोग के स्टोर में पड़े हैं।

मुख्य मंत्री : इस सूचना के लिए धन्यवाद। यह मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी इनक्वायरी करूंगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अभी तो **'इब्तदा-ए-ईश्क है, रोता है क्या।**

आगे-आगे देखिए, होता है क्या॥'

मुख्य मंत्री : मैं आपके ऊपर चार किताबें लिख सकता हूं what you have done. But keep quite about it because past is past, forget about it. और आपने जो मीटर्ज के बारे में कहा है it is not in my knowledge. I will definitely hold enquiry about what you have said.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : आपने अभी मेरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं भी जांच की मांग कर रहा हूं। ऐसा क्यों किया गया और वास्तव में मीटर कब लगाये जायेंगे क्योंकि अभी भी 13 हजार मीटर स्टोर में पड़े हैं। (---व्यवधान---) गम्भीर आरोप है और आप इसको इतना लाइटली लेना चाहते हैं तो रहने दो हम डिसकशन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते। मैं पैराग्राफवाइज बोल रहा हूं और आपसे पूछ भी रहा हूं।

अध्यक्ष : माननीय धूमल जी, आप और कितना समय लेंगे?

1.3.2016/1445/av/ag/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो जितना समय इन्होंने लिया उतना मैं भी लूंगा। मगर मैं इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा।

भावा बिजली परियोजना में 23 जनवरी, 2015 को 40 मैगावाट के तीन जनरेटिंग हाउस में आग लगी और नुकसान हुआ। उससे प्रदेश को लगभग 400 करोड़ रुपये के नुकसान की सम्भावना है। वहां से हर वर्ष 500 मिलियन युनिट बिजली पैदा होती है और लगभग 200 करोड़ रुपये की बिजली प्रदेशवासियों को उपलब्ध होती है। अब एक वर्ष से

अधिक समय से परियोजना बंद है। यह दोबारा कब चालू होगी इस बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। ऐसा हुआ क्यों? जिस 22/4के0वी0 के ट्रांसफॉर्मर में आग लगी थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई वह एक लम्बी अवधि से खराब पड़ा था। इस अवधि में संजय विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन में कोई बाधा नहीं पाई गई। वहां से बिजली सुचारू रूप से ट्रांसमिट होती रही। लम्बी अवधि से खराब पड़े ट्रांसफॉर्मर को निर्धारित मानक बिजली मूल्यों पर पुनः लाने के लिए इसकी तकनीकी मुरम्मत साइट पर न होकर उत्पादक फैक्ट्री में होनी चाहिए थी। उसकी साइट पर ही रिपेयर कर दी गई। ट्रांसफॉर्मर को साइट पर ही किसी देसी फर्म से मुरम्मत करवाकर चालू कर दिया। साइट पर रिपेयर करवा लेना और जिस दिन 22 के0वी0 बिजली भूमिगत पावर हाउस से दी गई उसी दिन इस हादसे को होना था। प्रदेश विद्युत बोर्ड को लगभग 75 करोड़ रुपये के नये इक्विपमैंट और 3.50 करोड़ रुपये का जनरेशन लॉस हुआ है। जांच के दौरान लीपापोती की गई है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जांच की गई है वह ठीक नहीं हुई है। इसकी लापरवाही का निर्णय न तो किसी अधिकारी / इनक्वायरी प्रबंधन पर लिया गया कि किस की लापरवाही से हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब इसकी रिपेयर मैनुफैक्चरिंग कम्पनी में होनी चाहिए थी तो साइट पर देसी / स्थानीय फर्म से क्यों करवाई गई? फिर उसको बिना प्रोपर टैस्टिंग के चालू कर दिया जिसके कारण मुझे लगता है कि वह प्रोजैक्ट

1.3.2016/1445/av/ag/3

अभी भी चालू नहीं हुआ। उसको एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया।

श्री टीसी द्वारा जारी

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ---- जारी

मुझे लगता है कि वह जनवरी, 2015 से खराब हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से चुनाव घोषणा पत्र पर आ रहा हूं । आपने कहा कि आपने नये स्कूल खोले हैं, अपग्रेड किए हैं और 878 टीचर्ज़ की पोस्टें सैंक्शन की है। आपके 6000 से ज्यादा टीचर्ज़ प्रतिवर्ष रिटायर होते है। आप 878 पोस्टें सैंक्शन कर रहे हैं तो नये स्कूलों, अपग्रेडिड स्कूलों, प्राईमरी स्कूलों, मिडल स्कूलों, हाई स्कूलों और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को यदि 4-4 का स्टॉफ भी देना होगा तो 878 से ज्यादा तो उनकी ही संख्या बनती है। इसके अलावा 6000 टीचर्ज रिटायर हो रहे हैं। फिर वह कहां से पूरे होगें। आपने अपने चुनाव घोषण पत्र के पेज़-23 में लिखा है- सभी सरकारी, बोर्डों, निगमों और डिर्पाटमेंट्स में हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाएगा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हर किस्म की भर्तियां होती रहती है। कोई प्रमोशन पर जाते रहते हैं। Thousands of figures have been included.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आपने इस बहस का उत्तर देना है, तब तक इन्तजार करें। पेज़-23 राज्य के ऐसे बेरोज़गार 10+2 व स्नातक युवाओं, जिनकी परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोत्रों से दो लाख रूपये तक है, उनको 1000/- रूपये प्रतिमाह बेरोज़गार भत्ता दिया जाएगा। विशेष विकलांग बेरोज़गार स्नातकों को बेरोज़गारी भत्ते के रूप में 1500/- रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसलिए यह वायदा आपके चुनाव घोषण-पत्र का सबसे Important था। एक भी नौज़वान को आपने बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया है। यदि आपने किसी को सबसे ज्यादा ठगा है, तो हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार पीढ़ी को ठगा है। एकल नारी का हमारी सरकार के समय में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और हमने सैपरेट राशन कार्ड व अन्य सारी सुविधाएं उनको दी थी। उसी का जिग़र आपने अपनी उपलब्धियों में कर दिया, जो पांच साल पहले हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, पैरा न0 30

में महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, जब लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा होगी तो आप देखिएगा कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। महिलाओं के अंगेस्ट अपराध पहले की अपेक्षा बड़े हैं।

01.03.2016/1450/TCV/AS /2

सिरमौर जिले में दो वारदातों का ज़िगर 22 फरवरी की अखबारों में हुआ है-गर्भवती महिला और नाबालिक से गैंगरेप। समाज विरोधी तत्व के हौंसलें इतने बढ़ गये हैं कि वे कुछ भी करने को तैयार है। महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बच्ची के पैदा होने से पहले जो गर्भ में सैक्स डिटर्मीनेशन टैस्ट होता है, उसके बारे में जरा गम्भीरता से सोचें। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से भी रिपोर्ट ले और सी0आई0डी0 से भी रिपोर्ट लें ।

श्री आर0के0एस0--- द्वारा जारी ।

01.03.2016/1455/RKS/AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल.....जारी

बहुत सारे प्राईवेट हास्पिटल में यह धंधा अब भी चल रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी कहा गया कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमने महिलाओं का अलग से ग्रामसभा करने का प्रावधान किया है। माननीय मंत्री जी को पता होगी कि जो आम ग्राम सभा होती है , उसमें भी कॉरम पूरा नहीं होता है। न वन थर्ड होता है, न वन फोरथ होता है। इसलिए महिलाओं की ग्राम सभा में कितनी महिलाएं आ पाएंगी Let's be practical. इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। केवल घोषणा के लिए कुछ बातें लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि जो मूवर और सैकेंडर थे उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसके समर्थन में आवाज उठाए। इसलिए वे समर्थन ढूंढने के लिए कभी जे.एन.यू. पहुंच गए, कभी

हरियाणा, कभी जम्मू-कश्मीर तो कभी पंजाब। यह उनकी अपनी सोच है। जो उन्होंने कहा, वह उनको मुबारिक। लेकिन जब वे बोल रहे थे तो स्पष्ट लग रहा था कि दिल में उनके कुछ ओर है, बोलना कुछ ओर पड़ रहा है। (पक्ष की ओर से, 'क्या बात है'।) अभी तो शेयर बोलूंगा तब बोलना क्या बात है। आप तो पहले ही बोल दिए।

नजर उनकी जुबां उनकी, नजर उनकी जुबां उनकी,

ताज्जुब यह है कि नजर कुछ ओर कहती है, जुबां कुछ ओर कहती है।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया और माननीय राज्यपाल महोदय ने पहले ही बता दिया, कि असली बात क्या है? इसलिए बोलने के समय के लिए आपको धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि सरकार ने जो-जो गलत रिपोर्टिंग की है, उसको ठीक करेगी और अपने उत्तर में जिन बातों में कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उन पर कार्रवाई भी करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

01.03.2016/1455/RKS/AS/2

मुख्य मंत्रीः श्री राकेश कालिया जी को बोलने दीजिए।

श्री राकेश कालियाः नजर उनकी जुबां उनकी, मैं किसको मोहतवर समझूं,

नजर कुछ और कहती है, जुबां कुछ और कहती है।

अध्यक्षः राकेश कालिया जी, बोलिए। लाइट ऑन कीजिए। कालिया जी का स्पीकर ऑन कीजिए। आप दोबारा बोलिए।

श्री राकेश कालियाः

नजर उनकी जुबां उनकी, मैं किसको मोहतवर समझूं,

नजर कुछ और कहती है, जुबां कुछ और कहती है।

अध्यक्षः श्री धूमल जी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मैं श्री राकेश कालिया का बहुत धन्यवादी हूं कि इन्होंने मेरी बात का समर्थन किया, मैं भी यही कह रहा हूं।

अध्यक्षः श्री कुलदीप कुमार जी, be brief and speak within short time.

01.03.2016/1455/RKS/AS/3

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी का जो महामहिम गवर्नर सहिब का अभिभाषण था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री जगजीवन पाल ने रखा और श्री अजय महाजन जी ने उसको अनुमोदित किया । आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने आपको इस धन्यवाद प्रस्ताव पर शामिल करता हूं। सबसे पहले जैसा कि माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि ये जो अभिभाषण होता है, सरकार की कारगुजारी के ऊपर होता है। ये सारा भाषण सरकार की पिछली कारगुजारी को दर्शाता है।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

01.03.2016/1500/SLS-AG-1

श्री कुलदीप कुमार ...जारी

लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया कि महामहिम राज्यपाल जो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने जो एक श्लोक पढ़कर पूरी मानवता के लिए संदेश दिया था, जिसमें शायद बीजेपी भी आती है और यह श्लोक मानवता के लिए था। वह विद्वान व्यक्ति हैं और मानवता को उन्होंने असत्य से सत्य की ओर ले चलने की बात कही थी। उनकी बात को भी अपनी सूइटेबिलिटी के अनुसार हम ट्विस्ट करें तो यह ठीक बात नहीं होगी। न ही यह महामहिम की भावना के अनुरूप होगा और न ही उनको इस सब के बीच में लाना

सही होगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी का जितना राजनीतिक तजुर्बा है उतनी शायद कई माननीय सदस्यों की तो उम्र भी नहीं होगी। आप छठी बार हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री बने हैं। इसी तजुर्बे का हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ मिला है और प्रदेश आगे बढ़ा है। आज हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गाथा लिखी जा रही है और जो पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का नाम विकास में गिना जाता है यह माननीय मुख्य मंत्री जी के लंबे राजनीतिक तजुर्बे का ही परिणाम है जिसका लाभ प्रदेश और यहां की जनता को हुआ है। जब हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र को एक सरकारी दस्तावेज बनाया गया और एक कमेटी बनाई ताकि उसकी इंपलीमैंटेशन हो। विपक्ष के नेता हमारे चुनाव घोषणा-पत्र का विरोध कर रहे थे। लेकिन इन्होंने एक बात नहीं पढ़ी। इसमें लिखा है - लगभग। लगभग में पूरा समय नहीं आता। अभी हमारे दो साल पड़े हैं और हमने लगभग सभी चुनावी घोषणा वायदे पूरे किए हैं। जो बाकी रह गए हैं उनको भी पूरा करेंगे। इसलिए महज एक आलोचना के लिए आप आलोचना कर रहे हैं। उसमें भी मैं देख रहा था और पढ़ रहा था कि माननीय विपक्ष के नेता जी ने सिर्फ़ एक-दो बातें निकाली कि यह घोषणाएं पूरी नहीं हुई। लेकिन अभी सरकार का समय बचा है। जो घोषणाएं बची हैं वह भी पूरी होंगी। अभिभाषण में लिखा है, मैं पढ़ कर सुनाता हूं - 'क्योंकि मेरी सरकार ने लगभग सभी चुनावी वायदों को पूरा कर लिया

01.03.2016/1500/SLS-AG-2

है।' लेकिन आपने समझ लिया कि सभी वायदे पूरे कर दिए हैं। महज एक आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें प्रमाण-पत्र केवल जनता देती है। जनता के लिए काम होता है जिसे सरकार करती है, चाहे वह भलाई की बातें हों, विकास की बातें हों, स्कूल खोलने की बातें हों या कोई और बात हो।

जारी ...गर्ग जी

श्री कुलदीप कुमार-----**क्रमागत**

उसका प्रमाण-पत्र जनता देती है। अभी हाल ही में पंचायतों के चुनाव हुए और उनमें जनता ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। अध्यक्ष महोदय, लगभग 70% पंचायतों में कांग्रेस पार्टी जीतकर आगे आई है।----(व्यवधान)----हम 77% कर देते हैं उसमें क्या है। आप सुनने की क्षमता तो रखो, आप तो सुनते ही नहीं हैं। उसमें 6 न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ----(व्यवधान)---

अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री कुलदीप कुमार : जनता जब एक सरकार के कार्यकलापों को सटिफिकेट चुनाव के जरिए देती है, यही एक प्रमाण-पत्र होता है। पंचायत चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी को यह एक अभूतपूर्व सफलता दी है। वह जनता का सरकार के प्रति एक सर्टिफिकेट है। माननीय विपक्ष के नेता ने पंचायती चुनावों में कुछ छुटपुट घटनाओं की बात की। यह इतना बड़ा प्रदेश है और ये भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं।

(श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति पदासीन हुए)

इतने बड़े प्रदेश में इतने बड़े चुनाव कराने के लिए कुछ कुछ छुटपुट घटनाएं होना एक आम बात है और ये इनके कार्यकाल में भी होती रही होंगी। लेकिन महज इन छुटपुट घटनाओं से यह नहीं कह सकते कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं यहां सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि पिछले तीन साल एक अभूतपूर्व सफलता के रहे हैं और जनता ने जो सर्टिफिकेट चुनावों में दिया है और अभूतपूर्व सफलता पंचायतों के चुनावों में दी है उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। ---(व्यवधान)--तभी तो आपको तकलीफ हो रही है। लोक सभा में आज आप चुनाव करा लें, आपका चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। आप अभी चुनाव कराकर देखो, आप केन्द्रीय सरकार को जाकर कहो कि अभी चुनाव कराओ तब आपको पता लग जाएगा। आपके कार्यकलापों से जनता रो रही है जो वह गलती कर

बैठी है। आपने लोक सभा की बात की। जब से एन.डी.ए. की सरकार आई, एन.डी.ए. सरकार आने के बाद महगाई से देश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। यहां तक कि दाल एक गरीब का खाना होता है और

01/03/2016/1505/RG/DC/2

वह एक दाल के ऊपर अपना गुजारा करता है। अपने परिवार की वह उससे रोटी-रोजी चलाता है। लेकिन दाल भी आपने 200/-रुपये प्रति किलो तक पहुंचा दी और गरीब से आपने रोटी भी छीन ली।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का आभारी हूं जहां पूरे देश में महंगाई से त्राहि-त्राहि हो रही है यहां जो सस्ते राशन की योजना प्रदेश में इन्होंने चलाई और प्रदेश की जनता को ऐसी कोई परेशानी नहीं आने दी। आज प्रदेश की जनता राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करती है कि हमें सस्ता राशन उपलब्ध हो रहा है और इनकी महंगाई की मार हमारे प्रदेश के ऊपर नहीं पड़ी है। इसके अंतर्गत लगभग 18,27,900 कार्ड होल्डर्ज हैं, सबको प्रदेश में सस्ता राशन मिल रहा है और यह एक अच्छी सरकार की जनहित की योजना के अन्तर्गत आता है। क्योंकि इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बांटना जानते हैं। आप जाकर देखिए, हर जगह हम जाते थे। जब गांवों में जाते थे, तो बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग माताएं आती थीं और कहती थीं कि हमें कोई पेंशन लगवा दो। लेकिन आप कहते थे कि पटवारी से लिखवाकर लाओ और पटवारी लिखकर नहीं देता था। वह कहता था कि आपके बेटे नौकरी करते हैं,

एम.एस. द्वारा जारी

01/03/2016/1510/MS/AG/1

श्री कुलदीप कुमार जारी--------

आपका बेटा मनरेगा में है इसलिए उनकी इन्कम उतनी नहीं बनती थी। वे दर-दर की ठोकरें और धक्के खाते थे। आज हम राजा वीरभद्र सिंह जी के आभारी हैं कि इन्होंने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को इन्कम सर्टिफिकेट में छूट दी है। -(व्यवधान)- अभी मैं इंटीरियर के एक गांव में गया था। वहां मैंने अपने भाषण में बताया कि ऐसे-ऐसे

सरकार ने 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को इन्कम सर्टिफिकेट से छूट दे दी है और उनको पैंशन लग जाएगी। उनको पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं धाम में बैठकर खाना खा रहा था तो मेरे से थोड़ी ही दूरी पर तीन-चार बुजुर्ग आपस में पहाड़ी भाषा में बातें कर रहे थे कि अब तो पैंशन लग ही जाएगी क्योंकि ऐसा बोला है कि 80 साल से ऊपर की उम्र वालों को इन्कम सर्टिफिकेट के लिए पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। *("हूण तो पैंशन लगी जाणी है बोल्या तो है के 80 साला ते ऊपर इन्कम वास्ते पटवारी के व्हाल जाणे दी जरूरत ही नहीं पाउणी।)* मैं सुन रहा था। यह होती है बात। यह होती है जनहित की योजना। आप क्यों नहीं कर पाए? आपके पास तो अच्छी बात को भी अच्छा कहने का जिगर नहीं है। इसके साथ-साथ जो सामाजिक सुरक्षा पैंशन पहले 450 रुपये थी उसको 600 रुपये किया और जो 80 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग हैं उनको 1100 रुपया यह पैंशन की गई है। जो 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले हैं उनको भी 1100 रुपये पैंशन की है। इसके साथ-साथ जो इन्कम की बड़ी तकलीफ आती थी उसको 35000 रुपया स्लैब किया है उससे भी बहुत लोगों को राहत मिली है। इसके तहत 3,99,921 पात्र लोगों को सरकार पैंशन दे रही है। -(व्यवधान)- ठीक किया जो आप लोगों ने याद करवा दिया। आप लोगों ने पैंशन बंद की हुई थी। हम मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं कि इतनी पैंशन रिलीज हुई है कि हर पंचायत में 400-500 लोगों को अब पैंशन दिलवाई गई है। -(व्यवधान)- सामाजिक सुरक्षा पैंशन और विधवा पैंशन जो पैंडिंग थी उसको रिलीज किया है। -(व्यवधान)- हम झूठ पर बात नहीं करते। सुनने का मादा रखो। -(व्यवधान)- आप मेरे पास आ जाना, मैं सब पंचायतों की गिनती करवा दूंगा।

01/03/2016/1510/MS/AG/2

पिछले साल जो आवास निर्माण की बात आई तो पहले 48000/- रुपये मकान बनाने के लिए मिलते थे और अब सरकार ने उसको 75000 रुपये किया है। उसके बाद रिपेयर के लिए 25000/- रुपये किया और 3080 पात्र लोगों को इसका फायदा मिला।

इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए इस साल 375 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और शिक्षा में भी अभूतपूर्व तरक्की हुई है। परन्तु आपके समय में क्या हुआ? आपने धड़ाधड़ विश्वविद्यालय खोले। एक ही जिले में 20 विश्वविद्यालय खोल दिए। शिक्षा की दुकानें खोल दीं जबकि हमने स्कूल खोले।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि इंटीरियर एरिया में चाहे पांच बच्चे होंगे, वहां भी प्राथमिक पाठशाला खोली जाएगी और हमने 21 प्राथमिक पाठशालाएं खोलीं। -(व्यवधान)- 49 प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशाला बनाया और 58 उच्च पाठशाला को जमा-दो का दर्जा दिया और सात नये कॉलेज खोले गए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

01.03.2016/1515/जेएस/एजी/1

श्री कुलदीप कुमारः---------**जारी**-------

6 नई आई0टी0आई0 खोली गई। इसके अलावा ॥T और ॥M भी खोले गए। आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे संस्थान हमारे यहां पर खुले हैं। इसी के साथ-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे इलाके में और आपके विधायक उसके 25 साल तक एम0एल0ए0 रहे हैं, चौकीमिनार यानि कुटलैहड़ के। वे एक कॉलेज भी नहीं खुलवा सके। चौकीमिनार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कॉलेज दिया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि वह इंटिरियर इलाका है जो कि जंगली इलाका है। आप मना करो और यहां पर उठ कर बोलो। वह एक जंगली इलाका है। यह इनकी एक हताशा को बताता है। जो वहां पर कॉलेज दिया गया है और वह जंगली इलाका है। वहां से 35 किलो मीटर बंगाणा पड़ता था, 35 किलो मीटर अम्ब पड़ता था और 35 किलो मीटर ऊना पड़ता था। वहां पर लड़कियों के लिए दिक्कत आती थी। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अगले साल से वहां पर क्लासिज बिठाने का फैसला लिया है। उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है। इसके साथ-साथ जैसा कि बताया गया कि 878 पद टीचर्ज के सृजित किए गए। यहां पर माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि ये कम है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पी0टी0ए0 में जो टीचर्ज थे उनको कान्ट्रेक्चुअल पॉलिसी में कॉन्ट्रेक्ट के ऊपर लेने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। पी0टी0ए0 के जो टीचर्ज हैं उनको कॉन्ट्रेक्ट में लिया गया। मैं यहां पर सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ लोग जो पी0टी0ए0 में थोड़े-बहुत रहते हैं,

जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाल दिया था और उनको पी0टी0ए0 पॉलिसी 2006 के अन्तर्गत रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया। वह जो गैप पड़ा उसमें उनकी सर्विस काऊंट नहीं हो रही है। कोर्ट का उनकी फेवर में फैसला आया है। उनकी फेवर में भी काम किया जाए ताकि उनको भी फायदा हो। गुणात्मक सुधार के लिए हमारी सरकार ने राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन करने का फैसला लिया।

01.03.2016/1515/जेएस/एजी/2

इसी तरह से हैल्थ सेक्टर में भी बहुत सारा विकास हुआ है, जिसमें 8 नये सिविल हॉस्पिटल, उसमें हमारे अम्ब का सिविल हॉस्पिटल बना है। जिसका उदघाटन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया और मैं इनका धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ-साथ 16 पी0एच0सीज0 खोली गई, 4 नये सब सेन्टर्ज खोले गए, 3 मेडिकल कॉलेज खोले गए। इसी के साथ-साथ मैं इसका भी धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अम्ब में सिविल हॉस्पिटल और चैक्सराय में एक पी0एच0सी0 भी दी तथा उसका पैसा भी साथ-साथ दिया। 8 करोड़ सिविल हॉस्पिटल के लिए और जो पी0एच0सी0 खोली है उसकी बिल्डिंग का काम भी जोरों से चला हुआ है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इसके साथ-साथ एस0सी0/एस0टी0 के समग्र विकास के लिए वर्ष 2015-16 में 1220.14 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया और 40 प्रतिशत से अधिक आबादी की जो वहां पर बस्तियां थी उनके लिए मुख्य मंत्री ग्रांम आदर्श योजना चलाई। हर बस्ति के लिए 10 लाख रूपया और हर पंचायत के लिए 10 लाख रूपया रखा गया। इसमें स्वच्छ पेयजल योजना के तहत 1332 बस्तियों को पानी दिया गया। 16,881 हेण्डपम्प लगाए गए। मैं खास करके यह कहना चाहता हूं कि फ्लड प्रोटैक्शन डिविजन ऊना जिला में 922 करोड़ का पूरे भारत वर्ष में सबसे बड़ा प्रोजैक्ट वहां के लिए सरकार

ने दिया है । उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज हालात यह हो गई है कि किसानों की जमीनें वहां पर जो प्रोक्लेम हुई है .....(व्यवधान).....

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

01.03.2016/1520/SS-AG/1

सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री कुलदीप कुमारः सभापति महोदय, अभी तो मैं शुरू ही हुआ हूं। थोड़ा समय दे दीजिए।

सभापतिः आपका समय अधिक हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जितना समय निर्धारित किया है उससे दुगुना समय आपको दे दिया है।

श्री कुलदीप कुमारः सभापति महोदय, 922 करोड़ रुपये की जो बात है, आज चैनेलाइजेशन से किसानों की जो जमीन है वह सैंकड़ों एकड़ रिक्लेम हुई है। लेकिन आज सैंटर गवर्नमैंट ने पैसा बंद कर दिया है और उससे काम रूक गया है। मैं माननीय विपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं जाकर केन्द्र सरकार से बात उठाएं और इसका पैसा रिलीज हो ताकि बाकी बचा हुआ काम पूरा हो सके।

इसी तरह से सड़कों की और दूसरे डिपार्टमैंटस की बातें हुई हैं। बहुत अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसमें मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस का एक ही नारा है - *"काम किया है, काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे"।* आपने झूठे वायदे किये हैं। आपने लोक सभा के चुनावों में एक वायदा किया था कि सब का विकास, सब का साथ। अब 420 दिन व्यतीत हो गए हैं और हिन्दुस्तान की जनता को पता लग गया है कि आप कितना विकास कर रहे हैं। आप सिर्फ एक बात में माहिर हैं - डिवाइड एंड रूल। आज देश की बुरी हालत है। इससे आज जनता पछता रही है। जो आपने वायदे किये थे वे झूठे थे। न वह 15 लाख रुपया मिला और न ही अच्छे दिन आए। महंगाई की मार है और कोई सुनने वाला नहीं है। कल जगजीवन पाल जी बोल रहे थे। एक और हमारे ओ0बी0सी0 के एक बड़े सीनियर लीडर हैं। आप उसके (श्री जगजीवन पाल जी) ऊपर इतना टूट पड़े कि सारे खड़े हो गए।

इससे बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है कि आप ओ0बी0सी0 और शिडयूल्ड कास्ट्स के विरोधी हैं। यह आपका एक चेहरा सामने आता है। हैदराबाद में क्या हुआ? रोहित बेमुला को आप लोगों ने खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। आज सारा हिन्दुस्तान आपकी कलई खोल रहा है कि वह एक शिडयूल्ड कास्ट जो था उसको खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। हैदराबाद में वह एक स्कॉलर था और उसको मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी।

01.03.2016/1520/SS-AG/2

इसके साथ-साथ एक बात और है। आपकी एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट ले रखा है देशभक्त बनाने का। देशभक्ति के सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। कल भी यहां पर बात उठी। हम सब देशभक्त हैं। आपसे ज्यादा देशभक्त हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। आपने कहां से सर्टिफिकेट देने? लेकिन आपकी एक बात है, आपको एक ही बात सिखाई गई है कि जो आपकी विचारधारा से एग्री नहीं होता, आपकी विचारधारा से अलग विचारधारा रखता है उसको आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट देते हैं। यह आपके लिये ठीक बात नहीं है। यह देश की बात है। आप किसी और की बात नहीं सुन सकते। आज आपने राहुल गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया। आनन्द शर्मा जी के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया। किसी और को नहीं छोड़ा। केजरीवाल के ऊपर भी देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया। आप चाहते क्या हैं? जो आपके विरोधी हैं आप उनको चुप कराना चाहते हैं। उनको दबाना चाहते हैं। इसी तरह से आप जगजीवन पाल जी को दबा रहे थे। आपको सीखना चाहिए। हम आदर करते हैं --(व्यवधान)--आप सुनिये, आपको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए, जिनका हम सभी आदर करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि वे मेरे बड़े खास दोस्तों में से हैं। उन्होंने एक बार पार्लियामैंट में कहा था कि सरकारें आती हैं, जाती हैं --(व्यवधान)

जारी श्रीमती के0एस0

01.03.2016/1525/केएस/एएस/1

श्री कुलदीप कुमारी जारी----

सरकारें आती है, जाती है लेकिन ये देश रहना चाहिए लेकिन आपने उनसे कुछ नहीं सीखा न आप देश के बारे में सोच रहे हैं । आज देश तोड़ने की बातें हो रही है। कृपया आप हिन्दुस्तान को बचाने की बात करिए। जो उन्होंने कहा है कि अपना राज धर्म निभाएं तो राज धर्म निभाने की बात करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

01.03.2016/1525/केएस/एएस/2

सभापतिः अब माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री चर्चा में हस्तक्षेप करेंगें।

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रीः आदरणीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरे विभाग के बारे में कुछ बात हुई है इसलिए उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। ----(व्यवधान)---

Chief Minister: As a member he has right to speak.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः सभापति महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

सभापतिः माननीय मंत्री जी, कृपया आप बैठ जाएं क्योंकि माननीय धूमल जी कुछ कहना चाहते हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः सभापति महोदय, अभी तो चर्चा प्रारम्भ हुई है और विपक्ष से केवल एक सदस्य बोला है। हर मंत्रालय के बारे में सवाल उठेंगें अगर हर स्पीकर के बाद हर मंत्री इस तरह स्पष्टीकरण देने लगेगा तो डिस्कशन के लिए कितना समय

मिलेगा? बाद में जब सारी डिस्कशन हो जाए तो जो-जो मंत्री जवाब देना चाहे, दें। सदन का समय बर्बाद न करें।

सभापतिः माननीय मंत्री जी, क्या आप बाद में बोलना चाहेंगें ? सभी लोगों के भाषण सुन लीजिए उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा।

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रीः सभापति जी, ठीक है।

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगें।

Chief Minister: You have called him to speak.

01.03.2016/1525/केएस/एएस/3

सभापतिः इन्होंने कहा कि मैं बाद में बोल लूंगा।

Chief Minister: Any minister can get up any time to take part in the debate. He is taking part in debate. He may talk about the department also. यह गलत बात है।I disagree with your ruling.

Chairman: I have allowed him and I have asked his name. But he has himself said that I will speak in the last; when all the members will speak after that he will speak. मंत्री जी, जब मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि बाद में ही बालूंगा। आप एक बार मान गए हैं।

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रीः सभापति जी, धूमल जी ने इस बात को कहा कि सभी डिस्कशन में भाग ले लें, बाद में जवाब देना । जवाब बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है।

सभापतिः हां तो इसके बाद आप बोलिए। You have right to speak.

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रीः सर, सभी के बारे में चर्चा कर लें उसके बाद बोल लेंगें।

सभापतिः जब सभी विभागों के बारे में चर्चा हो जाएगी तो आप बोल लेना। अब माननीय महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगें।

01.03.2016/1525/केएस/एएस/4

Chief Minister: I protest against your ruling.

श्री महेश्वर सिंहः सभापति महोदय, दिनांक 25 फरवरी को इस माननीय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके संदर्भ में इस सदन में माननीय सदस्य व सी.पी.एस. महोदय, जगजीवन पाल जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सभापतिः महेश्वर सिंह जी, कृपया रविन्द्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख का विषय है कि आपने जो व्यवस्था दी है, इस चेयर का सभी मान-सम्मान करते हैं और आपने जो व्यवस्था दी है, आपने मंत्री जी को भी पूछा, हम सभी ने भी अपनी बात रखी और आपकी रुलिंग आने के उपरांत पहले तो सदन के नेता की ओर से यह भी कहा गया कि यह कौन है? और दूसरे बाद में जब आपकी रुलिंग आ गई और मंत्री जी फिर बैठ गए तो ये कहने लगे कि मैं वाक आऊट करता हूं और बाहर चले गए यह तो सदन के नेता का चेयर के खिलाफ बयान है। यह चेयर का अपमान है। ----(व्यवधान)--- इस पर चेयर की रुलिंग आनी चाहिए।

सभापतिः नीरज भारती जी बैठ जाईए। ---(व्यवधान)---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

1.3.2016/1530/av/dc/1

सभापति (सुरेश भारद्वाज)----- जारी

मैं यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष की रूलिंग के लिए रखता हूं। अब माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी अपनी बात कंटिन्यू करेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : सभापति महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि दिनांक 25 फरवरी को जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में अभिभाषण दिया। यहां पर जिसका धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य और सी0पी0एस0 महोदय श्री जगजीवन पाल जी ने प्रस्तुत किया और अनुसमर्थन श्री अजय महाजन जी ने किया, मैं उस चर्चा में भाग लेने हेतु आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

अभिभाषण के आरम्भ में ही पैरा संख्या 2 में कहा गया कि इस बार जो स्थानीय निकायों एवं पंचायतों के चुनाव हुए हैं वह शांतिपूर्ण ढंग से पूरे हुए और उसके लिए जनमानस का धन्यवाद किया। निश्चित रूप से जनमानस ने शांति बनाये रखी और जिस शांति से चुनाव सम्पन्न हुए मैं उसके लिए मंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं। मगर आपके माध्यम से मतदाता सूची की कुछ सत्यता मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। पंचायतों की जो मतदाता सूचियां बनती हैं उसका आधार क्या होता है? उसका आधार परिवार रजिस्टर होता है। जो हाउस टैक्स नहीं देता, जो उस परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है वह वहां का मतदाता नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आरोप प्रदेश के चुनाव आयोग पर लगा रहा हूं। उन्होंने क्या देखा? लोगों के थोक में नाम काट दिए और जो परिवार रजिस्टर में है वह कई जगह वोटर लिस्ट में नहीं है। कई लोगों ने अपने फॉर्म भरकर वोट बनाए, ऐसे लोगों के वोट बन गए जो यू.पी. और बिहार से आए हैं और लेबर का काम करते हैं। क्या वे उस ग्राम सभा के सदस्य हैं? उन्होंने चुनाव का सारा गणित बिगाड़ दिया। यहां तक कि कई सम्भावित प्रत्याशी, जिन्होंने चुनाव लड़ना था

1.3.2016/1530/av/dc/2

उनका भी मतदाता सूचियों में नाम नहीं था, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। जहां तक शहरी क्षेत्र का सम्बंध है उसमें मतदाता कौन हो; इसके लिए गाइड लाइन्ज होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो किरायेदार है वह मतदाता होता है। लेकिन एक-एक घर में 30-30 मतदाता दर्शाए गए और देखा जाए तो इसकी फिर फिजिकल वैरिफिकेशन होती थी। इसकी एस0डी0एम0 महोदय के माध्यम से फिजिकल वैरिफिकेशन होती है। क्या वह वैरिफिकेशन की गई? कोई वैरिफिकेशन नहीं हुई और वे वोटर निर्णायक सिद्ध हो गये जो यू0पी0, बिहार या अन्य किसी प्रदेश से आए हैं तथा लेबर का काम करते हैं। उनको विकास से क्या लेना-देना है? वे वोट किधर देते हैं, यह सब जानते हैं और अब आने वाले समय में आपके धर्मशाला नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। मैं आसन से आग्रह करूंगा कि चुनाव आयोग को इस प्रकार के निर्देश जाएं कि कम-से-कम अब वह ठीक तरीके से मतदाता सूचियों को देखें। अब ऐसी गड़बड़ होने की ज्यादा आशंका है। अब ज्यादा आशंका इसलिए है क्योंकि हमारे हाथों की स्याही भी मिट गई है। जो गांव या अन्य जगह वोट दे चुके हैं वे भी अब वहां जाकर दर्ज हो जायेंगे। निश्चित रूप से एक व्यक्ति को दो जगह वोट देने का अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करे, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव होते हैं। वोट बनाने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया, जिन्होंने घर बैठकर वोट बनाए। अब ये सारी मतदाता सूचियां चैक होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए गाइड लाइन्ज होनी चाहिए कि मतदाता कौन होना चाहिए। पैरा संख्या 4 में सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है।

श्री टीसी द्वारा जारी

01.03.2016/1535/TCV/DC /1

श्री महेश्वर सिंह ---- जारी

निश्चित रूप से संख्या में वृद्धि हुई है, अच्छा काम हुआ है। मैं उसकी आलोचना नहीं

करूंगा। लोगों को पैंशन लगी है और 80 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को पैंशन देना, यह सचमुच एक सामाजिक सेवा का काम है। यह हुआ है। लेकिन क्या जो भोला-भाल आदमी गांव में 80 साल की आयु से ऊपर का हैं, क्या उसको पैंशन लग गई है? क्या उसको इसकी जानकारी है? आखिर जानकारी कौन देगा? आपके जिला का वैलफेयर ऑफिसर, आपके जिला का कल्याण ऑफिसर। इनकी ड्यूटी लगाईये, इनको ग्राम सभा में जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को स्मरण करवाना चाहूंगा कि परिवार की परिभाषा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में परिवार उसको माना जाता है, जिसका परिवार अलग हो जाता है। लेकिन आपके विभाग ने एक फॉर्म भेजा है। उसमें लिखा है कि अगर परिवार बंट भी गया है, भले ही बाप का बेटा मर गया हो, पोता अलग से शादी करके बैठा हो, उसकी इन्कम भी क्लब कर दें ताकि बूढ़े उस आदमी को पेंशन न लग सके। आपने आश्वासन दिया था कि आप इसमें सुधार लाएंगे। जो परिवार अलग लिखा गया है, उसकी इन्कम क्लब नहीं होगी। उस आश्वासन की पूर्ति गांव में बैठा बूढ़ा व्यक्ति आपकी तरफ़ नज़र लगाये इंतजार कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आप इस बार ऐसे निर्देश देंगे। महोदय एक बात और है। आखिर इस पेंशन का आधार क्या है? इसका आधार है आय । यह ठीक है पहले 18000/- रूपये थी। आपसे आग्रह किया और आपने इसी मान्य सदन में उसे बढ़ाकर 34000/-रूपये कर दिया। लेकिन एक चीज़ देखता हूं, जैसे विधी माता का लेख कभी नहीं मिटता, अगर धरती पर कोई विधी माता का अवतार है तो आपका पटवारी है। जो वह लिख देगा वह धर्म सत्य है, उसको कोई नहीं काट सकता। कुछ पटवारी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन अधिकांश जगह जब पटवारी सर्टिफिकेट देता है, तो यह नहीं देखता कि भूमि के अतिरिक्त वह क्या व्यवसाय करता है। कहीं दुकानदारी तो नहीं करता, कहीं उसके पास ट्रक तो नहीं है, कहीं उसके पास कोई गाड़ी तो नहीं है, अन्य आय के स्रोत तो नहीं है। पटवारी केवल और

01.03.2016/1535/TCV/DC /2

केवल उसकी भूमि और उसके मकान देखकर सर्टिफिकेट देता है और इन्कम बढ़-चढ़ कर लिखा देता है। फलस्वरूप पात्र लोगों को पैंशन नहीं मिलती है। जब हम शिकायत करते हैं, तहसीदार को कहते हैं, तो वह कहता है कि यह काम तो पटवारी का ही है, वही ठीक करेगा। क्या उस पर कोई अंकुश नहीं लग सकता है? क्या उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती? अब आपने कहा है कि पंचायतें अलग दिनों में ग्राम सभाएं करेगी। इसलिए सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम सभा में पटवारी और तहसील कल्याण अधिकारी जायें। ताकि जनता के सामने आई0आर0डी0पी0 परिवार का चयन हो। ऐसे-ऐसे परिवार चयनित हो जाते हैं, जो ट्रक के मालिक हैं, उदाहरण दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और ऐसे रह जाते हैं, जिनके पास दो टाईम की रोटी भी नहीं है और झोंपड़ी में रहते हैं। इसको दूर करना है तो ग्राम सभा में पटवारी का जाना अनिवार्य होना चाहिए। ग्राम सभा में ज़िल्द लेकर जाये और उसी दिन इन्कम सर्टिफिकेट दें। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? अगर ऐसा करेंगे तो ये सारी चोर-बाजारी, ये गोरख-धंधा समाप्त होगा। अन्यथा ये समाप्त नहीं हो सकता है। पटवारी मासिक बैठक में तहसील में बुलाए जाते हैं। क्या इनके लिए कोई गाईड लाईन्ज इनको नहीं दी जा सकती है और उस गाईड लाईन्ज़ के आधार पर ये सर्टिफिकेट दें। ये तभी संभव हो सकता है, जब आपके निर्देश डी0सी0 के माध्यम से एस0डी0एम0 तक जाये। ताकि इनको ट्रेनिंग दी जाये, गाईड लाईन्ज़ दी जाये। महोदय शिक्षा के क्षेत्र के बारे में पैरा-11,12,13,14 और 15 के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कोई दो राय नहीं । स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

01.03.2016/1540/RKS/DC/1

श्री महेश्वर सिंह...क्रमागतः

3 वर्षों में निश्चित रूप से संख्या में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खुले, इस बात का

हम स्वागत करते हैं। लेकिन आखिर स्कूलों की हालत क्या है? कहा गया है कि इस वर्ष में ही 21 नए प्राथमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत करके 49 माध्यमिक पाठशालाएं बनाई गई। 92 माध्यमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत करके उच्च माध्यमिक पाठशालाएं बनाई गई और 98 उच्च माध्यमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत करके वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाई गई। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टाफ कितना दिया गया? क्या पोस्टें क्रेट हो गई? इस अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि इतने अध्यापकों की भर्ती की गई। निश्चित रूप से पी.टी.ए. टीचर भी रेग्यूलराइज हुए। मैं यह भी मानता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में टीचर इम्पलॉय भी हुए और बाकियों को रेग्यूलराइज भी किया गया। क्या यह सत्यता नहीं है कि जितने स्कूल खोले, उस अनुपात में अभी भी अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी है। सिंगल टीचर स्कूल कितने हैं। मेरे छोटे से जिले में जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, वहां पर भी 45 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर के रहमोकर्म पर चलते हैं। शिक्षा विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है। यहां शिक्षा विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। एक फरमान इश्यू कर दिया कि मिडल स्कूल में एक ही स्नातक होना चाहिए। क्योंकि कमी है। यह या तो साईंस विषय का ग्रेजूऐट होगा या आर्टस का। फिर ऐसे अभ्यर्थि या स्टूडेंटस आगे जाकर इंटरव्यू में कैसे कम्पीट करेंगे। यहां वन मंत्री जी बैठे हैं, यह कहेंगे कि गार्ड तो वही भर्ती होगा जो साईंस पढ़ कर आएगा। जब साईंस का टीचर ही स्कूल में नहीं होगा तो वह कहां पढ़ेगा। यह कैसा फरमान है, मैं समझ नहीं पाया। हाई स्कूलों में भी वही हालत है। अगर प्लस टू स्कूल को ईमानदारी से चलाना हो तो कम से कम 15 अध्यापकों की आवश्यकता होती है। क्या सरकार ईमानदारी से कह सकती है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे स्कूल भी हैं, जहां 15 अध्यापक हों ? क्या ऐसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? जो कॉलेज खुले उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन स्टाफ का क्या हाल है? पीछे शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। कर्नल इंद्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छा निजी प्रस्ताव लाया था जिसके लिए मैं

01.03.2016/1540/RKS/DC/2

उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि आखिर हमारी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे क्यों गिर रहा है? क्यों 80 प्रतिशत अध्यापक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं? इस प्रकार शिक्षा का स्तरोन्नत कैसे होगा? वहां शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढेगी? इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इस पर अनुसरण होना चाहिए। मैं कुल्लू कॉलेज का उदाहरण दूंगा, जिसके आंकड़े मेरे पास है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूंगा। कहा गया कि पी.टी.ए. में भी भर्ती हो रही है। सत्यता यह है कि कुल्लू ब्लॉक में इन तीन वर्षों में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। आपके मनाली में हुए, आनी में हुए लेकिन कुल्लू में पी.टी. ए. के अंतर्गत कोई टीचर नहीं रखा गया। क्योंकि वहां पर साक्षात्कार हुआ ही नहीं। बल्कि पी.टी. ए. ने कई जगह प्रस्ताव दिया है। परिणाम यह है कि कई स्कूलों में रोटेशन में टीचर डिप्यूट किए जा रहे हैं। डेप्यूटेशन खत्म नहीं हुआ। मुझे याद है कि पिछले सत्र में डेप्यूटेशन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आज से ही यह लागू होगा कि किसी टीचर का डेप्यूटेशन नहीं होगा। हमनें उस बात का स्वागत किया। उस पर थोड़ी हरकत हुई। कुछ दिनों के बाद फिर ढाक के तीन पात। आज जिला में तो छोड़ दीजिए, अब इंटर डिस्ट्रिक डेप्यूटेशन जारी किया है। पता नहीं किसने ऐसे आदेश दे दिए। मैं इसका उदाहरण दूंगा। मेरे क्षेत्र दयार में सीनियर सकेंडरी स्कूल है। वहां का पी.टी.ए. 6 महीने से, वहां का जो पी.ई.टी. लगा है वह मण्डी जिला के खडलग स्कूल में है। वेतन कुल्लू जिला से खा रहा है और आनंद खडलग में ले रहा है। यह कैसा डेप्यूटेशन है? कई लाहौल से उठकर कुल्लू जिला में आए हैं

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

01.03.2016/1545/SLS-AG-1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

और वेतन ट्राइबल एरिया से आ रहा है। इस बात की छानबीन की जाए। जिसने मुख्य

मंत्री जी के आदेशों का उल्लंघन किया है उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक कॉलेजिज की बात है, इसमें कोई सवाल नहीं कि छोटी-सी अवधि में एक नहीं बल्कि 18 कॉलेज खुले हैं। 1911-12 में कुल्लू के कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 5000 थी और अध्यापक 82 थे। उसके बाद अब कितने कॉलेज खुले? गवर्नमैंट कॉलेज हरिपुर, उसमें स्टुडैंट्स 920 और अध्यापक 16 हैं जबकि 3 वैकैंसीज हैं। कहां से डिप्यूट किए? कुल्लू कॉलेज से 14 अध्यापक डिप्यूट किए गए। 14 अध्यापक हरिपुर पहुंच गए और कुल्लू को बदले में बाँसुरी मिली! उसके बाद बन्जार गवर्नमैंट कॉलेज है जिसमें स्टुडैंट 1060 हैं औंर अध्यापक 20 हैं तथा एक वेकैंसी है। इसमें कुल्लू से 12 टीचर गए। पनारसा में कॉलेज खुला। वहां से बच्चे पहले कुल्लू जाते थे। वहां बच्चों की संख्या 220 है और अध्यापक 6 हैं जबकि 2 वेकैंसीज हैं। उसके बाद यहीं से गाड़ा-गुसैणी के लिए बच्चे गए। वहां स्टुडैंट्स की संख्या 70 और अध्यापकों की 3 है। वह सब पी.टी.ए. पर हैं। कुकुमसेरी लाहौल में पड़ता है जबकि कुल्लू में ट्राइबल होस्टल है। अधिकांश स्टुडैंट वहीं पर हैं जबकि कुकुमसेरी में बच्चे 80 और अध्यापक 8 हैं। अब कुल्लू की हालत क्या होगी? वहां अभी भी विद्यार्थियों की संख्या 4460 है और जिस गति से माइग्रेशन हो रही है उससे अगले सैशन में वहां 5000 बच्चे हो जाएंगे। वहां टीचर्ज की संख्या 52 है। वहां से जो सारे विद्यार्थी गए, उनका भी मैंने जोड़ किया है जो 400 के लगभग बनता है। 400 अध्यापकों के लिए तो 3100 विद्यार्थी हो गए और कुल्लू खाली हो गया है। कुल्लू में 9 वेकैंसीज है। हमारी हालत तो ऐसी कर दी कि *'इक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा'* और सर्वनाश हो गया। क्या इस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? क्या शिक्षा इस तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगी? इस पर विचार करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नई शिक्षा नीति बनानी चाहिए ताकि शिक्षा में सुधार हो। अगर गुणवत्ता नहीं आएगी, तो जब हमारे स्टुडैंट इंटरव्यु में

01.03.2016/1545/SLS-AG-2

जाएंगे तो वह शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के साथ कैसे कंपीट करेंगे? यह चिंता का विषय है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अभिभाषण के पैरा 17 में स्वास्थ्य विभाग की चर्चा की गई है। मैं सर्वप्रथम तो सरकार और मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने कुल्लू अस्पताल में बैड्ज की संख्या 200 से 300 कर दी है। कोई भी ऐसा विषय नहीं था जिसमें आपने 3-3 डॉक्टर नहीं दिए। हमने ऐनेस्थिसिया का एक मांगा, आपने 3 दे दिए। लेकिन आपकी सूचना के लिए अब एक चला गया है और इस तरह एक घट गया। यह और न घटे क्योंकि वहां पर 9 वेकैंसीज हैं, उन्हें भर देना। उसके बाद तेगुबैड में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपकी अध्यक्षता में शिलान्यास किया । आपने 70 लाख रुपया दिया जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है, टैक्निकल सैंक्शन भी आ गई है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस काम को शुरू किया जाए। यहां डायलैसिज की बात माननीय धूमल जी ने कही।

Speaker: Hon'ble Member, you have been speaking for the last 20 minutes. 20 मिनट आपको चर्चा में भाग लेते हो गए। इस तरह कैसे काम चलेगा? अभी तो 10 सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री महेश्वर सिंह : सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। अभी पहली घंटी बजी और दूसरी बजने से पूर्व मैं समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष: मैं चाहता हूं कि अब आप समाप्त करें।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय के साथ समाप्त करूंगा और बाकी बातें बाद में करेंगे। एक नई स्कीम सरकार ने डायलैसिज के लिए दी है। यह पी.पी.पी. मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में है। उसमें कुल्लू के लिए अनुमति आई है।

जारी ...गर्ग जी

01/03/2016/1550/RG/AS/1

श्री महेश्वर सिंह-----क्रमागत

ै और संभवतया टैण्डर्ज होने हैं। कुल्लू में इस समय 80 रोगी हैं जोकि डायलैसिस के लिए गुटकर जाते हैं। उन्हें 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और हफ्ते में दो बार जाना पड़ता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करुंगा कि जल्दी-से-जल्दी वहां डायलैसिस का प्रबन्ध हो। क्योंकि कमरा भी बन गया है, सब कुछ तैयार है, यूनिट तैयार है, केवल ये टैण्डर्ज खुलेंगे, तो काम हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।

अध्यक्ष महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं एक शब्द कहूंगा कि कहीं ऑऊटसोर्सिंग होते-होते मध्य प्रदेश का 'व्यापम' न बन जाए। सरकार इसके लिए पुनर्विचार करे, कोई और तरीका अपनाए अन्यथा मार्केट कमेटी में जो इसमें ऊधम मचाया है वह किसी से छिपा नहीं है क्योंकि समय समाप्त हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं।

01/03/2016/1550/RG/AS/2

अध्यक्ष : अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे, तो अच्छी बात है।

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2016 को महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण यहां पर हुआ, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे तो जो इस पुस्तक में आया है, इस भाषण में न कोई सत्य है और न ही कोई तथ्यों पर आधारित इसमें बात कही गई है। वास्तविकता में भाई श्री

जगजीवन पाल जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव यहां रखा है, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनावों में 58% महिलाएं जीतकर आई हैं, लेकिन वे भूल गए कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी थे, उन्होंने उस समय महिलाओं के लिए यह आरक्षण दिया था। यहां यह भी कहा गया कि पंचायत के चुनावों में कई जगह गड़बड़ियां हुईं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक कोटापाप पंचायत पड़ती है जो बहुत दूर-दराज के क्षेत्र की पंचायत है। वहां पर चुनाव का परिणाम रात को 11.00 बजे वोटों की गिनती खत्म होती है जो पंचायत की प्रधान जीत रही थी उसका परिणाम रोका जाता है। उसके बाद सुबह तक परिणाम को रोका जाता है। सुबह 6.00 बजे तहसीलदार साहब वहां जाते हैं और वहां वोटों को बराबर किया जाता है और टाई में दूसरी पंचायत प्रधान को जिता दिया जाता है। इस तरह की धांधलियां भी इन पंचायत चुनावों में हुई हैं। माननीय धूमल ने कहा कि पंचायतों के प्रधानों की वित्तीय शक्तियों को छीना जा रहा है। ये चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों का उनके ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास होता है और विश्वास से लोग उनको चुनकर भेजते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जिस तरह प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है, आज सभी लोग चाहे कोई अधिकारी है या स्वयं शिक्षक है, सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में न पढ़कर निजी स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? उसका कारण यह है कि हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर गिर रहा है। अभी यहां जिक्र किया गया कि बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और प्लस टू स्कल खोले गए, लेकिन उनके लिए शिक्षकों का प्रावधान कहीं नहीं किया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत दूर-दराज के क्षेत्र हैं।

01/03/2016/1550/RG/AS/3

वहां अध्यापकों की बहुत कमी है। कई स्कूलों को डेपुटेशन पर चलाया जा रहा है, कहीं एक-एक अध्यापक के सहारे ही स्कूल चल रहा है। स्कूल शिक्षकों को भरने के लिए

सरकार ने एस.एम.सी. के माध्यम से एक योजना बनाई। उसके तहत आजकल मेरे चुनाव क्षेत्र में भी एस.एम.सी. के माध्यम से शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उनमें क्या हो रहा है कि जिस छात्र या छात्रा के ऐकैडैमी में 80 या 90% नंबर हैं उनको उसमें रखा नहीं जा रहा है और 50 या 55% नंबर वालों को उसमें भर्ती किया जा रहा है। उसका क्या कारण है? मेरे विधान सभा क्षेत्र में या शायद किसी विधान सभा क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति नहीं हो।

एम.एस. द्वारा जारी

01/03/2016/1555/MS/AG/1

श्री बलदेव सिंह तोमर जारी--------

माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो साल पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में एस0डी0एम0 कार्यालय खोला था। वहां दो साल से मात्र दो महीने तक दो एस0डी0एम0 रहे। एक-एक महीने के बाद उन दोनों एस0डी0एम्ज0 ने वहां से अपनी ट्रांसफर करवा ली और वहां पर उसी विधान सभा क्षेत्र से एक तहसीलदार लगे हुए हैं। उन तहसीलदार के पास एस0डी0एम0 का चार्ज भी है। जबकि किसी विधान सभा क्षेत्र का अधिकारी अपने क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकता है। लेकिन वह तहसीलदार पिछले दो-तीन साल से वहां कार्यरत्त है और एस0डी0एम0 का कार्याभार भी उनके ही पास है। जिस तरह से उन्होंने एस0एम0सी0 की भर्तियों में धांधलियां की हैं उससे पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोष है। इस तरह से उस एस0डी0एम0 कार्यालय को खोलने का भी क्या फायदा है? आप यहां पर संस्थान खोलने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे संस्थान आप लोगों ने खोल दिए हैं लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं है। जिस एस0डी0एम0 कार्यालय में दो साल से एस0डी0एम0 नहीं है, मात्र दो महीने के लिए एस0डी0एम0 आए, उस कार्यालय की क्या हालात होगी और जो स्थानीय तहसीलदार वहां लगा है उसके ही पास एस0डी0एम0 का चार्ज है जबकि एस0डी0एम0 अपने जिले में भी नौकरी नहीं कर सकता है। तो वहां पर किस तरह की एस0एम0सी0 की भर्तियां हुईं होंगी इसके ऊपर मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दें।

आपने कॉलेज भी बहुत सारे प्रदेश में खोले हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अभी

एक नया कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। लेकिन जहां पर पहले कॉलेज खुला है उसमें भी स्टाफ नहीं है और उसमें साईंस की कक्षाएं नहीं हैं। साईंस की कक्षाओं के लिए मैंने यहां पिछले सत्र में एक प्रश्न भी लगाया था कि वहां पर लैब बनकर तैयार है और पद भी स्वीकृत हैं लेकिन उसके बावजूद वहां पर स्टाफ नहीं भरा जा रहा है। इस वजह से बच्चों को पढ़ने के लिए नाहन या पौंटा जाना पड़ रहा है। ऐसे कॉलेज खोलकर क्या फायदा है जिनका वहां पर छात्रों को लाभ ही न मिले। इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

01/03/2016/1555/MS/AG/2

भाई अजय महाजन जी अभी सदन में बैठे नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए और शायद सभी विधान सभा क्षेत्रों में इस प्रकार के काम हुए होंगे। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। पिछले तीन सालों से जब से यह सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो आई0टी0आइज0 चल रही हैं लेकिन अभी तक उनके भवन नहीं बने हैं। जमीन सरकार के नाम कर दी है लेकिन आज तक भी वहां पर आई0टी0आई0 का भवन नहीं बना है और छात्रों को प्राइवेट किसी बिल्डिंग में पढ़ाया जा रहा है जहां पर उनको पढ़ाने के पूरे साधन नहीं हैं। ऐसी शिक्षा आज इस प्रदेश में हमारे नौजवानों को दी जा रही है। आई0आई0एम0 की कक्षाएं हमारे पौंटा साहिब में चल रही हें। लेकिन किसी प्राइवेट संस्थान में उसकी कक्षाएं चल रही हैं। यह बहुत बड़ा संस्थान केन्द्र सरकार ने हमारे प्रदेश को दिया है। इससे हमारे प्रदेश को लाभ होगा लेकिन जब तक यह संस्थान बनकर तैयार नहीं होगा, इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। अभी इसके लिए कहीं से कृषि भूमि ट्रांसफर होनी थी लेकिन पता नहीं अभी उसकी वस्तुस्थिति क्या है। इस तरह से जब अच्छे संस्थान नहीं बनेंगे तो हम शिक्षा को किस ओर ले जा रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है।

सभी लोग स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता करते हैं लेकिन दूर-दराज़ के क्षेत्रों में, मैंने माननीय मंत्री जी से मिलकर भी कई बार निवेदन किया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सक नहीं हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे क्षेत्र में होती हैं लेकिन अस्पताल बिल्कुल खाली हैं।

हमारे क्षेत्र में एकमात्र सी0एच0टी0 शिलाई में है जहां पर मात्र दो चिकित्सक हैं। जब एक चिकित्सक छुट्टी पर जाता है तो एक ड्यूटि पर रहता है। अब वह अकेला चिकित्सक ओ0पी0डी0 देखे या अंदर बिस्तरों पर दाखिल मरीजों को देखे। वहां पर 200-250 एक दिन की ओ0पी0डी0 है। जितनी भी पी0एच0सीज0 मेरे विधान सभा क्षेत्र में है जिनमें पी0एचसी0 रोनहाट, नैणीधार, क्यारीगुणा, कफोटा, कमरऊ और पी0एच0सी0 जागना, इन पी0एच0सीज0 में कहीं पर भी चिकित्सक नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः भेज दिए हैं।

01/03/2016/1555/MS/AG/3

श्री बलदेव सिंह तोमरः मैंने भी अखबारों में पढ़ा था कि आपने चिकित्सक भेज दिए हैं। मैंने आज सुबह ही पता किया और मुझे बताया गया कि अभी तक वहां चिकित्सक नहीं पहुंचे हैं। माननीय मंत्री जी होता क्या है कि आप यहां से आदेश कर देते हैं लेकिन वे एक महीने के अंदर-अंदर अपनी एडजस्टमैंट करवा लेते हैं। वे चिकित्सक या पौंटा में रहते हैं या नाहन चले जाते हैं। वे हमारे क्षेत्र में नहीं जाते हैं। मेरा आपसे विशेष आग्रह है क्योंकि मेरा दूर-दराज़ का क्षेत्र है और कोई मरीज यदि बीमार होता है तो जब तक उसको पौंटा पहुंचाया जाता है तब तक वह अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब खासकर चिकित्सकों की इंटीरियर में पोस्टिंग करते हैं तो उस पोस्टिंग में यह ऑर्डर डालें कि यह पोस्टिंग कैंसल नहीं होगी।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

01.03.2016/1600/**जेएस/डीसी**/1
श्री बलदेव सिंह तोमरः-------**जारी**------

दूसरे, यहां पर बेरोजगार भत्ते की बात कही गई। महाजन जी कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो सबने बैंकों में खाते खुलवाए। हिमाचल प्रदेश में भी बेरोजगारों ने बैंकों में खाते खुलावाए थे। जब यह सरकार इस प्रदेश में आई थी सभी बेरोजगार नौज़वानों ने खाते खुलवाए थे कि बेरोजगारी की

किश्त हमारे बैंक खातों में आएगी, लेकिन आज तक कोई भी पैसा उनके खाते में नहीं गया। वे आने वाले समय का इंतजार कर रहे हैं जब इस प्रदेश में विधान सभा का चुनाव होगा। उस वक्त इस चीज का ज़वाब वे आप लोगों को देंगे। वैल्फेयर डिपार्टमैंट के बारे में यहां कहा गया कि जो पैंशन इस प्रदेश में दी जा रही है, चाहे अपंग पैंशन हो, विधवा पैंशन हो, वैसे भी पैंशन किसने शुरू की थी जब वर्ष 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वर्ष 1977 में भी इसे जारी रखा और फिर माननीय धूमल जी ने इसे आगे बढ़ाया। लेकिन आज भी प्रदेश में बहुत सारे पैंशन के लम्बित मामले दफ्तर में पड़े हैं। इसमें भी pick & choose का कार्यक्रम होता है। मैं अभी सैशन में आने से पहले जब कार्यालय गया तो जिन्होंने एक-एक, दो-दो साल पहले अपने फॉर्म जमा करवाए थे उनको आज तक पैंशन नहीं मिल रही है। दूसरे, जो मकान वैल्फेयर डिपार्टमैंट के माध्यम से ओ0बी0सी0 लोगों को दिए जाते हैं उसमें भी बहुत बड़ी धांधलियां हमारे जिले में हो रही है। माननीय मंत्री जी आज यहां नहीं बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिला में DWO की जो पोस्ट है वह पिछले तीन साल से वहां पर नहीं है। पीछे एक TWO को वहां पर लगाया गया है और वे किस तरह से मकानों का आबंटन करते हैं कई बेचारे व्यक्ति जिन्होंने तीन-चार साल पहले फॉर्म जमा करवाया है उनको मकान नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी सिफारिश नहीं है और जो एक महीना पहले भी फॉर्म जमा करवाएगा उसको मकान तुरन्त दिया जाएगा। मुझे अभी सूचना मिली है कि जो दूसरी मीटिंग वैल्फेयर में मकान के लिए होती है लेकिन बिना मीटिंग के ही मकान आबंटित किए जा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी और सरकार से निवेदन है क्योंकि उस कमेटी में सभी माननीय विधायक सदस्य होते हैं। उसकी प्रॉपर तरीके से मीटिंग करके तभी

01.03.2016/1600/जेएस/डीसी/2

मकान आबंटित करें, क्योंकि इस तरह की धांधलियां अगर प्रदेश में होगी तो यह प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है और आपकी सरकार के लिए भी यह अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज वाईंड अप करें।

श्री बलदेव सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर एक बहुत बड़ी चर्चा एक नियम के तहत आई थी। माननीय अध्यक्ष जी मुझे समय दीजिए। मेरा नाम कल भी कट गया था और उससे पहले भी कट गया था, इसलिए मुझे पांच मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर जो चर्चा आई थी जो एन्क्रोचमैंट के मामले हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में किस तरह से pick & choose का कार्यक्रम हो रहा है। 45 जो मामले हैं उनके लिए कनैक्शन काटने के लिए यहां से वन विभाग को ऑर्डर गए और उन्होंने बिजली विभाग को ऑर्डर दिए। लेकिन मात्र 10 कनैक्शन कटे हैं जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग थे और बाकी लोगों के कनैक्शन आज भी नहीं कटे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि या तो उनके भी वापिस बिजली के कनैक्शन दिए जाए या तो बाकी लोगों के भी बिजली के कनैक्शन काटे जाएं। इस तरह की pick & choose की पॉलिसी है। यह ठीक नहीं है। विभाग को सूची गई है और आपके विभाग के पास पूरी सूची है।

दूसरे, यहां पर उद्योग की बात आई कि उद्योग की क्या परिस्थिति है। जिला सिरमौर की यहां पर माननीय धूमल जी ने यहां पर बात रखी। पौंटा और काला-अम्ब का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे उद्योग लगे हैं। लेकिन आज की स्थिति में दर्जनों उद्योग वहां से छोड़ कर जा चुके हैं उनके बिजली के कनैक्शन काटे गए हैं । मालापटन स्पिनिंग मिल जो सबसे पहले उद्योग पौंटा साहिब में आया था जिसमें 2-3 हजार तक महिलाएं काम करती थी। आज वह उद्योग खाली पड़ा है। बेरोजगारों के

प्रतिशत की बात की जाती है कि 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों को वहां पर कहां लगाया जाता है? ठेकेदार के माध्यम से बेलदारी में लगाया जाता है। जो हमारे लड़कें डिग्रियां करते आ रहे हैं उनको वहां पर रोजगार नहीं मिला है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

01.03.2016/1605/SS-DC/1

श्री बलदेव सिंह तोमर क्रमागतः

जो एम0बी0ए0, बी0टैक करके आ रहे हैं उनको कहा जाता है कि आपके लिए यहां पर नौकरी नहीं है। वे सभी लोग बाहर से वहां पर लगाये जाते हैं। श्रम मंत्रालय वहां पर जा कर देखे, उनके अधिकारी वहां पर जाकर उनके रजिस्टर चैक करें कि वहां पर कौन-से और कहां के लोग नौकरी कर रहे हैं। यह बहुत चिन्ता का विषय है क्योंकि यह हमारे नौजवान से जुड़ा हुआ विषय है। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य हो रहा है। हमारे यहां लाइम स्टोन की माइनिंग होती है। मैं हर बार विधान सभा के अंदर यह बात रखता हूं कि हमारे यहां अवैध खनन बहुत जोरों से चला है लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आज भी अगर आप यहां से टीम भेजेंगे तो कांटीमछवा, सतोली और पुडगा रोड पर देखेंगे कि अवैध खनन हो रहा है। वहां के लोग लगातार अपने डैपुटेशन लेकर डी0सी0 साहब के पास गए। एस0पी0 साहब के पास गए और माइनिंग अफसर के पास भी गए। लेकिन सभी विभाग एक-दूसरे पर बात को टालते हैं। माइनिंग अफसर कहता है कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। पुलिस कहती है कि हमारा यह काम नहीं है तो फिर इस काम को रोकेगा कौन? आज भी अगर आप रात को जाएं तो कम-से-कम 100 ट्रक वहां से निकलते हैं। उससे सरकार को कितनी हानि हो रही है। विशेषकर फॉरैस्ट क्षेत्र के अंदर अवैध खनन हो रहा है। मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि आप उसकी विजीलैंस इंक्वायरी करवाईये। कितना वहां से मैटीरियल निकाला गया, उसका आप सर्वेक्षण करिये। कई लाख टन मैटीरियल वहां से निकला है। उसके अंदर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। कौन-कौन लोग उसमें मिले हुए हैं इस

बात का खुलासा भी तब होगा जब इंक्वायरी होगी। मेरा निवेदन है कि आप इस ओर भी ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

01.03.2016/1605/SS-DC/2

अध्यक्षः श्री मनसा राम जी, अनुपस्थित। अब श्री सोहन लाल जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री सोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिवः अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने यहां पर अभिभाषण दिया, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। अभी-अभी हमारे विपक्ष के मित्र ने कहा कि जो भी इस अभिभाषण में कहा गया है वह सारा झूठ है। यह इनका सबसे बड़ा झूठ है। जबकि इस अभिभाषण में जो आंकड़े दिये गये हैं वे तथ्यों से युक्त हैं। ऐसा कोई विकास का क्षेत्र नहीं है जिसमें पिछले तीन सालों से सरकार ने काम न किया हो या उस पर उपलब्धि हासिल न की हो। हमारी सरकार ने जो चुनावी वायदे किये थे, जिस पर अभी चर्चा हुई और हमने कहा है कि हमने अधिकांश अपने चुनावी वायदे विकास की दृष्टि से पूरे कर लिये हैं। दूसरी तरफ विकास के आंकड़े इस दस्तावेज में दिये गये हैं। लेकिन यदि चुनावों के मुद्दों की बात करनी हो तो जब-जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और जो चुनावी वायदे देकर आई थी वे आज सभी प्रदेशवासियों के सामने हैं। वे एक चुनावी जुमले बन कर रह गए हैं। यदि हम याद करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नारा दिया था - 'हर हाथ को काम देंगे', 'हर रसोई में नल देंगे'। यह आज की स्थिति में एक चुनावी जुमला है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि सस्ता राशन देंगे। दो रुपये आटा, तीन रुपये चावल और 25 पैसे नमक देंगे। वह भी कभी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद अभी कल जो इस हाउस में चर्चा हुई, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी

की सरकार ने एक चुनावी वायदा किया था कि हम जितने भी प्रदेश में अवैध कब्जे हैं उनको वैध करेंगे। वह भी चुनावी जुमला साबित हुआ। आज उसका जो परिणाम है वह पूरे प्रदेश की जनता को सहन करना पड़ रहा है। उससे एक विकट स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जब यह कहा गया कि अवैध कब्जों को नियमित किया जायेगा तो रातोंरात अधिकाधिक अवैध कब्जे हो गए। कुछ तो ऐसे कब्जे थे जोकि लोगों ने अनजाने में किये हुए थे। जो उनकी बरतान की जगह थी उसमें अनजाने में कब्जे किये हुए थे। लेकिन जब उनको कहा गया कि हम आपके कब्जे वैध करेंगे..

जारी श्रीमती के0एस0

01.03.2016/1610/केएस/एजी/1

श्री सोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव जारी---

तब भारी पैमाने पर प्रदेश में अवैध कब्जे हुए जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है और इसी बात को यदि हम आज के परिवेश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ताजा जुमला इस देश की जनता को दिया, वह था- अच्छे दिन आएंगें, भ्रष्टाचार दूर करेंगें, मंहगाई दूर करेंगें, काला धन वापिस लाएंगें। ये सारी बातें आज चुनावी जुमले बन कर रह गए हैं। यदि हम कल की बात करें तो जो हमारे देश में पार्लियामैंट में बजट पेश हुआ, कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगें, किसानों के लिए अच्छे दिन का सपना अब 6 साल का सपना दिखाकर आगे बढ़ा दिया गया है। 2022 में उनकी आय दोगुना करने की बात कही गई है । इन्होंने यह अच्छे दिन की बात कही? जो हमारी सर्विस क्लास है, जो सारी उम्र सर्विस करके सेविंग करते हैं, उस सेविंग का ई.पी.एफ. उनका जमा होता है अब उसी पर इस सरकार ने ऐसा बजट दिया जिसमें 60 प्रतिशत यदि वह विद्ड्रा करता है तो उसको अपने ही पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा। रिटायरीज़ को केन्द्र सरकार ने नहीं बख्शा। यह अच्छे दिनों की बात इस सरकार ने की है लेकिन हमारी सरकार कांग्रेस सरकार जब-जब सत्ता में आई, हमने जो अपने चुनावी वायदे थे, उनको हर बार पूरा किया। हमने आपके चुनावी वायदों का जिक्र

किया है जो जुमले आज जनता के समक्ष है, हर हाथ को काम देंगें, सस्ता राशन देंगें। लेकिन वर्तमान सरकार ने, यहां पर पैंशन की बात हो रही थी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2003 में राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में

01.03.2016/1610/केएस/एजी/2

कांग्रेस की सरकार बनी उस वक्त प्रदेश में पैंशनों के 28 हजार मामले लम्बित थे। वह क्यों थे? क्योंकि उस वक्त यह पोलिसी डिसिज़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था कि कोई भी नई पैंशन प्रदेश में नहीं लगेगी only with replacement. और रिप्लेसमैंट तभी होगी जब पहले का पैंशनधारक स्वर्ग सिधारेगा। लेकिन इसी विधान सभा में हमारे मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था कि जितने हमारे पैंडिंग पैशन केसिज़ है उनको हमने उस वक्त मार्च, 2003 में एक मुश्त लागू किया जो कि इस प्रदेश सरकार का उस वक्त का एक रिकॉर्ड है और जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने पैंशन की उसी नीति को आगे न बढ़ाते हुए इसमें आय सीमा में कंडिशन लगा दी जिसमें मनरेगा की इन्कम को भी जोड़ा गया और मनरेगा की इन्कम की वजह से नए पात्र व्यक्तियों की उस इन्कम लिमिट की वजह से पैंशन नहीं लगी। हमारी सरकार ने इसके लिए एक फैसला लिया और इस इन्कम सीमा को बढ़ाकर 35 हजार किया जिसका नतीजा यह हुआ कि जितने भी पात्र व्यक्ति उस आय सीमा में आते हैं, उन्हें आज हमारी सरकार ने पैंशन लगाई है और एक बहुत बड़ी राहत दी 80 साल की आयु से ज्यादा और 70 प्रतिशत हैंडिकैप्ड लोगों को इस आय सीमा से बाहर किया है और उनको 1100 रुपया मासिक पैंशन हमारी इसी सरकार ने दी है जो कि इस सरकार की उपलब्धि है । यदि इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तुलना की जाए तो यह सही रूप में हमारी एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आपकी सरकार ने दो टर्मज़ में इस योजना पर काम नहीं किया बल्कि इसको पीछे

01.03.2016/1610/केएस/एजी/3

धकेला। इसके बाद आप देखिए कि हमारी सरकार ने,आप लोग अभी शिक्षा संस्थानों के बारे में बात कर रहे थे। हमारी सरकार ने इन तीन वर्षों में डिफरैंट केटैगरीज़ के 994 स्कूल अपग्रेड किए और 25 नए डिग्री कॉलेज खोले।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

1.3.2016/1615/av/ag/1

श्री सोहन लाल (मुख्य संसदीय सचिव)----- जारी

आपने (---व्यवधान---) वैरीगुड, बिल्कुल है। प्रदेश में यह एक प्रोग्रैस हुई है। कर्नल साहब, हम आपको याद दिलाते हैं, आज भी इतने स्कूल खुलने के बाद जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, आप भी जाते होंगे। तो वहां की जनता आपसे भी स्कूल अपग्रेड करने की मांग जरूर करती होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। हमारे पास आज भी लोगों की ऐप्लिकेशन्ज आई हैं। जहां पर सड़क से दूर कई मील पैदल चलकर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है, हमारे पास उस पंचायत क्षेत्र के लोगों की ऐप्लिकेशन्ज आती हैं। हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि प्रदेश में 954 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। हमारे चुनाव क्षेत्र में 20 से ज्यादा स्कूल अपग्रेड हुए हैं और अब भी यह मुक्कमल नहीं है। इसकी जरुरत अब भी है। (---व्यवधान---) हम आपको याद दिलाते हैं। वर्तमान सरकार ने तीन साल के कार्यकाल में 20 स्कूल अपग्रेड किए और आपके वक्त में मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरे पांच साल में केवलमात्र दो स्कूल अपग्रेड हुए थे। यहां तो मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं तो घोषणाएं पूरी होती है। हम इनके पास जाकर आवेदन करते हैं और जिसके आधार पर हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर घोषणाएं करते हैं तथा वे पूरी होती है। यहां पर पूर्व मुख्य मंत्री प्रेम कुमार धूमल जी बैठे हैं। इन्होंने 25

जनवरी, 2012 को सुन्दरनगर में चार स्कूल अपग्रेड करने की घोषणा की थी। मगर उन चार में से मात्र एक स्कूल ही अपग्रेड हुआ बाकी तीन स्कूल अभी तक अपग्रेड नहीं हुए। हमारी वर्तमान सरकार ने 25 डिग्री कॉलेज खोले हैं। आपकी सरकार ने भी शायद 8 कॉलेजिज की अनाउंसमैट की थी। मगर वह अनाउंसमैंट तब की गई जब चुनावी साल था और इलैक्शन के लिए 4 महीने का समय शेष रह गया था। जब युनिवर्सिटी ने ऐडमिशन बंद की थी तब आपने कॉलेजिज की नोटिफिकेशन की थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में निहरी में आपने कॉलेज की घोषणा की थी और उसकी नोटिफिकेशन सितम्बर, 2012 में हुई थी जबकि कॉलेजिज की क्लासिज जून महीने में बैठती है। वह कॉलेज मात्र एक लैक्चरर, 6 स्टुडैंट और एक पीयुन से चल पड़ा। हमारी वर्तमान सरकार ने प्रदेश में जो 25 नये कॉलेज खोले हैं उनके

1.3.2016/1615/av/ag/2

लिए बाकायदा लैक्चरर्ज की नियुक्तियां की है और उनके लिए विधिवत रूप से बजट का प्रोविजन किया है। जितने भी कॉलेज खुले हैं उनमें 5 करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन किया है। लैक्चरर्ज उपलब्ध करवाये गये हैं। आज निहरी कॉलेज में 6 की जगह 7 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और जितने भी वहां पर रिक्वायर्ड लैक्चरर्ज हैं; वे सारे कार्यरत्त हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री सोहन लाल (मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में पहली बार बोल रहा हूं।

अध्यक्ष : लम्बा सैशन है, आप अभी बहुत दफा बोलेंगे।

श्री सोहन लाल (मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, पहले तो विपक्ष की तरफ से व्यवधान डाला जा रहा था, मैं उसको सह रहा था और अब आप समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं। अब तो बोलने का रिदम ही खत्म हो गया। (---व्यवधान----) गलत नहीं

बोल रहा हूं, तथ्यों पर बोल रहा हूं। (---व्यवधान----) कहीं बंद नहीं हुए।

शिक्षा के बाद अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। आज हिमाचल प्रदेश के दूरदराज एरिया में स्वास्थ्य संस्थानों की बहुत जरुरत है। हमारी सरकार की विशेष उपलब्धि है कि इन तीन वर्षों के कार्यकाल में हमने सौ से ज्यादा नये इनस्टिच्यूशन्ज खोले/अपग्रेड किए हैं। ऐसा नहीं है कि अपग्रेड ही किए हैं कहीं-कहीं जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टरों की कमी है

:श्री टीसी द्वारा जारी

01.03.2016/1620/TCV/DC /1

श्री सोहन लाल ---- जारी

लेकिन सरकार ने इसके साथ-साथ इस कमी को देखते हुए 500 से ज्यादा 550 डॉक्टर्ज और 60 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्ज अप्वाईंट किए हैं। यह बात तथ्य पर आधारित है, कोई झूठ नहीं है। इसके साथ ही जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, उसमें 3355 टीचर्ज़ की पोस्टें सृजित हुई है। जो हमारी पूर्व सरकार ने पी0टी0ए0 टीचर्ज़ लगाए थे, उनके ऊपर आपने हमेशा तलवार लटकाकर रखी। इनमें से काफी तो आपने राजनीतिक भावना से भी निकाले थे। हमने उनको रि-इनिशिएट किया। उनके लिए एक नीति बनाई । अभी -अभी हमारी सरकार ने जो दूर-दराज़ के क्षेत्र हैं, जहां पर टीचर्ज़ नहीं है वहां एस0एम0सी0 के माध्यम से टीचर्ज़ को अप्वाईंटमैंट करने की पॉलिसी बनाई है। ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। इसके साथ-साथ सरकार ने 19 आई0टी0आई0 प्रदेश में खोले हैं। इसके चलते अब प्रदेश में ऐसा कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं हैं जहां आई0टी0आई0 न हो। ये भी सरकार की एक उपलब्धि है और आने वाले समय में हम प्रदेश के नौजवानों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देकर उनको सक्षम बना रहे हैं। इसी दौरान हमारी सरकार ने 20 नई उप-तहसीलें खोली हैं, 13 उप-तहसीलों को

तहसील का दर्ज़ा दिया है। इसके अतिरिक्त 7 नये राजस्व उप-मण्डल खोले गये हैं, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उन्हें तहसील और उप-तहसील के कार्य के लिए दूर-दूर तक न जाना पड़े। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं जो व्यवहारिक है। जिसका फायदा लोगों को सीधे रूप से मिल रहा है। जब आपकी सरकार थी तो न तो आपने उप-तहसील खोली, न तहसीलें बनाई। लेकिन जब-जब आप सत्ता में आए जिले बनाने की बात आपने जरूर की । जिले बनाने के लिए आपने चिन्हित भी कर दिए थे, हमारे सुन्दर नगर में भी जिला खोला जाना था। जोकि कभी पूरा नहीं हुआ और अनाउंसमैंट की अनाउंसमैंट रह गई। जिले बनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो छोटी-छोटी ईकाईयां है, उनको बनाने का काम हमारी सरकार कर रही

01.03.2016/1620/TCV/DC /2

है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी सरकार के विकास की उपलब्धि न हो। अब हमारी सरकार ने 1200 नई बसें प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एड की है और 69 नई बसें हम एड कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एच0आर0टी0सी0 का जो फेयर है, वह फ्री किया है। महिलाओं के लिए 25 परसेंट किराये में छूट दी है। ये काम इस सरकार ने किए हैं और जो हमारा तीन साल का कार्यकाल है, यह उपलब्धियों भरा है। यदि आपने अपने वक्त इस प्रकार से कार्य किए होते तो आपके साथ भी इसी तरह की उपलब्धियों का शुमार होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार ने चुनावी वादों के ऊपर काम किया है और इससे भी ज्यादा काम हम आने वाले दो वर्षों में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

अगला वक्ता श्री आर0के0एस0 द्वारा--जारी

01.03.2016/1625/RKS/AS/1

अध्यक्षः अब कर्नल इन्द्र सिंह जी, अपने विचार रखेंगे। kindly take shortest time.

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 25 फरवरी को दिए गए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यावाद प्रस्ताव आदरणीय जगजीवन पाल जी ने रखा। जिसका समर्थन आदरणीय अजय महाजन जी ने किया। मैं, उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। जगजीवन पाल जी ने बड़े जोर से कहा कि 70 परसेंट पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। अगर यह चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ा जाता तो शायद आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाता। इसमें हैरानी की बात नहीं है। श्री जगजीवन पाल जी जो पहले वक्ता थे, बड़े जोरशोर से इन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं हैं। सच मानो तो यह सारी बातें पिछली धूमल सरकार द्वारा चलाई गई थी। आपने उन्हीं बातों में इम्प्रूवमेंट किया है। जोकि हर सरकार करती है। जहां तक पेंशन की बात है, बार-बार हर वक्ता कह रहा था कि 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को पेंशन बिना इनकम के लग रही है। उनसे इनकम का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। यह केंद्र सरकार की देन है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको इसे केवल इम्पलिमेंट करना है। महाजन जी यहां नहीं हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता था। जगजीवन पाल जी you are a thorough gentleman, tall figure smiling face. पता नहीं आपको क्या हो जाता है। आप कभी -कभी नॉन कंट्रोवर्शियल इश्यू को भी कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। You try to put a square peg in a round whole. Try to defend then defensive वह बिल्कुल ठीक बात नहीं लगी। क्योंकि जो सच है उसको सच बोलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जब आप बोलते हैं तो इस सदन में कुछ नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, इन 3 वर्षों में मेरे चुनाव क्षेत्र में दो उपलब्धियां रही हैं। पहली उपलब्धि यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां जाकर शिलान्यास कर गए। पहला पत्थर और आखिर पत्थर माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे चुनाव क्षेत्र में रखा है। जिसका ए.ए. एण्ड ई. एस. आदरणीय धूमल जी के समय में सैंक्शन हुआ है। दूसरी उपलब्धि जो बड़ी

इंटरस्टिंग है, आपने वहां पर एक पॉलिटिक्ल एडवाइजर बना

01.03.2016/1710/RKS/AG/2

दिया है। एक रिटायर व्यक्ति को टायर लगा दिए हैं। लेकिन ईंजन तो पुराना ही है। You have not changed the engine. बहुत से वक्ताओं ने यहां की बात न करके, प्रदेश की बात न करके अपने चुनाव क्षेत्र की बात न करके कोई दिल्ली चला गया, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई जे.एन.यू में चला गया। कोई सेंटर बजट यहां डिस्कश कर रहा है। हम यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव को डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रहूंगा। क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में न कोई आता है और न कोई जाता है। वह हमारे हवाले ही छोड़ा है। Political Advisor is only to do the transfer that's all. सबसे पहले मैं उस विभाग की बात करना चाहूंगा जिससे सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। आज मेरे प्रदेश में आई.पी.एच. विभाग की खस्ता हालत है। जितने भी काम माननीय धूमल जी की सरकार ने शुरू किए थे वे सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। and the information what we get here is absolutely false, contradictory. मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने प्रश्न संख्याः 427 जो 18 दिसम्बर, 2013 को किया था। उसके जवाब में आया कि 3 बड़ी स्कीमें हमारी लिफ्ट इरिगेशन की है।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

01.03.2016/1630/SLS-DC-1

श्री इन्द्र सिंह ...जारी

ये स्कीमें 70-70, 80-80 लाख रुपये की हैं और ये स्कीमें मार्च, 2014, मई, 2014 या जून 2014 तक पूरी हो जाएंगी। यह विभाग का दिया हुआ उत्तर है। लेकिन अभी 2016 में भी वह अधूरी पड़ी हैं। अब हम कैसे विश्वास करें कि आप जो बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। इस हाऊस में झूठ नहीं बोलना चाहिए और आपका यह झूठ ज्यादा दिन नहीं

चलेगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। Speaker Sir with your permission I would like to say. This Government must know that the people are not interested in knowing about the labour pains this Government is undergoing. Their interest is at the result कि मुंडा होया या कुड़ी होई। ऐत्थे तां कुछ बी नी होया, तिन साल हो गए। कुछ तो करो।

मुख्य मंत्री : ज़रा तमीज़ से बात करो। क्या बातें करते हो? कर्नल रहे हो फौज के। Speak in a civilized language . लेबर पेन हो रहा है ...(व्यवधान)...

Shri Inder Singh : It is not an unparliamentary language. I am pained to know nothing is happening in my constituency.

Chief Minister : I am pained that Colonel of the Indian Army has stood so low. I am pained for you and I am pained for Indian Army.

Shri Inder Singh : Your Government is not supporting my constituency at all. I am pained. I go to the people and they ask me, where is water? I say I will bring it from Chief Minister Sahab.

Chief Minister : It is your failure. What can be done. ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो आपके काम कौन करेगा?

01.03.2016/1630/SLS-DC-2

Shri Inder Singh : Nothing is done there, everything is pending there. You have laid only one stone there thats all, that is your contribution towards my constituency. I am sorry to say that.

Chief Minister : Yes.

श्री इन्द्र सिंह : 52 कूहलें हैं, स्मॉल चैनल्ज हैं जो रैवन्यु रिकॉर्ड में हैं। वह एक भी काम नहीं करती है, मैं किसके पास जाऊं। Whom should I tell my grievances. I have to come to you and you are annoying when I am saying the truth.

3 स्कीमें हैं जिनमें माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के समय में हमने काण्डापत्तन से पानी उठाना था। एक 40 करोड़, एक 15 करोड़ और एक 29 करोड़ रुपये की है। वह क्यों पैंडिंग पड़ी हैं जबकि आपने मुझे उत्तर दिया है कि वह 31 अक्तूबर, 2014 को पूरी हो जाएंगी और जनता को हैंड ओवर कर दी जाएंगी? इस समय 2016 चला है। Who is responsible for that? Mr. Chief Minister, Sir, I need your assistance in this case, I don't need your anger in this case.

Chief Minister : You can't get anybodies assistance with the language you use and the arrogance you have.

Shri Inder Singh : I don't have. I am a very docile man.

Chief Minister : You are a slur on the traditions of the Indian Army.

Shri Inder Singh : I am a very docile man. You are cracking me in this house जितनी भी पीने के पानी की फ्लो ग्रेविटी स्कीम्ज हैं, किसी में फिल्टर नहीं है कहीं टैंकों के ऊपर डक्कन नहीं हैं। आप हमें क्या पानी दे रहे हैं? बात करें तो कहते हैं! एक फौजी आदमी जिसकी लड़ाई में टांग कट गई है, आपने उसका वॉटर कनैक्शन भी कटवा दिया। वह बेचारा चल नहीं सकता, पहाड़ी इलाका है। मैंने बार-बार एक्स.ई.एन. को फोन किया कि उसको कंपैशनेट ग्राऊंड पर लगा दो। कम-से-कम उसका कंपैशनेट ग्राऊंड तो

01.03.2016/1630/SLS-DC-3

देखिए। Nothing is happening , nobody is listening.आपके सिस्टम में कोई इनपुट

और आऊटपुट देने का तरीका ही नहीं है। Information should flow from bottom to top and orders should come from top to bottom. उस एक्स.ई.एन. को पता ही नहीं है कि कौन-सी स्कीम खराब हो रही है क्योंकि नीचे से ऊपर कोई सूचना जाती ही नहीं है। आपका क्या सिस्टम है और आप कैसे काम कर रहे हैं, इसका पता ही नहीं। Very bad. मैं सीर खड्ड की बात करना चाहता हूं। वहां हालत बहुत खराब है। मैंने यहां प्रश्न किया था। उसका मुझे जो सप्लीमैंटरी उत्तर मिला वह कोई संतोषजनक नहीं है। मैंने कहा कि जो डैंजर प्वायंट्स हैं, जहां इरोजन होने वाला है; दो गांव प्रभावित हैं, कम-से-कम वहां ऐडहॉक अरेंजमैंट्स तो करिए क्योंकि जब सी.डब्ल्यु.सी. से

परमीशन आएगी तब तक नुकसान हो गया होगा, बीच में कई बरसातें निकल गई होंगी। उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। फिर हम ज़ोर से न बोलें तो क्या बोलें।

मेरी कोई डी.पी.आर. नहीं बनी है। मेरी नाबार्ड की 9 सड़कें पड़ी हैं। PMGSY Stage-1 की 14 सड़कें और Stage-2 की 20 सड़कें पड़ी हैं और यह सड़कें केवल FCA के कारण लंबित पड़ी हैं।

जारी ...गर्ग जी

01/03/2016/1635/RG/DC/1

श्री इन्द्र सिंह-----क्रमागत

What is this? आपके कर्मचारी काम क्यों नहीं करते? सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है। सड़कों में आज आप टारिंग करिए, कल को उखड़ जाती है और जब आप शिकायत करिए, I have written a letter, personally handed over to Chief Secretary, कृपया आप इसकी जांच कराइए, nothing happened, where has the letter gone? Is it in the dead letter box. What is this? Very poor arrangements और मेरे लोक निर्माण मण्डल में केवल डंगे लग रहे हैं, सड़कें रिपेयर नहीं हो रही हैं मुख्य मंत्री महोदय, केवल डंगे लग रहे हैं, लोक निर्माण मंत्री महोदय,

केवल डंगे लग रहे हैं। इसलिए मैंने अपने डिवीजन का नाम ही डंगा डिवीजन रख दिया है। Very strange situation, Sir. आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूं और सच्ची बात बोल रहा हूं।

Chief Minister: I know you very well. I am not angry.

Shri Inder Singh: Then as I said in the Planning Committee meeting also. कॉन्ट्रैक्ट लेता है एक मोटा आदमी ही। सर, मोटा आदमी कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, then he starts subletting them और सबलैट पर 15-20% कमीशन वह रखेगा, बाकी वह सबलैट कर देगा। आप मुझे बताइए कि क्या क्वालिटी ग्राऊन्ड में आएगी? कुछ वह भी रोजी-रोटी कमाएगा, तो 30-40% पैसा आपका जमीन में जाएगा, ग्राऊन्ड में जाएगा। Kindly stop this sub-contracting business. कहीं ठेकेदार ठेका ले लेते हैं, बहुत से इकट्ठा कर लेते हैं फिर बाद में रिसींड कर देते हैं, ढाई प्रतिशत तो उनका लगना है। उनकी सिक्योरिटी जब्त होगी, उनको इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उससे आपका प्रोजैक्ट कितने साल तक डिले हो जाता है? आप इसको भी बंद कराइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

Speaker : Please try to windup.

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे सिर्फ दस मिनट हुए हैं। अभी तो मुझे एजुकेशन पर भी बात करनी है। सर दो मिनट, प्लीज। मैंने पहले भी कहा है कि सरकाघाट सन्धोल से लेकर धर्माणी जी, सुनिए, घुमारवीं तक कोई मैडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। इतनी पूरी बैल्ट में, इतनी बड़ी वैली में कोई गाइनॉकॉलाजिस्ट नहीं है, कोई ऑर्थोपैडिक सर्जन नहीं है। हम किस पर निर्भर हों, आप बताइए and total dependency is on Government

01/03/2016/1635/RG/DC/2

Hospitals because there is no private hospital there worth name. मेरे यहां बी.एम.ओ. के अण्डर 19 डॉक्टर्ज होने चाहिए, लेकिन चार डॉक्टर्ज पोस्टेड हैं। अब बताइए हम किससे बात करें? आप कहते हैं कि जोर से बोल रहे हो। मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं। मैं प्यार से बोल रहा हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : आठ डॉक्टर्ज हैं।

श्री इन्द्र सिंह : नहीं, सर, नहीं। अभी आपने भेज दिए हों, तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं। रैफरल हास्पीटल, सरकाघाट में आपने एक इन्डोर ब्लॉक बनाना है। वह सौ बिस्तरों का अस्पताल है, लेकिन 50 बैड पर रन कर रहा है। मुझे यह बताया गया था, मैंने पूछा था कि वह कब बनना है, तो आपने जवाब दिया था 29-8-2013 को। प्रश्न संख्या 622 के अन्तर्गत कहा गया कि पी.डब्लू.डी. वास्तुकार से बात चल रही है। वह बात कब खत्म होगी जब सैंचुरी खत्म हो जाएगी? बात चल रही है। इसी प्रकार सी.एच.सी. , बल्दवाड़ा के लिए 40 लाख रुपये सी.एम.ओ. मण्डी के पास आया था और वह वर्ष 2012 से पड़ा हुआ है। वह धूमल साहब के आशीर्वाद से आया था। you are aware of it. मैंने प्रश्न संख्या 1011, दिनांक 17-2-2014 को बार-बार करने के बाद, एक आखिरी प्रश्न था, तो आपने कहा प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग से लिया जा रहा है। This is strange Sir, please exercise your powers. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से बार-बार मेरी सबमिशन रहती है और प्लानिंग की मीटिंग में भी बात हुई है कि मिनी सैक्रेटेरिएट, सरकाघाट में लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए। कहते हैं कि लोक निर्माण विभाग को पैसे दे दिए हैं, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पांवटा है। It is in a pathetic state. उसका मुख्य भवन डेन्जर डिक्लीयर किया है, उसको लोक निर्माण विभाग ने अनसेफ डिक्लेयर किया है। 3-4 साल हो गए, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, पिछली सरकार से भी कुछ पैसा वहां आया था। वह बिल्डिंग वैसे-की-वैसे ही खड़ी है। उसमें कभी भी हादसा हो सकता है। बार-बार बोलने के बावजूद भी कोई ऐक्शन नहीं होता। स्कूलों में साइंस लैब कोई नहीं बनीं। धूमल साहब के समय में सात स्कूलों में 90-90 लाख रुपये की साइंस लैब बनी थीं। लेकिन इन तीन सालों में एक भी स्कूल में साइंस लैब नहीं बनी। यह शिक्षा के लिए आपकी देन है। यह मैं कहना चाहूंगा। कितने स्कूल आपने अपग्रेड कर दिए, लेकिन अध्यापक कहां हैं, इनफ्रास्ट्रक्चर कहां है? किसी को कोई पता नहीं। इधर से उधर अध्यापको को भेज रहे हैं। एक स्कूल में मैं गया, तो एक टीचर बैठा

01/03/2016/1635/RG/DC/3

हुआ था और उसके पास दो छात्र थे। मैंने उससे पूछा कि तू कब से यहां आ गया, वह

कहता हे कि मैं तो डेपुटेशन पर आता हूं, कई महीने हो गए। तो केसे पढ़ाई चलेगी। Quality education has gone down the hill.

एम.एस. द्वारा जारी

01/03/2016/1640/MS/AG/1

श्री इन्द्र सिंह जारी--------
आप कितने भी स्कूल खोलते जाओ लेकिन अपने आर्थिक कद के मुताबिक स्कूल/कॉलेज खोलो। -(घण्टी)- उनको इन्फ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी भी दो, तब मैं आपको मानता हूं। आप बिना फैकल्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और बिना स्टाफ के स्कूल/कॉलेज धड़ाधड़ खोल रहे हैं। यह कैसे चलेगा? आप स्कूल खोल भी रहे हैं और अपग्रेड भी कर रहे हैं। यह कैसे चलेगा? Let us rationalize it. That is my humble request to the Hon'ble Chief Minister.

इस वक्त माननीय परिवहन मंत्री जी यहां सदन में बैठे नहीं है। प्रदेश में लम्बी-लम्बी बसें आई हुई हैं। वे बसें हमारे किस काम की हैं? हमारी सड़कें छोटी-छोटी हैं और यहां वन-वे ट्रैफिक है। वे बसें मुड़ती ही नहीं है। जब हम आर0एम0 को पूछते हैं कि उधर छोटी बस भेजो तो वे कहते हैं कि छोटी बसें है ही नहीं।। hope he will listen to me.

कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रदेश में बहुत दयनीय है। मैंने यहां एक प्रश्न मंदिरों में हो रही चोरियों के बारे में किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न किया था कि प्रदेश में बहुत ज्यादा चोरियां और डकैतियां हो रही हैं, खासकर जो मंदिरों में चोरियां हो रही हैं उन पर ध्यान दिया जाए। एक बड़ा लम्बा-चौड़ा चिट्ठा मुझे जवाब में डी0जी0 साहब की ओर से मिला। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन एक भी काम का नहीं है। उसमें से एक भी चीज ऑन दि ग्राउंड इन्स्टॉल नहीं हुई है।

अध्यक्षः कृपया माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मैं नशे की बात कर रहा हूं। Every alternate dhabha is selling liquor. और वे लिकर कौन सा ब्रांड है? आप हैरान होंगे कि वह कोई चण्डीगढ़ ब्रांड है। वह शराब सब जगह खुल्लेआम बिक रही है। Why don't you control? इससे स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते।

01/03/2016/1640/MS/AG/2

जंगली जानवरों, बंदरों और आवारा पशुओं से हमारे खेत लहुलूहान हो गए हैं इसमें कोई शक नहीं है। कितनी ही कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है, इसका अंदाजा इस सरकार को नहीं है। आप उस बारे में भी सोचिए कि उससे कितना नुकसान प्रदेश की आर्थिकी को हो रहा है। You think over it. यह मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। रोजगार के लिए कोई मॉडल तैयार नहीं किया और विद्युत उत्पादन भी बड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है। ये सारी बातें मैं विस्तार से कहना चाहता हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी बार-बार घण्टी बजा रहे हैं। इसलिए अब मुझे बैठना पड़ेगा। हमारी आर्थिक उत्पादकता फिजूलखर्ची अलाऊ नहीं करती है। मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं कि किस-किस ढंग से फिजूलखर्ची होती है All of you are aware of it including the Chief Minister. मैं इतना ही कहूंगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए बहुत समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

01/03/2016/1640/MS/AG/3

अध्यक्षः अब श्री रवि ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रवि ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत ही लोकप्रिय बजट रहा है और पीछे जितने भी बजट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा चाहे वह महिला, युवा या बुजुर्ग वर्ग है, मैं समझता हूं कि हर वर्ग के लिए बजट में बढ़ौत्तरी हुई है। इसी तरह से स्कूल के बच्चे हैं, किसान वर्ग है, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य

विभाग है या लोक निर्माण विभाग है, हरेक के बजट में बढ़ौत्तरी हुई है। मैं इसके लिए हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। इससे आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा और सभी क्षेत्र विकसित होंगे। हरेक सामान्य वर्ग के लिए यह बजट है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

01.03.2016/1645/जेएस/एजी/1

श्री रवि ठाकुरः ------**जारी**-------

और सामान्य विकास होगा। ऐसा मेरा मानना है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय सदस्य, यह बजट नहीं है, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है।

श्री रवि ठाकुरः सर सॉरी, अभी तो राज्यपाल जी का ही अभिभाषण है। जो काम हुए हैं। (Interruption) I apologize for the mistake. I correct it now. अभी जो हमारे माननीय राज्यपाल जी ने अभिभाषण दिया है वह हमारे लाहौल-स्पिति व जितने भी जन-जातीय क्षेत्र है उसके लिए जो बढ़ौत्तरी हो रही है, जो वहां पर उत्थान हो रहा है उसके बारे में भी काफी कुछ कहा। इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारे इलाके हैं, खासतौर से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेकर लद्दाख तक का इलाका है वह ज्यादातर सीमा पर है और वहां पर जो ओवरऑल डवैल्पमैंट है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसके उत्थान के लिए एक डवैल्पमैंट प्लान बनना बहुत जरूरी है। इसमें एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस जो कि संविधान में हमारे राज्यपाल महोदय हैं, जो कि हमारे कन्स्टोडियन है, उनको पूरी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस दें। इसके बारे में जो हमारी केबिनैट है उसने भी अपनी अप्रुअल दी थी regarding Forest Conservation Act, 1980 in the Scheduled Areas of Himachal Pradesh. यह फोरैस्ट क्लीयरैंस एक्ट बहुत ही जरूरी है। किसी भी तरह का इलाके में कोई भी

उत्थान होना हो या कन्स्ट्रक्शन होनी हो या जो नौतोड़ दिए जाने है हरेक जन-जातीय क्षेत्र में उसके लिए फोरैस्ट क्लीयरैंस एक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें हिमाचल केबिनैट ने यह क्लीयरैंस दी है और मैं इसे यहां पर पढ़ना चाहूंगा। That the Government of Himachal Pradesh vide its notification dated 17.07.2014 suspended the operation of Forest Conservation Act, 1980 in exercise of powers vested under sub para (1) of para 5 as Section-v of the Indian Constitution for the period of two

01.03.2016/1645/जेएस/एजी/2

years with certain conditions. But subsequently again vide notification dated 23.07.2014 the notification dated 17.07.2014 was amended and the scope was limited only for the purpose of grant of natour land under Natour Rules, 1968.

That the Cabinet again approved amendment of notification dated 23.07.2014 to enlarge the scope of notification for even construction of roads and other developmental activities in Scheduled Areas. The case for amended notification approved by the Cabinet is pending for final assent by the Governor of Himachal Pradesh since last more than two months. Now only the assent of Governor is awaited. Henceforth, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम् राज्यपाल महोदय से यह आवेदन करना चाहता हूं कि यह फोरैस्ट क्लीयरैंस एक्ट के बारे में अभी हाल ही में हमारे माननीय वन मंत्री, श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, श्री जगत सिंह नेगी जी तथा मैं मिला था। उन्होंने यह फाईल अप्रूअल के लिए होम मिनिस्टरी को भेजी है, जो कि जल्दी से सेंक्शन हो करके वहां से आ जाएगी। मगर दो महीने बीत चुके हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस संविधान के मुताबिक ये जो पॉवर है, शक्ति है यह गवर्नर में निहित है। गवर्नर साहब को किसी और से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। He was wrongly advised to send it to Delhi. The Governor is competent by himself.

Shri Ravi Thakur: Henceforth, I request that कि इसको जल्दी कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं so that the people of tribal areas get relief on this issue.

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

01.03.2016/1650/SS-AS/1

श्री रवि ठाकुर क्रमागतः

दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमें पावर में बजट का प्रावधान है, बहुत ज्यादा हमारे ट्राईबल एरिया का बजट डाईवर्ट हो रहा है। उसमें कुछ कटौती करके हमारे बजट में इससे ज्यादा प्रावधान होगा। उससे हमारे इलाके ज्यादा विकसित होंगे। सन् 1960 के दशक में एम0पी0टी0सी0 हुआ करती थी, जिसमें पंजाब के समय में मेम्बर ट्राईबल एडवाइजरी कांउसिल होते थे। उसमें एक समय मेरे पिता जी भी रहे थे। क्योंकि उस समय लाहौल-स्पिति विधायक की कांस्टीचुऐंसी नहीं थी तो लेट श्री निहाल चंद ठाकुर जी वहां से चयनित होते थे और इलैक्टिड मेम्बर्ज़ की मीटिंग होती थी। जैसे आजकल ट्राईबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तो उनकी मीटिंग में यह निर्णय होता था। उनको कैबिनेट पावर मिलती थीं और वे निर्णय करते थे कि पूरे ट्राईबल एरिया को कैसे विकसित किया जाए। उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि मैंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर जो पूरा इलाका है, लाहौल-स्पिति किन्नौर से लेकर लद्दाख तक का है, ये सारा सैंसटिव जोन है। पीछे मैं आयोग के एक टूअर पर

लद्दाख गया हुआ था तो हमने वहां यह पाया कि वहां के जो लोकल कमांडेंट थे, वे कह रहे थे कि यहां से बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है। इसी तरह से लाहौल-स्पिति से भी और खास तौर से स्पिति से भी कुछ पलायन हुआ है। लद्दाख से भी पलायन हुआ है। इसको सही तरीके से विकसित करने के लिए भी एक कार्यक्रम बनाया जाए, ये मैं समझता हूं। इसमें जो एल0ओ0सी0 में डिवैल्पमैंट फोर्सिज़ हैं, अभी हमारे यहां ट्राईबल एरिया से और पूरे हिमाचल से कुल मिलाकर 41 माऊंट एवरैस्टर्ज़ हैं जोकि इंटरनेशनल फेम के हैं। अभी उनकी हाल ही में तीन दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। वे सैल्फलैसली कम्युनिटी को डिवैल्प करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि फर्स्ट ऐड है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमैंट के साथ मिल करके फ्री कोर्सिज़ देना चाहते हैं। वहां पर रेस्क्यू करना चाहते हैं। उन्होंने एक टीम बनाई हुई है। इस तरह से हमारे इलाकों को विकसित करने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील है। वे माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिले थे और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम पूरा उनका साथ देंगे। पीछे जो कारगिल में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा अधिक काम उस समय लद्दाख स्काऊट ने किया था। इस कारण लद्दाख स्काऊट को फौज ने मान्यता दी है। मेरा यह मानना है कि इस तरह से हमारे जो बॉर्डर एरिया में लोग हैं, जो पैरा-मिलिटरी फोर्सिज़ हैं

01.03.2016/1650/SS-AS/2

उसमें हमारे लोगों को अधिक-से-अधिक रिक्रूटमैंट दी जाए। उनके लिए अलग से सीटें रखी जाएं। पीछे किरण रिज्जू जी, जो होम मिनिस्टर साहब हैं, वे भी स्पिति में आए थे। उन्होंने भी यह कहा था कि इसमें हम लोग रियायत देंगे। जैसे हाइट पर हमारे एग्जाम होते हैं उसमें नम्बर्ज़ पर भी रियायत देंगे और इनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा सीटें रखी जायेंगी। क्योंकि सन ऑफ दी सॉयल जो वहां से जुड़े हुए हैं और पुश्त दर पुश्त वहां पर रह रहे हैं निश्चित रूप से उनके लंग्ज़ भी ज्यादा काम करते हैं और उस इलाके की ठंड को भी सह सकते हैं। उस इलाके को विकसित करने के लिए यह एक अच्छा तरीका है यह मेरा मानना है। मेरे परिवार से मेरे दो अंकल जैसे कि मैंने कहा कि लेट श्री निहाल चंद ठाकुर जी एम0पी0टी0सी0 में रहे हैं, उसी तरह से मेरे दो कर्नलज़ फौज में रहे हैं। उन दोनों ने महावीर चक्र लिया है। कर्नल पृथी चंद जी और लेट कर्नल कुशाल चंद

ठाकुर जी ने लद्दाख की लड़ाई में भाग लिया था। इस तरह से हमारे लोगों ने बहुत नाम बनाया है। पैरा-मिलिटरी फोर्सिज़ में हमारे लोग अधिक से अधिक जाएं। जो माऊंट एवरैस्टर्ज़ हैं ये भी हमारे इलाके में ज्यादा कार्य करें तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा होगा। यह मेरा मानना है। हमारे जो जनजातीय इलाके के लोग होते हैं उनके रीति-रिवाज, खान-पान, रहना, धर्म, पहनावा और नाज-गान थोड़ा अलग होता है। वे लोग ज्यादा शायर होते हैं। जैसे कि मैंने अभी दौरा किया था तो हमारे 12 करोड़ ट्राईबल्ज़ के जिन्हें हम नेता मानते हैं वे रांची से मिर्जा मुंडा हैं जोकि मार्टर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत की थी।

जारी श्रीमती के0एस0

01.03.2016/1655/केएस/एएस/1

श्री रवि ठाकुर जारी----

उनका जन्म 1875 में हुआ था और 1901 में जेल में उनकी मौत हो गई थी। अंग्रेजों ने उन्हें जेल दे दी थी और डूम्बारी जो रांची के पास एक पहाड़ है, उन्होंने अंग्रेजों की फौज के साथ लड़ाई छेड़ी थी और 400 अनुसूचित जनजातीयों की मुंडा कम्युनिटी के लोगों को अंग्रेजों ने घेरकर मारा था। तो जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं देश भर में उन्हें वे सूर्य पुत्र मानते हैं और भूमि का भगवान मानते हैं क्योंकि ज्यादातर जो अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं वे जंगलों में रहते हैं और माईनर प्रोड्यूस पर अपना निर्वाह करते हैं तो उसी तरह से जो हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ठक्कर बाबा जी जो कि अमृत लाल जी के नाम से भी जाने जाते हैं जिनका जन्म 1869 में हुआ था और 1951 में पूरे हुए थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कार्य किया है। मैं अनुसूचित जन जाति और जनजाति के लोगों की बात कर रहा हूं। आजकल पूरा देश

ही नहीं, पुरी दुनिया, प्रत्येक देश एक-दूसरे पर निर्भर है तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यहां के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या-क्या कार्य किए हैं और ठक्कर बाबा जी ने एक पूरी सोसायटी थी पूरे हिन्दुस्तान के अंदर जिसे कि सर्वेंट सोसायटी कहा जाता था, उसमें उन्होंने कार्य किया और उत्थान किया और महात्मा गांधी जी की अगुवाई में उन्होंने यह कार्य किया था, यह मैं इस माननीय सदन को बताना चाहूंगा।

01.03.2016/1655/केएस/एएस/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया अपने समय का ध्यान रखें और वाइंड अप करने की कोशिश करें।

श्री रवि ठाकुरः ठीक है, अध्यक्ष महोदय। मैं इन दो नेताओं का इसलिए यहां पर जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो असली रूट्स हैं वे कहां पर है और कहां से हमें ताकत मिली है, कहां से हमें पानी आया है और कहां से हमारे ऊपर छत्र छाया आई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पीछे पुणे का दौरा किया था । वहां महात्मा गांधी मैमोरियल में हम गए थे,-----(व्यवधान)---आप मुझे डिस्टर्ब न करें, मेरी बात सुनिए। जो टोपी मैंने पहनी है, इसे भी मैं वहीं से लाया हूं और मैं आपको एक गम्भीर बात बता रहा हूं, आज की तारीख में नेशनल इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है। आप ट्राईबल्ज़ का मज़ाक मत उड़ाइए। महात्मा गांधी जी को जब पूणे में नज़रबन्द किया गया और कस्तूरबा गांधी जी जब बीमार थीं, उनके अन्तिम दिनों में, वह महात्मा गांधी जी के लैफ्ट में लेटी हुई थीं, बहुत बीमार थीं तो अंग्रेज डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इन्हें पैंसिलिन का इंजैक्शन लगाया जाए अन्यथा ये नहीं बच सकती तो गांधी जी ने कहा कि नहीं हमारा नारा है कि किसी भी विदेशी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगें इसलिए हम यह इंजैक्शन नहीं लगाएंगें। गांधी जी ने अपनी जान की आहूति ही नहीं दी बल्कि अपनी पत्नी की जान की आहूति भी दी । तो मैं यह आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि

उन्होंने अपनी पत्नी को पैंसिलिन का इंजैक्शन नहीं लगवाने दिया और वह पूरी हो गई उसके बाद उनका स्मारक वहां बना। तो मैं जब वहां पर गया था तो

01.03.2016/1655/केएस/एएस/3

अनुसूचित जनजाति के लोगों ने मुझे वहां पर इस टोपी से सम्मानित किया । जो वहां का ट्राईबल का एन.जी.ओ. था उन्होंने मुझे सम्मानित किया । इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

अध्यक्षः अभी दो माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं । यदि माननीय सदन की अनुमति हो तो इस सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है। कृपया 10 मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

1.3.2016/1700/av/dc/1

श्री हंस राज : अध्यक्ष महोदय, जब भी हमारी बोलने की बारी आती है तो आप समय का ज्यादा ध्यान देते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से जो माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण पढ़वाया गया, उस पर हम भी बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

हम दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा या किसी अन्य राज्य में नहीं जायेंगे। हम बड़ी देर से सबको सुन ही रहे हैं। अब दिमाग भी गड़बड़ा गया है कि क्या बोलें। बोलने को तो कुछ नहीं है मगर शुरुआत में जो कहा गया है। जैसे जगजीवन पाल जी एक पत्र के माध्यम से हमें बता रहे थे कि ओ0बी0सी0, एस0सी0/एस0
टी0 के साथ आप दो लोग बोलकर कुछ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय तो सरकार ने किया हुआ है और उसी का प्रतिफल; मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र में जाऊंगा। यहां गृह आवास का बड़ा जिक्र हुआ, अन्त्योदय का बहुत जिक्र हुआ। यहां पर एस0सी0/एस0टी0 तथा ओ0बी0सी0 के लिए जितनी भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली हुई हैं उन पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। मगर आजकल जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की मीटिंग होती है उसमें स्थानीय विधायक को बुलाया ही नहीं जाता है जबकि वह मैम्बर होता है। एस0सी0/एस0टी0 के विषय में एक एस0सी0 केटेगरी का व्यक्ति जो इस मान्य हाउस में है, हम जो रिजर्वेशन लेकर आये हुए हैं और इस मान्य सदन में एक तरह से एस0सी0 कम्युनिटी को रिप्रेजैंट कर रहे हैं। हम से ही नहीं पूछा जाता तो आप इस सरकार की दशा और दिशा का समझ सकते हैं कि वह किस तरह का न्याय एस0सी0/एस0टी0 तथा ओ0बी0सी0 के साथ कर रही है, यह बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है।

01.03.2016/1700/av/dc/2

शिक्षा के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने नियम 130 के तहत मान्य सदन से चर्चा मांगी है। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी सरकार ने बड़ी वाहवाही लूटी है कि हमने इतने कॉलेज, सीनियर सैकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल खोल दिए। मगर चुराह के दो-तीन स्कूलों का उदाहरण देकर मैं आपको थोड़ा चेताना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी इससे बिल्कुल आश्वस्त होंगे क्योंकि इनको पता है कि वहां की तस्वीर पिछले तीन सालों में बिल्कुल बदली हुई है। वह इस तरह से बदली है कि वहां पर इन तीन सालों में इतना विकास हुआ है कि एक-एक स्कूल में सौ-सौ बच्चे हैं और टीचर्स डैपुटेशन पर हैं। स्कूलों के नाम पर इस तरह का विकास चला हुआ है। 47 पंचायतों को सिविल अस्पताल तीसा फीड करता है। मेरा तीन सालों में बोलते-

बोलते गला सूख गया कि आप इसको एफ0आर0यू0 करो या कोई चाइल्ड स्पैशलिस्ट, गायनोकोलोजिस्ट; कोई तो स्पैशलिस्ट भेजो। यदि किसी गर्भवती महिला को दर्द होता है तो उसको सौ किलोमीटर की दूरी तय करके चम्बा अस्पताल आना पड़ता है। आपने इन तीन वर्षों में इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी हुई है। 47 पंचायतें एक माइने रखती है। हमारे कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि दस किलोमीटर की दूरी पर फलां पी0एच0सी0 काम नहीं कर रही है, पांच किलोमीटर पर फलां पी0एच0सी0 काम नहीं कर रही है। मैं तो यहां पर यह सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं। 47 पंचायतें और सौ किलोमीटर; आज की डेट में इतनी शर्मनाक परिस्थितियां चली हुई है। माननीय राज्यपाल महोदय से जितनी भी स्पीच पढ़वाई गई है उसमें कम-से-कम थोड़ा सा जिक्र भी सही तरीके से हुआ होता तो माननीय जगजीवन पाल जी, हम उसका भरपूर समर्थन करते। सड़कों के लिहाज से चुराह विधान सभा क्षेत्र में स्टेट हाई-वे 1992 से घोषित है। मगर उस स्टेट हाई-वे का हाल तो देखो। वहां हर महीने कोई-न-कोई गाड़ी लुढ़कती ही है और उसमें दो-तीन लोग बेचारे स्वर्गावास हो ही जाते हैं।

श्री टीसी द्वारा जारी

01.03.2016/1705/TCV/DC /1

श्री हंस राज ---- जारी

इस पर भी हम आज तक चिंतन मंथन नहीं कर पाये। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें लगता है कि हम लोग संपूर्ण विकास की ओर जा रहे हैं। यदि यह सम्पूर्ण विकास है तो विकास को हमें एक अलग तरीके से परिभाषित करना पड़ेगा। विकास की परिभाषा को हमें यहां अलग से इन्टरप्रिएट करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, चुराह विधान सभा क्षेत्र हर लिहाज़ से पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत सालों से राजनैतिक उदासीनता रही है। जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है, तब और उदासीनता से उस चुराह विधान सभा क्षेत्र को देखा गया है। हाईड्रोपॉवर में हमें पॉटेंशियल लगता है और हाईड्रोपॉवर के बहुत से

पॉवर प्रोजैक्ट भी स्वीकृत हुए हैं। पिछले दिनों जब हम एम0एल0ए0 प्रायोरिटी के दिन मिले थे, तो माननीय मुख्य मंत्री जी से हमने अनुरोध किया था कि हाईड्रोपॉवर में लोग इनवेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों में कोई नया हाईड्रोपॉवर प्रोजैक्ट वहां पर नहीं लगा है। ये हालात हमारे हाईड्रोपॉवर के रिगार्डिंग है। जिससे हमें थोड़ा सा यह लगता था कि सी0एस0आर0 में पैसा आता, लाडा में पैसा आता और उससे थोड़ा सा विकास होता। साथ ही जिन लोगों की ज़मीने जाती, उनको कंपनसैशन मिलता, रोजगार मिलता, क्योंकि रोजगार का कोई और तरीका वहां पर नहीं है। सीमेंट प्लांट की आस हम वहां जमानों से लिए बैठें हैं। शिकरीधार का सीमेंट प्लांट एक टाईम में स्वीकृत हुआ था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता पर काबिज़ हुई, इन्होंने आते ही सबसे पहले वही स्वीकृति रिजेक्ट की । सीमेंट के लिहाज़ से चुराह में इतना पॉटेंशियल है, जिन्होंने सर्वे किया हुआ है, वे बताते हैं कि पूरे 100 वर्षों के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश लोगों को वहां रोज़गार पैदा हो सकता है। इस संदर्भ में भी कोई जिक्र नहीं है। इस तरह का अभिभाषण यहां पर माननीय राज्यपाल महोदय से दिलवाया गया। इस तरह से बहुत ही शर्मनाक परिस्थितियां बनी हुई है। आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियां बड़ी भारी खुली है। कई जर-जर हो गई है। न वहां पर कोई फोर्थ क्लास के इम्पलाईज़ है, न कोई फार्मासिस्ट है और न ही

01.03.2016/1705/TCV/DC /2

किसी तरह की कोई सुविधा है। ये मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं । दो-तीन का जिक्र भी कर देते हैं। आयुर्वेदिक संस्थान, बौदेड़ी है, उसका बहुत बुरा हाल है। इसके अतिरिक्त जो पी0एच0सी बैरागढ व देवीकोठी और भी कई पी0एच0सीज़ हैं, सबकी सब खाली पड़ी है। हमारा चुनाव क्षेत्र सीमांत क्षेत्र है, टैरेरिस्ट एक्टिविटिज़ भी हुई है। 1998 में सतरूंडी कांड के नाम से एक कांड हुआ था। वहां पर 35 लोग मारे गये थे और 7-8 लोगों को वह साथ लेकर गये थे। उसके बाद एस0पी0ओज को अप्वाईंट किया गया था। एस0पी0ओज़ का मुद्दा ऐसा हो गया है कि इन लोगों को 15-17 साल हो गये हैं।

लेकिन आज भी वही 4000/- रूपये इनको मिल रहे हैं। आप इमेजन कीजिए जिनके 2-2 या 3-3 बच्चे हैं, उनका पूरा परिवार उसी पर निर्भर करता है, उनका गुजारा कैसे होता होगा? उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए भेदभाव हो रहा है, क्योंकि अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट में एस0पी0ओज नहीं हैं। यदि किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में एस0पी0ओज होते, शिमला में होते, तो उनके लिए भी जरूरी कोई पॉलिसी बनती, जैसा बी0आर0जी0एफ0 के कर्मचारियों के साथ हुआ है। सिरमौर और चम्बा में बी0आर0जी0एफ0 स्कीमज़ शुरू हुई। लेकिन सिरमौर और चम्बा दोनों बैकवॉर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वरना उनको भी मर्ज़ किया जा सकता है, जिस तरह से बड़े कर्मचारियों को मर्ज़ किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले इतिहास में हुआ है यदि आप पीछे की विधान सभाओं को देखें

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ------

01.03.2016/1710/RKS/AG/1

श्री हंस राज चुराह....जारी

या सरकारों को देखें तो उसमें यह हुआ है। कई कर्मचारियों को कई अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया है। जो लोग बी.आर.जी.एफ. स्कीम के बंद होने की वजह से बाहर हुए हैं और दूसरे जो एस.पी.ओज हैं जिनके परिवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उन पर गहन मंथन होना चाहिए। इस बात को आपको जहां ले जाने की जरूरत है, वहां ले जाइए। एग्रीक्लचर, होर्टीकल्चर, विशेषकर होर्टीकल्चर, फ्लोरिक्लचर में बहुत बड़ा पोटेंशियल चुराह में है। वहां पर

बहुत से पोलीहाउसिज लगे थे। फूल दिल्ली व अन्य प्रदेशों में जा रहा था। लेकिन जब से यह सरकार बनी हैं तब से कोई नया पॉलीहाऊस नहीं लगा। जो लगे थे वे भी बंद हो गए हैं। ऐसे में जो इनकम का अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए वह भी जनरेट नहीं हो पाया है। एग्रीकल्चर में भी इस तरह के हालात हैं। मैं यहां पर राज्यापाल के अभिभाषण पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्योंकि अभी अन्य सदस्यों ने भी बोलना है। मैं चंद लाइनों में कहना चाहूंगा '**हर तरफ ही शोर सा है, मतलब हर तरफ शोर है कि बड़ा विकास हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विकास कहां हुआ। आज उदासीन हो गया हूं इस विकास से, अब तो नफरत सी हो गई है इस विकास के नाम से।**' धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने समय दिया।

अध्यक्षः श्री किशोरी लाल जी।

01.03.2016/1710/RKS/AG/2

श्री किशोरी लालः आदरणीय अध्यक्ष जी, 25 फरवरी, 2016 को महामहिम राज्यपाल जी ने जो विधान सभा में अभिभाषण दिया है। जिसका समर्थन आदरणीय जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव जी ने धन्यवाद के रूप में प्रस्तुत किया तथा जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य श्री अजय महाजन जी ने किया। उस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं भी खड़ा हूं। हाल ही में प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। छिट-पुट घटनाओं को छोड़कर पूरे प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव नतीजों में कांग्रेस विचारधारा के लोग ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद् में चुनकर आए हैं । विपक्ष के लोग गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं कि ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह पूर्णतयः निराधार है। ग्राम पंचायतों को सरकार पूरी शक्तियां देगी। ऐसा कोई भ्रम पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जिनकी कृपा से इन 3 वर्षों में पूरे प्रदेश में एक समान विकास हुआ है। जो यह पुस्तक प्रिंट हुई है वह तथ्यों के आधार पर है। इसमें

कुछ भी गलत प्रिंट नहीं हुआ है। इसको आप आराम से पढ़ें तब आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है? मेरे एक एस. सी. साथी जो पहले यहां यह बोलकर गए कि एस.सी. के लिए कुछ नहीं किया । मैं भी एस.सी. से संबंध रखता हूं। उनको मैं कहता हूं जिनके पास मिर्च उगाले के लिए जमीन नहीं थी, घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, उन्हें यह जमीन किस सरकार ने दी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीब लोगों को 10-10 कनाल जमीन मुहैया करवाई है। भूमि के मंजारों को मालिक बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाई, छूआछूत को बंद किया। यह सब कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही हुआ। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से सुरक्षा पैंशन 450 रुपये से 600 रुपये हुई। 80 साल से ऊपर के वृद्धों के लिए पेंशन राशि को 1100 रुपया किया गया। यह सब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने किया।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

01.03.2016/1715//SLS-AG-1

श्री किशोरी लाल ...जारी

आप लोग भूल क्यों जाते हैं? जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो पैंशन होल्डर पैंशन लेते थे और जब किसी ने पैंशन के लिए अप्लाई किया होता था, तब जब पहले वाला मर जाता था तो दूसरे को पैंशन मिलती थी। क्या आप इस बात को भूल गए? आप उस बात को भी याद करिए। अब सबको पैंशन मिलेगी। ...(व्यवधान)... मेरे चुनाव क्षेत्र में 3 सालों में 1800 लोगों को पैंशन लगी है। वह कहां से लगी? बजट का प्रावधान यहां पर आदरणीय मुख्य मंत्री जी करते हैं, तभी लोगों को वह पैंशन मिल रही है। पटवारी लोग इनकम लिखने में ज़रूर थोड़ी-बहुत आनाकानी करते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो तहसीलदार हैं उनको आदेश दिए जाएं कि उन पटवारियों पर अंकुश लगे जो जानबूझकर इनकम ज्यादा लिखते हैं। यह

प्रावधान भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी से करवाएंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है।

जो हमारे मकान बनते थे उनके लिए 48,500 से 75000 रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है। अब लोगों के मकान बन रहे हैं। 25000 रुपये का अनुदान मुरम्मत के लिए दिया जा रहा है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के सभी वर्गों की प्रगति, समृद्धि और बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्तियां दी जा रही है। सरकार ने 'बेटी है अनमोल योजना' के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये और 450 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति बच्चा की है। हमारी सरकार स्वातंत्रता सेनानियों के पुत्रियों तथा पौत्रियों के विवाह पर 51000 और 21000 रुपये प्रदान कर रही है। यह सभी आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच और लंबे तजुर्बे का फल है जिसका प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश में महात्मा गांधी वर्दी योजना पर 62 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। छात्र बसों में मुफ्त यात्रा करते हैं, वह भी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है।

01.03.2016/1715//SLS-AG-2

यहां पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बात भी आई। सरकार ने काफी हद तक डॉक्टरों की भर्ती की है और प्रदेश सरकार ने हर पी.एच.सी. में एक चिकित्सक नियुक्त करने का फ़ैसला लिया है जिसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के जितने भी पी.एच.सी. हैं वहां एक चिकित्सक नियुक्त होने से लोगों को फायदा होगा। इसी तरह जो पैरा मैडिकल स्टॉफ है, उसकी भी भर्तियां हो रही हैं और जब यह भर्तियां होंगी तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी और लोगों को फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार नाहन, चम्बा और हमीरपुर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने जा रही है

जो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए पोलीहाऊसिज पर 85 प्रतिशत् अनुदान, बीजों पर 50 प्रतिशत् अनुदान, पॉवर टिल्लर और चारा काटने की मशीनों पर 50 प्रतिशत् अनुदान और केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित करने पर 50 प्रतिशत् अनुदान दे रही है। किसानों के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। किसानों द्वारा सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं तथा उनकी फसल को मंडियों में बेचने के लिए मंडियों की व्यवस्था भी की है। किसानों के ठहरने के लिए मंडियों के पास किसान भवनों का निर्माण करवाया गया है। प्रदेश के किसान अगर किसी वजह से खेती-बाड़ी छोड़ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है।

जारी...गर्ग जी

01/03/2016/1720/RG/AS/1

श्री किशोरी लाल-----क्रमागत

प्रदेश में जो खाद्यान सरकार उपदान पर दे रही है, 200/-रुपये के राशन से परिवार का गुजारा हो रहा है इसलिए लोग खेतीबाड़ी छोड़ रहे हैं। बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है कि किसान किसी अन्य कारण से पीछे हट रहे हैं। क्योंकि उनका सस्ता राशन बन जाता है और 150-200 रुपये में महीने का राशन आ जाता है। इसलिए खेती से कुछ लोगों का मन हटा है।

अध्यक्ष महोदय, पशु-पालकों के लिए सरकार ने गांव-गांव में पशु औषधालय, चिकित्सालय संस्थान खोले हैं। वहां मुफ्त टीकाकरण तथा दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बेसहारा पशुओं के लिए सरकार गौसदन बनाने जा रही है। मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन गौसदन सरकार ने बनाकर तैयार किए हैं। वहां बेसहारा पशुओं को रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह पूरे प्रदेश में सरकार गौसदन खोलेगी तथा गौंवंश के बोर्ड का गठन भी सरकार ने किया है। दस करोड़ रुपये का प्रावधान भी इसमें सरकार

ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सड़कों की जो खस्ता हालत तीन वर्ष पहले थी उसमें काफी सुधार किया है। प्रदेश में दो नई फोरलेन सड़कें मंजूर हुई हैं जिनका काम जोरों पर है। प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों, मार्गों और पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड को 543.43 करोड़ रुपये की परियोजनाएं रिपोर्ट भेजी गई थीं तथा नाबार्ड से 92 सड़कें और 15 पुल मंजूर हुए हैं जिनका काम शुरू है। सरकार ने राष्ट्रीय मार्गों के रख-रखाव के लिए 106 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। प्रदेश में 93 अतिरिक्त सड़क परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और प्रदेश में जहां-जहां पीने-के-पानी की कमी थी वहां हैण्ड पम्प्ज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदान कर रहा है तथा प्रदेश में काफी बसें नई आई हैं। इससे प्रदेश की जनता को फायदा हुआ है। प्रदेश ने 25 इलैक्ट्रिक बसें आरम्भ करने का सरकार का फैसला सराहनीय है। प्रदेश में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2007 में सस्ता राशन देकर लोगों को राहत दी है। जो पी.डी.एस. की दुकानें हैं उनके

01/03/2016/1720/RG/AS/2

माध्यम से आटा, चावल, दाल, तेल, नमक आदि चीजें मुहैया करवाकर महंगाई से राहत प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बजट में कटौती करके कई जो स्कीमें थीं उनमें धन के अभाव के कारण वे स्कीमें प्रभावित हुई हैं। चुनाव से पहले जब केन्द्र में आज जो सत्तासीन सरकार है उन्होंने क्या नारा दिया था कि विदेशों से कालाधन लाएंगे, प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा करवाएंगे। परन्तु प्रत्येक भारतीय के खाते में कौन सा पैसा आया? यह हमारे विपक्ष के लोग बताएं।

महंगाई से हा-हाकार मची हुई है। 220/-रुपये अरहर की दाल, 160/-रुपये मास की दाल, तो कौन सी महंगाई कम हुई? यह भी विपक्ष के लोग बताएं। हिमाचल प्रदेश में रेल बजट के लिए जो झुनझुना प्रदेश को थमाया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे जो वहां नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वे कहते थे कि लेह-लद्याख तक रेलगाड़ियां पहुंचाएंगे। लेकिन जोगिन्द्रनगर से पठानकोट की गाड़िया अब शुरू हुई हैं काफी दिनों के बाद। लोग त्रहि-त्राहि कर रहे थे। तो आप रेल की बात करते हैं और अच्छे दिनों की बात करने वाली सरकार अब बताए कि वे अच्छे दिन कब आएंगे?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से बैजनाथ विधान सभा चुनाव क्षेत्र में कई स्कूल अपग्रेड हुए, सबमें अध्यापक हैं, स्कूल के कमरे बने हैं और कक्षाएं शुरू हुई हैं। बैजनाथ का 1962 का कॉलेज था पं. संतराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहां एम.ए. इंगलिश की कक्षाएं और अर्थशास्त्र की कक्षाएं इस सत्र से शुरू होंगी। चढ़िहार में सब-तहसील,

एम.एस. द्वारा जारी

01/03/2016/1725/MS/AG/1

श्री किशोरी लाल जारी--------

चढ़ियार में सब-तहसील, चढ़ियार में पुलिस चौकी, मुल्खान में पुलिस चौकी, बैजनाथ में अग्निशमन चौकी तथा बैजनाथ पपरोला को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। 19 जनवरी, 2016 को आदरणीय मुख्य मंत्री जी जब बैजनाथ के दौरे पर गए तो देओल में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइन्दे रहे, वहां पर आज तक पी0एच0सी0 नहीं खोल सके। वहां पर देओल में पी0एच0सी0 नहीं है इसलिए लोगों को इंजैक्शन लगवाने

के लिए बैजनाथ आना पड़ता है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने देओल में भी पी0एच0सी0 खोलने की घोषणा की है और शीघ्र ही वहां पी0एच0सी0 खोली जाएगी। इसी तरह से बैजनाथ के अस्पताल को भी 50 से 60 बिस्तरों वाला किया है। धूमल साहब की सरकार के वक्त बैजनाथ से सारे डॉक्टर बदल दिए थे। डी0एस0पी0 का कार्यालय दाड़लाघाट विद पोस्ट कर दिया था। स्वाइल कन्जरवेशन का एस0डी0ओ0 का दफ्तर बन्द कर दिया था। गत्ता फैक्टरी बन्द कर दी थी। क्या मेरे मित्रों को वे दिन भूल गए कि वह सबकुछ लुटा दिया जो कांग्रेस सरकार ने वहां पर मुहैया करवाया था। आज राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से बैजनाथ में सारे डॉक्टर्ज हैं। इसके अलावा डॉक्टर्ज के आवास के लिए भी 30 लाख रुपया सरकार ने मुहैया करवाया है। पीने-के-पानी की समस्या हल करने के लिए धरेड़ और सेल के लिए छिब्बरनाला से स्कीम शुरू की है। -(घण्टी)- इसी तरह से सेल के साथ-साथ संसाल-पंजाला-भटूगांवों को भी थाथी से पेयजल योजनाएं शुरू की हैं जिसका हाल ही में आदरणीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया है और इनकी वजह से हमें 25 लाख रुपया कूहलों के लिए मिला है। यहां पर पिछली सरकार में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रहे श्री रवि जी बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके समय में वर्ष 2011 में वहां सभी कूहलों की शिलान्यास पट्टिकाएं लगी हुई हैं कि इस कूहल के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपये, उस कूहल के लिए इतने पैसे इत्यादि। इस तरह से लाखों रुपये लगे हैं लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा। हाल ही में 20 लाख रुपये की लागत से मुरम्मत करवाकर पानी खेतों में पहुंचाया जा रहा है। यह उस वक्त की सरकार की हालत थी। आप लोग अपनी बातें भूल जाते हैं। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

01/03/2016/1725/MS/AG/2

श्री किशोरी लालः मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के लिए करोड़ों रुपये आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार खर्च रही है और सारी सड़कें बनाई जा रही हैं। इसी तरह वहां पर सड़कें, पुल और नेशनल हाइवे की जो सड़कें हैं उनको भी बढ़िया ढंग से बनाया गया है। पहले की जो सरकार यहां रहकर गई है अगर मैं बाजार की बात करूं

तो जो खड्डे वहां सड़कों में थे, दुकानदार उनमें पत्थर रखते थे कि कहीं छींटे न लग जाएं लेकिन आज वे सड़कें बनी हैं और उसका श्रेय माननीय वीरभद्र सिंह जी को जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूं राजा वीरभद्र सिंह जी को कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं और आगे भी होंगे। अगले दो वर्षों में आगे देखिए होता है क्या, सब-कुछ आपके सामने आएगा और फिर राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। मैं अधिक न कहता हुआ सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक बुधवार दिनांक 02 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांकः 01 मार्च, 2016 **सचिव।**